चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

13 जनवरी –19 जनवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

अरविंद केजरीवाल राजनीति की नई उम्मीद हैं

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

अरविंद केजरीवाल ने कई राजनीतिक मान्यताओं को बदला है. हालांकि, उन्होंने कोई नई रणनीति नहीं बनाई. कांग्रेस और भाजपा के प्रति मतदाताओं के गुस्से को ही अपना हथियार बनाया, लेकिन अब वे बदलाव के ट्रेंड सेटर के तौर पर उभर रहे हैं. ज़ाहिर है कि अब उनकी निगाहें लोकसभा चुनाव की ओर हैं, जिसके लिए उन्हें कई नई पहल करनी होंगी. नीतियों के माध्यम से समस्याओं का हल खोजना होगा, अन्ना हजारे को साथ लेना होगा और देश के भीतर जगी नई राजनीतिक उम्मीद को क़ायम रखना होगा.

संतोष भारतीय

अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास का मत जीत लिया. और विश्वास का मत भी इस अंदाज़ में जीता कि कांग्रेस के सामने समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी टुकुर-टुकुर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठते हुए असहाय सी देखती रही. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया था कि कांग्रेस की नीतियों के ख़िलाफ़ देश में गुस्सा है, नरेंद्र मोदी का साथ है, पंद्रह साल का उनका वनवास है, जो 2013 में ख़त्म हो जाएगा और डॉ. हर्षवर्धन दिल्ली के नये मुख्यमंत्री बनेंगे. भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा अतिउत्साह, अतिआत्मविश्वास में थी कि उसने प्रचार में सभी नेताओं को नियोजित ढंग से लगाया ही नहीं. उनका आत्मविश्वास तो सिर्फ़ कांग्रेस के ख़िलाफ़ रोष और नरेंद्र मोदी की सभाओं में उपजी भीड़ को लेकर हद से ज्यादा बढ़ गया था. अपने इसी चश्मे की वजह से वो दिल्ली के लोगों का गुस्सा नहीं देख पाए, जो जितना कांग्रेस के प्रति था, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी था. लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं किया. न उसने दिल्ली में किया, न उसने केंद्र में बैठी सरकार के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर किया. सड़कों पर तो भारतीय जनता पार्टी रस्मी तौर पर ही दिखाई दी. उसने कहीं पर भी कांग्रेस की नीतियों का विरोध ही नहीं किया. वो नीतियों का विरोध कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि आर्थिक नीतियां उसकी और कांग्रेस की समान हैं. भाजपा की शिकायत सिर्फ़ इतनी है, जो नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में कहते हैं कि कांग्रेस ने खुली उदारवादी आर्थिक नीतियों को ठीक से लागू नहीं किया, उसे वे ठीक से लागू करेंगे.

अगर लोगों को ये पता होता कि अरविंद केजरीवाल को इतनी सीटें मिलेंगी तो ये निश्चित था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सीटें मिलतीं. अगर अन्ना हजारे उनके समर्थन में दिल्ली में प्रचार कर देते, तो भी अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता. लेकिन अरविंद केजरीवाल का दुर्भाग्य यह था कि उनका हृदय से साथ देने वाले लोग भी उन्हें 12 से 14 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे. पूरा मीडिया इस मामले में असफल साबित हो गया. सारे शाख़कार असफल साबित हो गए. कांग्रेस और भाजपा के रणनीतिकार इस मसले में मात खा गए. मात तो वैसे अरविंद केजरीवाल के साथियों ने भी खाई. जब योगेंद्र यादव ने दिल्ली में सर्वे कराया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को 47 सीटें दीं. ये 47 सीटें अरविंद केजरीवाल के प्रचार का हथियार बनीं. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने हर उस चीज़ का प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, जिसका वे कर सकते थे. उन्होंने योगेंद्र यादव की साख़ का, उनके इन्स्टीट्यूट का भरपूर इस्तेमाल किया, बिना ये बताए कि योगेंद्र यादव उनकी ही पार्टी के नेता हैं. जो लोग योगेंद्र यादव को विभिन्न टीवी चैनलों में चुनाव का विश्लेषण करते हुए देखते थे, उन्होंने योगेंद्र यादव की उसी छवि को ध्यान रखा. इसीलिए जितना मीडिया असफल हुआ, जिसने अधिकांश संख्या 12 से 14 बताईं, वहीं मेरा मानना है कि योगेंद्र यादव भी फेल हुए, जिन्होंने 47 सीटें बताईं, लेकिन आईं 28.

पर ये 28 सीटें आना महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण है दिल्ली का वो गुस्सा, दिल्ली के लोगों की वो तकलीफ़, जो उन्हें पिछले साठ सालों से झेलने को मिल रही है. उनकी सुनवाई न कांग्रेस में होती थी, न भारतीय जनता पार्टी में होती थी. ऐसे दल जो दिल्ली विधानसभा में दो या तीन सीटें लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, उनके ख़िलाफ़ भी लोगों का गुस्सा था. इसीलिए मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के चुनाव में प्रतिशत के तौर पर भी साफ़ हुई और संख्या के तौर पर तो बिल्कुल साफ़ हो गई. दरअसल, कांग्रेस का सारा का सारा आधार खिसक कर आम आदमी पार्टी के साथ चला गया. दिल्ली में यह पहली बार हुआ कि झुग्गी-झोपड़ियों में लोगों ने पैसे नहीं लिए, झुग्गी-झोपड़ियों में शराब कम बंटी. आम तौर पर ये माना जाता रहा है कि झुग्गी-झोपड़ियां और अनधिकृत कॉलोनियां कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड हैं, जहां पर एक रात या दो रात पहले शराब बंटती है, पैसा बंटता है और वोट कांग्रेस के पास आ जाता है. इस बार ऐसा नहीं हुआ. इस बार लोगों ने अपने आप अरविंद केजरीवाल को अपने यहां मीटिंग करने को बुलाया. लोगों ने अपने आप अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया. उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तंत्र के ख़िलाफ़ उपजे अपने गुस्से का हथियार बना लिया. ये हथियार लोगों का हथियार था, जिसका चुनाव में उन्होंने इस्तेमाल किया. इसके बाद की कहानी तो और मज़ेदार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लोगों के गुस्से का प्रतीक बन रहे हैं, इस बात का पता न मीडिया को चला और न चुनाव विश्लेषकों को चला और न चुनाव पूर्व सर्वे करने वालों को चला. इससे एक चीज़ साफ होती है कि सारे विश्लेषण, सारे सर्वे ढाक के तीन पात हैं. ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं. यही हालत सीटों की राजस्थान में रही. किसी ने वसुंधरा राजे की इतनी सीटें आने की कल्पना नहीं की थी. हालांकि, अशोक गहलोत की वजह से वसुंधरा राजे सत्ता में आएंगी, ये तो उन्होंने मान

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अरविंद केजरीवाल को यह भी साफ़ करना है कि क्या बाज़ार आधारित आर्थिक नीतियां चलेंगी? किसान की फ़सल और उसकी ज़मीन का क्या होगा? जल, जंगल, ज़मीन का निजीकरण हो रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल उसे रोकेंगे? या उसका साथ देंगे. देश की नदियां विदेशी कंपनियों को बेची जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे? ये सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव सिर पर है.

दिल्ली को कैसे मिलेगा मुफ़्त पानी 04

यह कोई करिश्मा नहीं है 05

जनआकांक्षाओं पर फिरा पानी एकला चलेंगे वाम 07

साई की महिमा 12

अरविंद केजरीवाल राजनीति की नई उम्मीद हैं

पृष्ठ एक का शेष

लिया था, लेकिन इतनी सीटों के साथ आएंगी, यह किसी ने नहीं माना था. अरविंद केजरीवाल ने पूरा प्रचार बिल्कुल उस तरह किया, जिस तरह छात्र आंदोलनों में होता है. उन्होंने वैसे ही नवजवानों को उद्वेलित किया. उन्होंने वैसे ही कार्यकर्ताओं को देश भर से बुलाया. बहुत सारे कार्यकर्ता तो देश भर से अपने आप आए. वो यहां पर आकर परेशानी में भी रहे. कुछ अच्छी तरह भी रहे. लेकिन काम सबने बराबर किया. और दिल्ली में हर जगह आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया वो एक ऐसी अदभुद घटना थी, जिसे लोग भूल चुके थे. नब्बे के दशक से पहले इसी तरह से प्रचार होता था. राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ता थे. लेकिन इस बार राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ता नहीं रहे. राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने पैसा देकर दो हज़ार दिहाड़ी पर लोगों को अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए आरक्षित कर लिया है. दरअसल, वो ये समझ नहीं पाए कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नवजवान क्यों प्रचार करने को उतर गया है? उनके पक्ष में क्यों विदेश से लोग प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? ये कोई समझ नहीं पाया. हम भी समझ नहीं पाए. हम अरविंद केजरीवाल को अतिउत्साही चुनावी योद्धा के रूप में देखते रहे. लेकिन अरविंद केजरीवाल का वह अति उत्साह दिल्ली की जनता को ये भरोसा दे गया कि यही शख़्स है जो उनके ग़ुस्से का हथियार बन सकता है. अरविंद केजरीवाल ने पारंपरिक राजनीति नहीं की. अपारंपरिक राजनीति की, उन्होंने सीधी राजनीति की. जिसमें कांग्रेस और भाजपा या पत्रकार, मीडिया, चुनाव विश्लेषक उनकी रणनीति समझते रहे. अरविंद केजरीवाल ने कोई रणनीति नहीं बनाई. उन्होंने सिर्फ़ एक काम किया. लोगों के बीच जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रति अपने सख़्त रवैये को लेकर ये विश्वास दिला दिया कि वो कांग्रेस और भाजपा के साथ समझौता नहीं करेंगे और यही दिल्ली के लोगों के दिल को जीत गया. अब जब विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की जीत हो गई है और उन्होंने कांग्रेस के प्रति ज़रा भी नर्म रवैया अपनाए बिना, जिस तरह से विधानसभा में अपना भाषण दिया, वो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी के लिए समझौता नहीं किया.

हालांकि, दिल्ली के गलियारों में एक ख़बर गर्म है कि लोदी कॉलोनी के अमन होटल में राहुल गांधी जिम जाते हैं. राहुल गांधी से शीला दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगर समर्थन दिया तो ये कांग्रेस के हित में होगा, वर्ना भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के विधायकों को इस्तीफ़ा दिला देगी या कांग्रेस के विधायकों को ख़रीद लेगी. चूंकि, आठ ही कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं, हो सकता है कि इनमें पांच लोग बीजेपी की तरफ चले जाएं. क्योंकि कोई भी चुनाव नहीं चाहता. इसलिए उन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए. राहुल गांधी को शीला दीक्षित ने लगातार दो दिन जब ये समझाया तो राहुल गांधी के दिमाग़ में ये आ गया कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए. उसी जिम में उनकी मुलाक़ात कुछ लोगों से हुई, जिन लोगों को राहुल गांधी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए. हालांकि, कांग्रेस में लोग यह मानते हैं कि अब कांग्रेस अगले दस सालों तक दिल्ली की राजनीति से ग़ायब हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा लोगों का एजेंडा है. कांग्रेस और भाजपा इस एजेंडे पर कभी नहीं चलतीं. लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल के क़दम भा गए तो अगले चुनाव में, चाहे वह छह महीने में हों या साल भर में हों, अरविंद केजरीवाल एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में आएंगे. इसलिए कांग्रेस में बहुत सारे लोगों का कहना है शीला दीक्षित और राहुल गांधी ने मिलकर दिल्ली की कांग्रेस को साइनाइड खिला दिया है. इतना ही नहीं, उन लोगों का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर ये संकेत दे दिया है कि वह अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अप्रसांगिक होने के लिए तैयार है और उसका सारा आधार अरविंद केजरीवाल के साथ अगर चला जाए तो उन्हें कोई चिंता नहीं होगी.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

दरअसल, बीजेपी और कांग्रेस अरविंद के राजनीति के इस प्रयोग को समझ ही नहीं पाईं. क्योंकि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में किया गया प्रयोग सोचा समझा, योजना बनाकर किया गया प्रयोग नहीं था और टेढ़ा–मेढ़ा प्रयोग भी नहीं था, इसीलिए हर चीज़ में रहस्य देखने वाले लोग अरविंद केजरीवाल के इस क़दम को नहीं समझ पाए. लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस प्रयोग का असर कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों में दिखना शुरू हो गया है. महाराष्ट्र में बिजली की दरें कम हों, इसके लिए सरकार चिंतित हो गई और संजय निरूपम ने एक चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया. वहीं हरियाणा सरकार ने बिजली के दाम कम कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को 12 घंटे बिजली देने का वायदा कर दिया है. वसुंधरा राजे ने सामान्य रहन–सहन और गाड़ियों के क़ाफ़िले की संख्या को घटाने का फ़ैसला लिया है. और भी राज्य हैं जो दिल्ली के लोगों को देश की नब्ज़ मानकर शायद कुछ फ़ैसले करेंगे. इसलिए अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में जीतना राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के भविष्य के संकेत देता है.

लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में जीतने का थोड़ा–सा और विश्लेषण करना चाहिए. अरविंद केजरीवाल ने समस्याओं को विचारधारा का रूप दे दिया. समस्या चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, उन्होंने दिल्ली में उसी को विचारधारा बना दिया. जबकि विचारधारा के आधार पर समस्याओं को सुलझाने के क़दम उठाए जाते हैं. और जो क़दम विचारधारा के आधार पर नहीं उठाए जाते, उन क़दमों का स्थायित्व बहुत दिनों तक नहीं रहता. सवाल ये है कि पानी का संरक्षण कैसे हो, पानी लोगों को कैसे मिले, पानी बिकने के पीछे कौन लोग हैं, इसका पैसा कहां–कहां जाता है और क्या दिल्ली में हर एक को पानी देने की नीति बनाई जानी चाहिए? उसी तरह बिजली और इसके उत्पादन पर विचार होना चाहिए. कोयला ख़त्म हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, बिजली दिल्ली में ख़ुद बन नहीं रही है. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाए और हर मोहल्ले का और हर उद्योग का एक बिजली घर बन जाए? संभव है, पर ये निर्भर करता है नीति पर. हालांकि, हम ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग़ में ये सारी बातें नहीं होंगी. पर जो चीज़ हमें दिखाई दी, वो ये कि समस्याओं को विचारधारा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि विचारधारा या नीति बनाकर समस्याओं को उनके आधार पर हल करना चाहिए, तभी ग़रीब और वंचित को फ़ायदा मिल पाएगा.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

देश की जनता राजनीति के रंग-ढंग से नाराज़ है. लोगों की समस्याएं राजनीति के रंग-ढंग ने बढ़ाई हैं, उनके रास्ते इस राजनीति ने बंद किए हैं. चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों या किसी भी आर्थिक वर्ग के हों, देश में कोई भी सुखी नहीं है. क्योंकि किसी को जीवन की आशा नहीं दिखाई देती, विकास की आशा नहीं दिखाई देती. इसीलिए लोग इस प्रचलित राजनीति को तोड़ना चाहते हैं. लोग चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आएं, सुलझे हुए लोग आएं, जनता के बीच के लोग आएं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अरविंद केजरीवाल भी अब किसी भी तरह के लोगों को साथ लेने में कोई परहेज नहीं बरत रहे.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 45
दिल्ली, 13 जनवरी –19 जनवरी 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

आम आदमी पार्टी से आशा

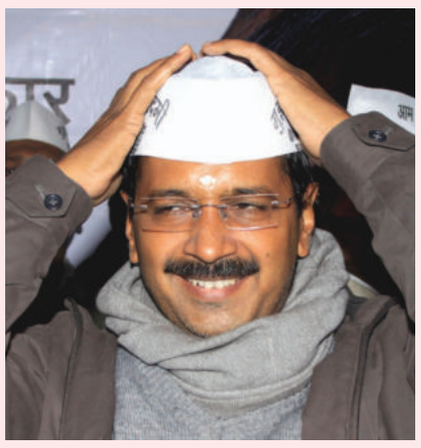

साल 2104 की शुरुआत दिल्ली के उन नौकरशाहों में आशा की किरण लेकर आई है जो आम आदमी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं. पार्टी ने हाल में सरकार बनाकर कई सारे लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है. नौकरशाहों में इस बात को लेकर घबराहट थी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई में विच हंट शुरू करेंगे. लेकिन सूत्रों के अनुसार, कई ईमानदार नौकरशाह आप के सरकार बनाने से काफ़ी ख़ुश हैं. सरकार में बदलाव का स्वागत करने वाले ये नौकरशाह वे हैं जिन्हें लगता है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान किनारे कर दिया गया था. शुरुआत संजय श्रीवास्तव के साथ की गई है, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है. उन्होंने 1976 बैच के आईएस अधिकारी डी.एम. स्पोलिया की जगह ली है. स्पोलिया को शीला दीक्षित का क़रीबी माना जाता है. संजय का नाम मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार ने सुझाया था. माना जाता है कि ज्यादातर प्रशासनिक मामलों में अरविंद केजरीवाल को वे सुझाव दे सकते हैं. अपने आपको कई सालों से उपेक्षित मानने वाले मध्य और छोटे अधिकारियों में भी यह आशा है कि उन्हें मौक़ा दिया जा सकता है.■

आदर्श सोसायटी पर नौकरशाहों का विरोध

अब जब कि कांग्रेस हाई कमान ने महाराष्ट्र सरकार से आदर्श जांच कमीशन रिपोर्ट पर निर्णय की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा है, कई अधिकारी जिनका नाम इस रिपोर्ट में था, वे कह रहे हैं कि उन्होंने तो सिर्फ़ अपने आकाओं के आदेशों का पालन किया है. इस मामले में जिन पर उंगली उठाई गई थी, उनमें से एक सी.एस संगीतराव (विलास राव देशमुख के पूर्व सेक्रेटरी) ने कहा है कि उन्हें तो कमीशन के सामने अपना पक्ष रखने की भी इजाज़त नहीं दी गई.

सूत्रों के अनुसार कई ऐसे अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को पत्र लिखा है जिनका जस्टिस पाटिल की रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया है. मुख्य सचिव जे एस सहरिया के अनुसार, उन्होंने इन अधिकारियों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है. ऐसी अफ़वाह है कि नौकरशाह इस बात से गुस्सा हैं कि सरकार पूर्व तीन मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए तो क़दम उठा रही है, लेकिन उन्हें आदेशों का पालन करने के लिए सज़ा दे रही है.■

नौकरशाहों का बचाव

उत्तर प्रदेश में दुर्गाशक्ति नागपाल प्रकरण के बाद बनी लहर दिल्ली में भी महसूस की जा रही है. राज्यों में काम कर रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राजनीतिक वर्ग से बचाने के लिए क़दम उठाए जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय को उस समय एक पत्र लिखा था, जब नागपाल को अखिलेश सरकार ने निलंबित कर दिया था. उनके पत्र ने सरकार को नौकरशाहों को बचाने के लिए क़दम उठाने की ओर दबाव बनाया.

सूत्रों के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 1969 के ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के लिए बनाए गए एआईएस (अनुशासन और अपील) रूल्स में संशोधन कर एक कैबिनेट नोट बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे राज्य सरकारों को आईएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को निलंबित करने से रोका जा सके. इन संशोधनों के अनुसार, राज्य सरकारों को अपने राज्यों में तैनात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करने के लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा. लेकिन क्या राज्य सरकारें इन प्रस्तावित निर्देशों को स्वीकार करेंगी. इंतज़ार कीजिए और देखिए. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

नीता सचिव नियुक्त

1977 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस नीता चौधरी को गृह मंत्रालय के अर्न्तगत राजभाषा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है. नीता को 1977 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस अरुण कुमार जैन के स्थान पर नियुक्त किया गया है.

वर्मा निदेशक बन सकते हैं

आईपीएस अधिकारी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के विशेष निदेशक के रूप में सेवारत अरुण चंद्र वर्मा को रेलवे सुरक्षा बल के अगले महानिदेशक के लिए नामित किया गया है. वर्मा को 1977 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस पी.के.मेहता के स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है. मेहता जल्द ही सेवानिवृत्त होंगे.

चौधरी विशेष सचिव हो सकते हैं

गृह मंत्रालय ने 1979 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी कृष्णा चौधरी को विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) चयन किया है. चौधरी राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल और पर नागरिक सुरक्षा महानिदेशक के तौर सेवारत हैं.

संजीवनी आईओसी प्रमुख हो सकती हैं

1983 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी और संघ लोक सेवा आयोग में अपर सचिव (संयुक्त सचिव समकक्ष) के रूप में सेवारत संजीवनी कुट्टी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त जा सकता है.

सहाय संयुक्त सचिव नियुक्त

1990 बैच के भारतीय रक्षा खाता सेवा अधिकारी विश्वजीत सहाय को भारी उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. सहाय को 1983 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हरभजन सिंह के स्थान पर लाया गया है. हरभजन सिंह को हाल ही में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में महानिदेशक (राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद) के तौर पर स्थानांतरित किया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए कि उन्होंने नवजवानों की एक ऐसी खेप खड़ी कर दी जो दिमाग़ी तौर पर कांग्रेस और भाजपा के नवजवान नेताओं के सामने बौद्धिक चुनौती पेश कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने पूरी एक नवजवानों की पीढ़ी को दिमाग़ी तौर पर प्रभावित किया है. ये भाजपा और कांग्रेस के नवजवानों का मुक़ाबला बख़ूबी करते दिखाई देते हैं. अगर ये सारे उत्साही नवजवान, जिनमें बदलाव के प्रति आस्था नये सिरे से पैदा हुई है, नीतियों पर भी साफ़ हो जाएं तो भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल की ये बेमिसाल देन होगी.

अगला चुनाव देश का भाग्य बदलेगा

पृष्ठ 2 का शेष

देश की जनता राजनीति के रंग-ढंग से नाराज़ है. लोगों की समस्याएं राजनीति के रंग-ढंग ने बढ़ाई हैं, उनके रास्ते इस राजनीति ने बंद किए हैं. चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों या किसी भी आर्थिक वर्ग के हों, देश में कोई भी सुखी नहीं है. क्योंकि किसी को जीवन की आशा नहीं दिखाई देती, विकास की आशा नहीं दिखाई देती. इसीलिए लोग इस प्रचलित राजनीति को तोड़ना चाहते हैं. लोग चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आएं, सुलझे हुए लोग आएं, जनता के बीच के लोग आएं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अरविंद केजरीवाल भी अब किसी भी तरह के लोगों को साथ लेने में कोई परहेज नहीं बरत रहे. उनके दल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता धड़ल्ले से शामिल हो रहे हैं और शामिल होने के बाद लोगों में असर डाल रहे हैं कि अब वही अरविंद केजरीवाल के ख़ास हैं और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें टीम केजरीवाल में शामिल कर लिया है.

दिल्ली आम तौर पर संपन्न है. यहां झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाल भी कूलर हीटर, एयर कंडीशंड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है. लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में लोगों के पास खाने को रहने को जगह नहीं है. अगर दिल्ली में यह हाल है, या दिल्ली का सामान्य आदमी अपनी ज़िंदगी को लेकर गुस्सा है तो अंदाज़ा लगाना चाहिए कि देश का क्या हाल होगा? देश के जितने भी सीमावर्ती प्रदेश हैं, उन सबमें नक्सलवाद या उग्रवाद बुरी तरह से बढ़ रहा है. कश्मीर से देखना शुरू करें और बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल होते हुए कहीं भी चले आएं, आपको हर जगह नक्सलवाद और उग्रवाद की फ़सल दिखाई देगी. ये नक्सलवाद अब किनारे के प्रदेशों से होकर बीच के प्रदेशों में आ गया है. बिहार में आ गया है, महाराष्ट्र में आ गया है. छत्तीसगढ़ में आ गया है. मध्य प्रदेश में आ गया है. उत्तर प्रदेश में आ गया है. ये समस्याओं को हल न कर पाने के गुस्से से उपजा नक्सलवाद है. लोग कहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकतीं. मुझे लगता है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल की प्रासंगिकता है. अरविंद केजरीवाल अगर समस्याओं को सुलझाने में एक समझदार इंसान का रोल निभाते हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं जो लोगों की समस्याओं को लेकर 24 घंटे चिंतित रहता है तो अरविंद केजरीवाल देश में एक नई आशा पैदा करेंगे और नक्सलवाद या उग्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक नया दरवाज़ा खोलेंगे.

दरअसल, देश का मुख्य सवाल आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक है. लोग अरविंद केजरीवाल से जानना चाहेंगे हैं कि उनकी आर्थिक नीतियां क्या हैं? क्या चलती हुई मौजूदा बाज़ार व्यवस्था के पक्ष में वे हैं या इस पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर वो जनाभिमुखी अर्थव्यवस्था को शुरू करना चाहेंगे, जिसमें हर आदमी को करने के लिए कुछ हो? अगर अरविंद केजरीवाल ये दर्शन सफाई से सामने रखते हैं तो अर्थव्यवस्था को लेकर, समाज व्यवस्था को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश के लोगों को उनमें एक नया नेता दिखाई देगा. और अगर अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह से बाज़ार आधारित अर्थनीति का समर्थन करते हैं तो अरविंद केजरीवाल अपने लिए असफलता का दरवाज़ा ख़ुद खोल लेंगे.

अरविंद केजरीवाल को यह भी साफ़ करना है कि क्या बाज़ार आधारित आर्थिक नीतियां चलेंगी? किसान की फ़सल और उसकी ज़मीन का क्या होगा? जल, जंगल, ज़मीन का निजीकरण हो रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल उसे रोकेंगे? या उसका साथ देंगे. देश की नदियां विदेशी कंपनियों को बेची जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे? ये सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव सिर पर है. इसीलिए जब तक नई आर्थिक नीतियां नहीं बनतीं, सत्ता का विकेंद्रीकरणा नहीं होता, तब तक उठाए गए सारे क़दम काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, ये ख़तरा बना रहेगा.

अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम बनाई है. उनका साथ सुप्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कुमार विश्वास और शाज़िया इल्मी जैसे लोग दे रहे हैं. ये सारे लोग समझदार लोग हैं और इन्होंने अपनी भाषा से बताया है कि उनका पक्ष जनता की तरफ़ है, उनका रुख़ जनता के साथ है. इसके बावजूद उनके एक साथी की भाषा असभ्य, गाली-गलौज भरी व शिष्टता से परे है. अरविंद को यह कहावत ध्यान रखनी चाहिए कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है. लेकिन अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए कि उन्होंने नवजवानों की एक ऐसी खेप खड़ी कर दी जो दिमाग़ी तौर पर कांग्रेस और भाजपा के नवजवान नेताओं के सामने बौद्धिक चुनौती पेश कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने पूरी एक नवजवानों की पीढ़ी को दिमाग़ी तौर पर प्रभावित किया है. ये भाजपा और कांग्रेस के नवजवानों का मुक़ाबला, जिनमें लड़के और लडकियां दोनों शामिल हैं, बख़ूबी हर जगह करते दिखाई देते हैं. अगर ये सारे उत्साही नवजवान, जिनमें बदलाव के प्रति आस्था नये सिरे से पैदा हुई है, अगर ये नीतियों पर भी साफ़ हो जाएं तो भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल की ये बेमिसाल देन होगी. आशा है कि इस बारे में अरविंद केजरीवाल अवश्य सोच रहे होंगे.

दिल्ली आम तौर पर संपन्न है. यहां झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाल भी कूलर हीटर, एयर कंडीशंड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है. लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में लोगों के पास खाने को रहने को जगह नहीं है. अगर दिल्ली में यह हाल है, या दिल्ली का सामान्य आदमी अपनी ज़िंदगी को लेकर गुस्सा है तो अंदाज़ा लगाना चाहिए कि देश का क्या हाल होगा? देश के जितने भी सीमावर्ती प्रदेश हैं, उन सबमें नक्सलवाद या उग्रवाद बुरी तरह से बढ़ रहा है.

अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे में शुरू से एक मतभेद रहा. अन्ना हजारे का ये मानना था बदलाव का रास्ता लोकसभा से जाता है, जबकि अरविंद का ये मानना था कि अगर हम दिल्ली विधानसभा जीत जाते हैं तो उससे देश में एक नई आशा पैदा होगी. आज फिर दो रास्ते हमारे सामने हैं.

अगर अन्ना हजारे जी की बात के पीछे की रणनीति को परखें, अगर यही माहौल अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा की जगह लोकसभा के लिए देश भर में बनाते और लोकसभा का चुनाव लड़ते, तो आज लोग पागलों की तरह देशभर से अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े दिखाई देते, क्योंकि लोगों का गुस्सा अन्ना ने समझा था कि वह सिस्टम के प्रति है. अरविंद ने उस गुस्से का एक रूप देखा. अरविंद के दिल्ली के प्रयोग का एक ख़तरा है. अगर अरविंद का प्रयोग दिल्ली में अगले चार महीने में, तीन महीने में असफल हो गया या कहीं पर थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया तो सारे देश में लोगों को लगने लगेगा कि यह प्रयोग करने लायक नहीं है. शायद इसीलिए अन्ना हजारे पूरे तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे. हालांकि, अरविंद के साथ दो शख़्स ऐसे हैं जो अरविंद को दिमाग़ी तौर पर बांध कर रखने वाले व्यक्तित्व हैं, जिनमें पहला नाम योगेंद्र यादव का है जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की ग़रीब जनता के पक्षधर हैं और दूसरा नाम प्रो. आनंद कुमार का है, जो शुरू से डॉ. लोहिया और जय प्रकाश जी की विचारधारा के मिले-जुले मूर्त रूप हैं. प्रो. आनंद कुमार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी भाषा-शैली, उनका रहन-सहन और चीज़ों को समझने की क्षमता अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मदद है. जहां तक योगेंद्र यादव का सवाल है वो किशन पटनायक के विश्वस्त साथी रहे हैं और किशन पटनायक ने अपनी सारी ज़िंदगी हमेशा ग़रीबों की चिंता में काटी और उनके लिए लड़े. वो डॉ. लोहिया के ऐसे नौजवान दोस्त थे, जिन्होंने संसद में बड़ी-बड़ी बहसों को जन्म दिया था. मुझे आज भी किशन पटनायक और ओमप्रकाश दीपक की जोड़ी याद है. ओमप्रकाश दीपक अद्भुत शख़्सियत थे. शायद आज का ज़माना जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का स्वागत कर रहा है अगर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे को किशन पटनायक और ओमप्रकाश दीपक जैसे व्यक्तित्वों का साथ मिला होता तो आज यह लड़ाई सामाजिक संदर्भों की सभी सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती.

अभी भी वक्त है. अरविंद केजरीवाल देश के बारे में जो भी सोचते हैं उसे वे जाकर अन्ना हजारे को बताएं. अन्ना हजारे को अपनी रणनीति समझाएं, क्योंकि अन्ना हजारे का मानना है कि वो पार्टी और पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान में पार्टी शब्द नहीं है और अन्ना हजारे सच्चे लोकतंत्र के लिए पार्टियों को सही नहीं मानते. लेकिन इसके बावजूद इस संक्रमण काल में अगर अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के पास जाते हैं और अन्ना को संपूर्ण संदर्भ बतलाते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में वो किस तरह से और किन लोगों को साथ लेकर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहेंगे, शायद भारत की राजनीति में यह टर्निंग प्वाइंट हो सकता है. अरविंद केजरीवाल अगर यह समझते हैं कि बिना अन्ना हजारे के वो लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच में कहीं अतिरेक है. आज भी दिल्ली की सरकार को देश के अधिकांश हिस्सों में अन्ना की सरकार कहा जा रहा है. लोग यह धड़ल्ले से कह रहे हैं, ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश, बिहार राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां कहा जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश में अन्ना की सरकार बन गई. इसमें अन्ना का कोई योगदान नहीं है अन्ना का योगदान है तो मात्र इतना कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे कैंपेन को मनोवैज्ञानिक तौर पर अन्ना के साथ जोड़ दिया था. यह रामलीला मैदान जहां अन्ना का अनशन हुआ था, अन्ना का जनलोकपाल का सपना जैसे जुमले दिल्ली के लोगों को अन्ना आंदोलन की याद दिला रहे थे. आज अरविंद केजरीवाल के पास बड़ा मौक़ा है कि वो जाएं, अन्ना हजारे से बात करें, उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें और देश में ग़रीब की आशा, गरीब का विश्वास, देश के लोगों के आखों का सपना जो अन्ना के आंदोलन ने जगाया था, उस सपने को साकार करने के लिए अन्ना को तैयार करें. उन्हें साथ लें. तभी उनके लिए 2014 के चुनावों में सफलता की आशा है अन्यथा 2014 का चुनाव किसी के भी पक्ष में जा सकता है.

मैं आख़िरी पंक्तियां अरविंद जी के लिए कहना चाहता हूं. अरविंद जी, अन्ना जी का कहना है कि वो सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता देश को तोड़ देगी, लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भ्रष्टाचार के भी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भ्रष्टाचार वो कभी सहन ही नहीं कर सकते और यहां से 2014 के चुनावों में अन्ना के हस्तक्षेप और अरविंद के दिमाग़ की एक बड़ी गुंजाइश दिखाई देती है. देखते हैं भविष्य इस देश की जनता के भाग्य में कोई अच्छा पन्ना जोड़ता है, नई इबारत लिखता है या नहीं. मेरा मानना है कि 2014 का चुनाव देश के भाग्य को बदलने वाला चुनाव साबित होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

> एक और बड़ी समस्या बिजली के मीटर को लेकर है. लंबे अर्से से यह कहा जा रहा है कि बिजली का मीटर बहुत तेज़ भागता है. बिजली क़ानून की धारा 38(2)(सी) के अनुसार, बिजली का बहाव समानान्तर होना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिससे मीटरों में झटके लगते हैं और बिल बढ़ता है. लोड शेडिंग में भी यही होता है. दूसरे जो मीटर लगाए गए हैं, जब टेंपरेचर 23 डिग्री से ज्यादा होता है तो मीटर तेज़ चलने लगता है.

ज़ोर का झटका देगी बिजली पर मिली छूट

नीरज सिंह

आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बिजली और पानी के मुद्दों से ही की थी. अपने चुनावी एजेंडे में भी बिजली और पानी को शामिल किया और पार्टी की सरकार बनने पर सबसे पहले 700 लीटर पानी मुफ़्त और फिर 400 यूनिट तक बिजली के बिल को आधा करने की घोषणा की. यह दोनों ही घोषणाएं ऊपरी तौर पर लोकलुभावनी तो दिखती हैं, लेकिन अगर उनका बारीकी से अध्ययन करें तो ज़ाहिर होता है कि इन योजनाओं के माध्यम से जनता को सिर्फ़ एक झुनझुना थमाया जा रहा है, जो पिछली सरकारों से कहीं महंगा साबित होने वाला है. दरअसल, दिल्ली में बिजली उत्पादन से लेकर उसके वितरण तक के पूरे सिस्टम में कई सारे लूप होल हैं और मौजूदा सरकार ने उन होल्स को बंद करने के बजाए या उससे निपटने का कोई रास्ता तलाशने के बजाए सब्सिडी का ज़रिया खोजा है. इस तरह पूर्व की सरकारों की तरह ही इस सरकार ने भी रोग की दवा न खोजने की बजाए रोग को दबाने की ही कोशिश की है.

दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के पास एक ही घिसा-पिटा राग है कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियां, बिजली वितरण करने वाली कंपनियां (एनडीपीएल, बीवाईपीएल और बीआरपीएल) घाटे में जा रही हैं. पिछले दस साल के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो दिल्ली में औसतन प्रतिवर्ष दो बार से अधिक बिजली की दर बढ़ रही है. जबकि बिजली क़ानून 2003 धारा-62(4) कहती है कि बिजली के दाम वर्ष में सिर्फ़ एक बार बढ़ाए जाएंगे. लेकिन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) इन क़ानूनों को नहीं मानता और वह जब चाहता है तब दाम बढ़ा देता है. इसके अलावा विनियामक हर साल कभी विद्युत शुल्क (सर चार्ज) और स्थाई शुल्क (फिक्स चार्ज) के नाम पर उपभोक्ताओं से पैसा वसूलता है. जैसे अप्रैल, 2012 में, अप्रैल, 2012 में उपभोक्ताओं से 5 प्रतिशत ईंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लिया गया. ग़ौरतलब है कि ये कंपनियां केवल बिजली वितरण करती हैं, बिजली बनाती नहीं हैं फिर ईंधन शुल्क क्यों? क्या अरविंद केजरीवाल ने इस व्यवस्था को ठीक करने के बारे में कोई प्रावधान किया?

नवंबर, 2012 में उपभोक्ताओं से 8 प्रतिशत सर चार्ज भी लिया गया. 2010-11 में दिल्ली में तक़रीबन 40.47 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जिनका कि वर्ष 2012-13 में तक़रीबन 45 लाख होने का अनुमान है. ज़ाहिर है कि बिल के अलावा भी इन उपभोक्ताओं से सर चार्ज के नाम पर करोड़ों रुपया वसूला गया फिर भी बिजली कंपनियां घाटे में हैं और उपभोक्ताओं को लूट रही इन कंपनियों को ही मुख्यमंत्री जी सब्सिडी दे रहे हैं.

दिल्ली सरकार ने इन कंपनियों को 2006-07 तक बिजली वितरण का अधिकार दिया था. इसके बाद कब और कैसे इन कंपनियों को फिर से अधिकार मिला, यह सार्वजनिक नहीं है. 2012 में इस संदर्भ में आरटीआई दाखिल की गई थी, लेकिन उसका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया. बिजली क़ानून की धारा 39 के मुताबिक, केवल सरकारी कंपनी या बोर्ड बिजली का वितरण कर सकता है. बावजूद इसके निजी कंपनियों को बिजली वितरण का काम दिया गया है. आरटीआई कार्यकर्ता सीपी राय ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट भी गए, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है.

एक और बड़ी समस्या है बिजली के मीटर को लेकर. लंबे अर्से से यह कहा जा रहा है कि बिजली का मीटर बहुत तेज़ भागता है. बिजली क़ानून की धारा 38(2)(सी) के अनुसार बिजली का बहाव समानान्तर होना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिससे मीटरों में झटके लगते हैं और बिल बढ़ता है. लोड शेडिंग में भी यही होता है. दूसरे जो मीटर लगाए गए हैं, जब टेंपरेचर 23 डिग्री से ज्यादा होता है तो ये मीटर तेज़ चलने लगता है. आदर्श मीटर उसे माना जाता है जो 100 वाट के एक बल्ब के 10 घंटे तक जलने के बाद 1 यूनिट बिजली का ख़र्च दिखाता हो. लेकिन ऐसा है नहीं. ऐसे में प्राथमिकता बिजली के बिल को आधा करने की बजाए इन मीटरों को ठीक करना होनी चाहिए. हालांकि, इन मीटरों को ठीक कराने की बात मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. गड़बड़ी मीटर में नहीं है, दिक्कत न्यूट्रल में है. सिंगल फेज मीटर में सभी को सेपरेट न्यूट्रल नहीं दिया गया है और कॉमन न्यूट्रल की वजह से उन लोगों को भी ज्यादा बिल भरना पड़ता है, जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं.

लुटियंस जोन में बिजली सस्ती दी जाती है. यहां बुनियादी सुविधाएं एनडीएमसी देती है. जबकि एमसीडी के इलाक़े में बिजली महंगी है. यानी केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का आम आदमी महंगी बिजली का उपयोग कर रहा है और ख़ास आदमी सस्ती. मुख्यमंत्री अभी इस दिशा में कुछ नहीं कह रहे हैं.

अब बात करते हैं ऑडिट की. अरविंद केजरीवाल बार-बार कह रहे हैं कि बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया जाएगा, जिससे स्थित साफ़ हो जाएगी और सारी कंपनियों के सारे घोटाले बाहर आ जाएंगे. सीएजी ऑडिट के लिए पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए, लेकिन 2004 से डीईआरसी ने डिस्कॉम का प्रूडेंस चेक नहीं किया है. तो किस आधार पर सीएजी को सही आंकड़े मिलेंगे. यानि ऑडिट की स्थिति भी उतनी स्पष्ट है नहीं, जितना कि दिल्ली सरकार दावा कर रही है.

मेकैनिकल मीटर में मोबाइल चार्जर, जीरो वॉट बल्ब की यूनिट रिकॉर्ड नहीं होती थी, लेकिन जबसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे, तब से यह भी रिकॉर्ड हो रहा है, जिससे बिजली कंपनियां 30 पर्सेंट से अधिक का फ़ायदा कमा रही हैं. उपभोक्ताओं को सेपरेट न्यूट्रल नहीं दिया गया है और ऐसे में उन उपभोक्ताओं का भी ज्यादा बिल आता है जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं. तो फिर इस 50 पर्सेंट वाली इस कटौती का क्या फ़ायदा?

बदरपुर पावर प्लांट में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 अक्षम हैं. इसमें ख़र्च ज्यादा आता है और बिजली कम. लेकिन टोटल ख़र्च डिस्कॉम के खाते में आता है और यही कंज्यूमर की जेब पर भी भारी पड़ता है, उसे सुधारने की कोई व्यवस्था फिलहाल सरकार ने नहीं की है. बवाना पावर प्लांट गैस न मिलने की वजह से बंद है. तब भी इसकी फिक्स कॉस्ट काफ़ी आती है और यह ख़र्चे में जुड़कर उपभोक्ता तक ही पहुंचती है. इस ख़र्चीले दिखावे को सरकार क्यों वहन कर रही है?

बिजली कंपनियां सरप्लस बिजली किस रेट पर बेच रही हैं और किस रेट पर खरीद रही हैं, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खुला होना चाहिए. अगर पावर एक्सचेंज में बिजली तीन रुपये प्रति यूनिट बिक रही है और दिल्ली की कंपनियां उसे दो रुपये में बेच रही हैं तो इसकी सार्वजनिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए. हालांकि, सरकार इस मसले पर भी मौन है.

कई एजेंसियों को पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है, जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जो ज़रूरत से ज्यादा बिजली ख़र्च करते हैं. इनका बोझ भी आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है. ऐसी स्वीट हार्ट डील ख़त्म होनी चाहिए. इसके लिए प्रतिबद्धता की ज़रूरत है न कि सब्सिडी देने की.

एक आख़िरी सवाल की अभी नए बजट के एलोकेशन में दो महीने बाक़ी हैं, लेकिन सरकार ने आते ही 200 करोड़ की सब्सिडी दे दी. हालांकि यह कहा जा रहा है कि सब्सिडी के यह आंकड़े ग़लत है तीन महीने में यह सब्सिडी 350 करोड़ की ठहरेगी. जब बजट नहीं पास हुआ है फिर यह 200 करोड़ रुपए किस मद से दिए गए. दूसरे जो पैसा सब्सिडी का पैसा दिया जा रहा है वह तो जनता का ही पैसा ही, डिस्कॉम से तो कोई वसूली हुई नहीं है, उल्टे उसे पैसा ही दिया जा रहा है, फिर इसमें आम जनता की क्या भलाई.

असली सवाल सरकार की मंशा को लेकर नहीं नहीं है. सवाल तो यह है कि बिजली का बिल कम करने के लिए जिन ज़रूरी क़दमों को उठाए जाने की ज़रूरत थी, सरकार ने पहले वह क़दम नहीं उठाए. पहले जनता को मुफ़्तख़ोरी का एक लॉलीपॉप थमा दिया. यह एक बड़े ख़तरे की ओर संकेत है क्योंकि यह कोशिश मर्ज की दवा खोजने की नहीं है, बल्कि थोड़े समय के लिए दर्द मिटाने वाला इंजेक्शन देने जैसी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली को कैसे मिलेगा मुफ़्त पानी

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अपने वादे के मुताबिक़ मुफ़्त पानी देने की योजना लागू कर दी है, लेकिन फ़िलहाल इस योजना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं. इस योजना को लागू करने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है, क्या उतना पानी दिल्ली जल बोर्ड के पास है? यदि नहीं, तो कहां से आएगा? जिन घरों में मीटर नहीं हैं, उन्हें इसका लाभ कैसे मिलेगा? झुग्गी-बस्तियों समेत आधी दिल्ली में पानी की आपूर्ति नहीं है, वहां के लिए क्या व्यवस्था होगी? अभी पानी और बिजली की आपूर्ति को लेकर कोई स्पष्ट खाका नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह योजना सफल होगी, या फिर यह घोषणा मात्र रह जाएगी?

कृष्णकांत

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जनता को मुफ़्त पानी देने का वादा पूरा किया. पार्टी ने प्रतिदिन 700 लीटर मुफ़्त पानी देने का वादा किया था. सरकार बनने के बाद घोषणा की गई कि सभी मीटर कनेक्शन वाले घरों को 20 हज़ार लीटर यानी क़रीब 666 लीटर पानी प्रतिदिन मुफ़्त दिया जाएगा. नई सरकार ने पानी देने की योजना में यह शर्तें रखी हैं कि मुफ़्त पानी उसी परिवार को मिलेगा, जिसके यहां पानी का मीटर लगा होगा. इस तरह दिल्ली की आधी जनसंख्या को मुफ़्त पानी नहीं मिल पाएगा. शर्त यह भी है कि हर एक परिवार प्रतिदिन 666 लीटर से ज्यादा पानी ख़र्च न करे. इससे ज्यादा एक भी लीटर पानी इस्तेमाल करने पर पूरा शुल्क देना पड़ेगा. उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा. हैरानी इस बात की है कि उसे 10 प्रतिशत बढ़ी दर अदा करनी होगी. यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की इस योजना पर कई सारे सवाल भी हैं.

दिल्ली में पानी के कुल 19 लाख कनेक्शन हैं, जिनमें से तीन लाख बिना मीटर वाले हैं. जिन लोगों ने अभी तक मीटर नहीं लगवाया था, उन्हें 22,000 लीटर पानी प्रति माह की दर से औसत बिल का भुगतान करना होता था. चूंकि, इन लोगों के पास मीटर नहीं है, इसलिए यह व्यवस्था अब भी जारी रहेगी. अब सवाल यह है कि दिल्ली की डेढ़ करोड़ की आबादी है, 25 लाख मकान हैं, जिनमें मात्र 19 लाख कनेक्शन हैं और सिर्फ 16 लाख कनेक्शन मीटर वाले हैं, तो बाकी जनता के बारे में क्या व्यवस्था होगी? ख़ुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में 50 प्रतिशत लोगों के पास पानी का कनेक्शन नहीं है. इन 50 प्रतिशत लोगों तक पानी पहुंचाने की क्या व्यवस्था होगी? इसके अलावा, मौजूदा मुफ़्त पानी की व्यवस्था का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा, जिन क्षेत्रों में पानी आता ही नहीं? झुग्गी-झोपड़ियों में पानी की आपूर्ति की क्या व्यवस्था होगी? जिन क्षेत्रों में पानी के मीटर ख़राब हैं, उनका क्या होगा? पानी के टैंकरों से पानी लेने वाली जनता के लिए सरकार ने फ़ौरी तौर पर क्या व्यवस्था की है? हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैटों में रह रहे परिवारों को यह सुविधा कैसे मिलेगी, जहां पर कॉमन मीटर लगे होते हैं?

ज़ाहिर है कि दिल्ली की नवगठित सरकार की मुफ़्त पानी देने की इस योजना से सबको लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है. दिल्ली में रहने वाला एक बड़ा तबका ऐसा है, जो बेहद संपन्न है और दूसरा तबका वह है जिसकी हालत बेहद ख़राब है. केजरीवाल सरकार ने बदतर हालत वाले तबके को ध्यान में रखकर योजना बनाने की जगह यह घोषणा सबके लिए कर डाली है. सवाल उठता है कि क्या संपन्न तबका, जो पानी और बिजली का बिल देने में सक्षम है, उसे भी मुफ्त बिजली-पानी देने का क्या औचित्य है? दिल्ली के ज्यादातर पिछड़े इलाक़ों में पानी के अवैध धंधेबाज़ों और टैंकर माफ़िया का राज है, क्योंकि सरकार अभी तक वहां पर पानी आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकी है. सरकार की इस योजना से उन लोगों को फ़िलहाल कोई लाभ नहीं मिलेगा. योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनतक स्वच्छ पानी पहुंच रहा है. मुफ़्त पानी और कम रेट पर बिजली का सवाल तो प्रासंगिक उनके लिए था, जो ग़रीब हैं, झुग्गी-बस्तियों में रहे रहे हैं, या अवैध कालोनियों में रह रहे हैं. उनके लिए जीवन ज्यादा संघर्षशील और महंगा है. जो आबादी संपन्न है और बिजली पानी का बिल भरने में सक्षम है, सरकार उसी को फ़ायदा पहुंचाने जा रही है.

अहम सवाल यह है कि दिल्लीवासियों को मुफ़्त पानी पिलाने की यह घोषणा पूरी करने के लिए पानी कहां से आएगा? दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, इस वक्त दिल्ली में रोजाना 855 मिलियन गैलन (एमजीडी) पानी की ज़रूरत होती है. दिल्ली जल बोर्ड गंगा, यमुना, भाखड़ा बांध और भूजल मिलाकर पानी की आपूर्ति करता है. दिल्ली को यमुना से 310 एमजीडी, गंगा से 240 एमजीडी, भाखड़ा बांध से 140 एमजीडी तथा भूजल से 115 एमजीडी पानी मिलता है. दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि सभी दिल्लीवासियों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 165 एमजीडी पानी की कमी है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड हर परिवार को 20 हज़ार लीटर मुफ़्त पानी देता है, तो यह पानी आएगा कहां से? तमाम झुग्गियों और पिछड़े इलाकों समेत दिल्ली में फैली सोसाइटीज में रहने वाली जनता को इस मुफ़्त पानी का लाभ नहीं मिल पाएगा. कई सोसाइटीज ऐसी हैं, जिन्हें इस योजना से कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा. दिल्ली में सैकड़ों ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं, जहां पानी का मीटर कॉमन है. ऐसी सोसाइटीज में रहने वाले हर परिवार को रोज़ कितना पानी मिल रहा है, इसका हिसाब रखना मुश्किल है. सोसाइटी वालों का कोई ज़िक्र न करके उन्हें इस योजना से बाहर ही रखा गया है.

दिल्ली जल बोर्ड में पानी की ज़बरदस्त कमी है, जिसे दूर करने के लिए बोर्ड हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध के बनने का इंतज़ार कर रहा है. यह बांध 2021 तक पूरा हो सकेगा. इस बांध के लिए दिल्ली सरकार 225 करोड़ रुपये दे चुकी है. इसके साथ ही यह भी योजना है कि 10 एमजीडी पानी की आपूर्ति जल बोर्ड यमुना से निकालेगा. लेकिन इस योजना पर बोर्ड ने कितना काम किया, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है. सवाल वही है कि इस घोषणा के बाद जितने पानी की आवश्यकता बढ़ेगी, वह दिल्ली जल बोर्ड कहां से लाएगा. बिना वितरण ठीक किए पानी की इस समस्या से निपट पाना कैसे असंभव हो सकेगा?

मुफ़्त पानी देने की इस योजना पर एक और सवाल है कि पानी वितरण की यह व्यवस्था स्थायी नहीं, बल्कि तात्कालिक है. अगले तीन महीने में क्या जल बोर्ड कोई ऐसा मसौदा पेश करने जा रहा है कि यह योजना स्थायी तौर पर लागू की जा सके? जल बोर्ड पहले से ही अपने कुल पानी का 54 फ़ीसदी मुफ़्त वितरित करता है. जल बोर्ड की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसके द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी का 54 फ़ीसदी कोई रिटर्न नहीं देता यानी इससे कोई कमाई नहीं होती. ज़ाहिर है, यह पानी ज्यादातर ग़ैर-मीटर वाले घरों या कालोनियों में पहुंच रहा है. अगर जल बोर्ड अपने पानी का 54 फ़ीसदी पहले ही मुफ़्त बांट रहा है तो फिर नया क्या हुआ? मुफ़्त पानी की योजना मीटर वाले घरों के लिए है. तो क्या अब मुफ़्त पानी, जो गैर-मीटर वाले घरों को मिलता था, वही मीटर वाले घरों को मिलेगा? बहरहाल, जो घोषणा हुई है, वह स्थायी नहीं है, बल्कि प्रायोगिक तौर पर ही है. अब यह समय बताएगा कि मुफ़्त पानी की यह योजना कितनी सफल होगी. हालांकि, सदन में विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह मसला उठाया कि तमाम इलाक़ों में पानी नहीं पहुंच रहा, वहां पहुंचना चाहिए और जहां मीटर नहीं लगा है, वहां मीटर लगना चाहिए.

इतनी सारी ख़ामियां तब हैं, जब इस योजना की अभी-अभी घोषणा ही हुई है. असली समस्याएं तब सामने आएंगी, जब बिल आने लगेंगे. हालांकि, अब जब सरकार का गठन हो गया है और पार्टी ने विधानसभा में कांग्रेस के सहयोग से बहुमत भी साबित कर दिया है, उसके पास यह मौक़ा है कि अपनी योजना की समीक्षा करे और इसमें मौजूद ख़ामियों को ठीक कर ले. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है. अरविंद केजरीवाल अब छह महीने तक सुरक्षित हैं. अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से समर्थन भी खींच लेती है, तब भी अब लोकसभा चुनाव के बाद ही दिल्ली में चुनाव होने की संभावना है. अब एक सवाल यह उठता है कि अगर फिर से चुनाव होगें तो क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी को फिर से सफलता मिलेगी? क्या आम आदमी पार्टी को इस बार बहुमत मिल जाएगा?

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत

यह कोई करिश्मा नहीं है

मीडिया में अरविंद केजरीवाल की जय जयकार हो रही है. कोई इसे अचंभा बता रहा है तो कुछ लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं. अरविंद केजरीवाल इन सबसे आगे हैं. वे कहते हैं यह तो भगवान का ही करिश्मा है, नहीं तो एक नई पार्टी सरकार बना सकती है यह कोई सोच भी नहीं सकता है. केजरीवाल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान होते तो देश की ये हालत ही नहीं होती. अरविंद केजरीवाल असलियत जानते हैं कि दिल्ली चुनाव का नतीजा कोई करिश्मा नहीं, बल्कि एक सही रणनीति, सही प्रचार और उत्तम चुनाव-प्रबंधन का परिणाम है.

मनीष कुमार

आम आदमी पार्टी बनने के पहले से ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन पार्टी बनने के बाद जून 2013 में उन्होंने इसकी घोषणा की थी. कांग्रेस और बीजेपी की यह भूल रही कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का सही आंकलन नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे. उन्हें इस बात अंदाज़ा था कि नई पार्टी को चुनाव में खड़ा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होगी. सही रणनीति और ढेर सारे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होगी. एक तरफ़ सही मुद्दे के चयन की चुनौती थी और दूसरी तरफ़ संगठन को मज़बूत करने की चिंता थी. इसमें संगठन खड़ा करने की ज़िम्मेदारी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, शाज़िया इल्मी और गोपाल राय ने बड़ी भूमिका निभाई. दूसरी तरफ़, मुद्दे क्या क्या हों, किस इलाक़े में क्या समस्या है, नारे क्या हों, लोग क्या चाहते हैं, इन सब के लिए योगेंद्र यादव और उनकी रिसर्च की पूरी टीम ने आम आदमी पार्टी को फ़ीडबैक दिया. कई सर्वे किए गए. लोगों से राय ली गई.

आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रयोग किया. इस क्षेत्र से दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित विधायक थीं. आम आदमी पार्टी ने पूरे क्षेत्र को 11 अगल-अलग जोन में बांटा. दूसरी पार्टियां एक विधानसभा क्षेत्र को वार्डों में बांटकर योजना बनाती हैं. हर क्षेत्र के लिए छोटी-छोटी टोलियां बनाई गईं. इसका फ़ायदा यह हुआ कि पार्टी घर-घर जाकर लोगों से संपर्क साधने में सफल हुई. शुरुआत में ऐसे लोग सामने आए जो अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े थे. इन लोगों ने घर-घर जाकर लोगों की समस्याओं का पता किया और जिनके घर गए, उन्हीं के ज़रिए पड़ोसियों से संपर्क किया. लोग परेशान तो थे ही, इसलिए उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला. साथ-साथ इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए चंदा भी इकट्ठा किया. लोगों की समस्याएं, परेशानियां और उनकी प्रतिक्रिया का जायज़ा लेते ही आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों को समझ में आ गया कि सिर्फ़ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली पर क़ब्ज़ा किया जा सकता है. इसके लिए 3000 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने मैदान में उतार दिया.

दिल्ली की सभी सत्तर सीटों पर 11 हज़ार से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं. किसी भी पार्टी के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर पोलिंग बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता हों. भाजपा और कांग्रेस ने ज़मीनी राजनीति जब से छोड़ी है, तब से पोलिंग के दिन बड़ी-बड़ी पार्टियां पैसे देकर लोगों को पोलिंग बूथ पर लगाती हैं. लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस चुनौती से निपटने कि लिए दिल्ली के हर इलाक़े में घर-घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ा. कार्यकर्ता बनाए. जो जितना समय दे सकता है उनकी पूरी लिस्ट तैयार हुई. डाटा बैंक बना. फोन नंबर जमा किए गए. हर इलाक़े में तीन चार बार सर्वे किया गया. जिससे पार्टी को मतदाताओं के बारे में सारी जानकारियां हासिल हो गईं. जैसे कि कौन कांग्रेस और बीजेपी के वोटर हैं. कौन न्यूट्रल वोटर हैं. युवा क्या चाहते हैं. गृहणियां क्या चाहतीं हैं. यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में इन सर्वे के ज़रिए अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करने में सफल हुई. लोगों को लगा कि पहली बार किसी पार्टी का कार्यकर्ता उनके घर आ रहा है. संपर्क कर रहा है. साथ ही जिन मुद्दों को पार्टी ने उठाया, जैसे कि भ्रष्टाचार और महंगाई आदि, वह लोगों को दिलो-दिमाग पर चढ़ गया. दूसरा फ़ायदा यह हुआ कि आप अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इससे लोगों ने उसपर भरोसा किया. सबसे ज्यादा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को इस बात से हुआ कि वे दूसरी पार्टियों की तरह राजनीति करने नहीं, बल्कि अन्ना हजारे के बताए रास्ते पर सेवा करने आए हैं. शहरी इलाक़ा होने की वजह से आम आदमी पार्टी को ज्यादा फ़ायदा हुआ. फोन और इंटरनेट के ज़रिए लोगों को संपर्क करना आसान हो गया. यही एक बात यह भी कहनी ज़रूरी है कि जिस ऊर्जा और समर्पण से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उससे यह काम आसान हो गया. पार्टी दिल्ली के 25 लाख घरों में पहुंचने में कामयाब हुई और चुनाव आते-आते हर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग भी हुई.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही थी, वहीं कांग्रेस और बीजेपी पुराने अंदाज़ में चुनाव की तैयारी कर रही थीं. बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस उम्मीदवार पर रहा, उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कैंपेन पर रहा, जो आम आदमी पार्टी के कैंपेन के मुक़ाबले बहुत ही सतही साबित हुआ. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छह-सात महीने अपने-अपने इलाक़े में इतनी मेहनत की, जिससे लोगों ने इस बात की ओर ध्यान भी नहीं दिया कि पार्टी के उम्मीदावार का नाम क्या है. आम आदमी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार न तो प्रभावशाली थे, न ही लोकप्रिय लोग थे. सचमुच वो आम आदमी थे. कोई हलवाई था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, छोटा-बड़ा व्यापारी था और ज्यादातर युवा थे. जहां दूसरी पार्टी टिकट वितरण में इलाक़े के आज़माए हुए, प्रभावशील व चुनाव जीतने की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों पर अपना ज़ोर दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने सतही राजनीति के नीचे सुरंग खोद कर अपनी पैठ बनाई.

आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मध्यवर्ग का मिला. इनमें ज्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले, छोटे व्यापारी, डॉक्टर, टीचर, वकील और पत्रकारों का सबसे ज्यादा समर्थन मिला. ये वर्ग ऐसा था जो भ्रष्टाचार और महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान था. यही वह वर्ग है जो सरकारी विभागों से नाराज़ था. जिन्हें बिजली बिल में गड़बड़ियां नज़र आ रही थीं. वह पानी को लेकर परेशान था. अस्पताल और ट्रांसपोर्ट को लेकर चिंतित था. आम आदमी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का भी भरपूर समर्थन मिला. आम आदमी पार्टी ने हर जगह इस बात पर ज़ोर दिया कि दिल्ली में ठेके पर काम पर रोक लगा दी जाएगी. सफाई कर्मचारी, टीचर, मजदूर, ट्राइवर, मेट्रो में काम करने वाले कर्मचारियों ज्यादातर लोग ठेके पर काम करते हैं. इनकी दिल्ली में एक बड़ी आबादी है. यही वजह है कि शपथ लेने के बाद लोग अपने मुख्यमंत्री से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मौजूद एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी भरपूर समर्थन मिला. इनमें हर विचारधारा और सोच वाले लोग शामिल थे. आम आदमी पार्टी ने अब तक कोई वैचारिक स्पष्टता नहीं दिखाई है, इसलिए वामपंथियों को यह पार्टी केंद्र से लेफ्ट की ओर झुकी नज़र आती है और वहीं दक्षिणपंथियों को यह पार्टी गुड गवर्नेंस देने वाली केंद्र से राइट की ओर झुकी नज़र आती है. इससे पार्टी को यह फ़ायदा हुआ कि विचारधारा के आधार पर किसी ने आम आदमी पार्टी को ख़ारिज नहीं किया. जो संगठन जिन वर्गों में काम कर रहा था, वहां आम आदमी पार्टी का प्रचार स्वत: हो गया. दिल्ली के ज्यादातर एनजीओ झुग्गी-झोपड़ी में काम करते हैं. इन ग़ैर-सरकारी संगठनों ने आम आदमी पार्टी का जमकर प्रचार किया. झुग्गी-झोपड़ी में अब तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा. कांग्रेस पार्टी झुग्गियों में यहां के प्रभावशाली लोगों के ज़रिए ऑपरेट करती आई है. यह बात भी छिपी नहीं है कि पार्टियां पहले झुग्गियों में चुनाव से पहले पैसे और शराब बांटती थीं और लोगों का वोट पाती थीं. लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वयंसेवी संस्थाओं के ज़रिए झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं से सीधा संपर्क साधा. उन्हें घर देने का वादा किया. ठेके पर काम करने से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिया. लोगों ने आम आदमी पार्टी के वादों पर भरोसा किया. यही वजह है कि यह वर्ग आम आदमी पार्टी के गढ़ में तब्दील हो गया.

राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली में आप की सफलता को चुनाव से पहले आंकने में असफल रहे. ऐसा इसलिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ दो चीज़ें ऐसी हुईं, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. पहला यह कि 2008 के चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 14.05 फ़ीसदी वोट मिले थे. यह तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि बसपा का वोटर भी किसी दूसरी पार्टी को वोट दे सकता है और दूसरा यह कि कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक भी खिसक सकता है. आंकलन यह था कि कांग्रेस पार्टी तो हारेगी, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी. कांग्रेस पार्टी हारने के बावजूद 20-25 सीट जीत जाएगी. लेकिन यही उल्टा हो गया. कांग्रेस का परंपरागत वोट आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो गया और बीजेपी इसलिए हारी, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनके मध्यमवर्ग वोटरों में सेंध मारने में सफल हुई.

दिल्ली में सरकार बन गई है. अरविंद केजरीवाल अब छह महीने तक सुरक्षित हैं. अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से समर्थन भी खींच लेती है, तब भी अब लोकसभा चुनाव के बाद ही दिल्ली में चुनाव होने की संभावना है. अब एक सवाल यह उठता है कि अगर फिर से चुनाव होगें तो क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी को फिर से सफलता मिलेगी? क्या आम आदमी पार्टी को इस बार स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा? अगर दिल्ली में फिर से चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी को चिंतित होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को शायद चिंता करने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि कांग्रेस इस स्थिति में ही नहीं होगी. भारतीय जनता पार्टी को अगर दिल्ली में फिर से सरकार बनानी है तो उन्हें आम आदमी पार्टी की तरह ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा. जो घर-घर जाकर संपर्क बना सके. दिल्ली में अब पुराने रीति-रिवाज वाली राजनीति का अब कोई स्थान नहीं है. जो पार्टी जनता के साथ जितना सामंजस्य स्थापित करेगी, वही दिल्ली में राज करेगी. यही लोकसभा में होगा, यही विधानसभा और एमसीडी के चुनावों में होगा. इसमें कोई शक नहीं है कि अगर फिर से चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा. इसकी वजह यह है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली के चप्पे-चप्पे में खड़ा हो चुका है. इस बार मुसमलानों का समर्थन आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है और यही आम आदमी पार्टी के लिए अवसर है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उसी पार्टी को वोट देता है, जो बीजेपी को हरा सकती है. यही वजह है कि दिल्ली में अगर फिर से चुनाव हुए तो बीजेपी को हराने का दमखम सिर्फ़ आम आदमी पार्टी के पास होगा और वे मुसलमानों के वोट के हक़दार हो जाएंगे. इससे कांग्रेस पार्टी के वोट पर ऐसा असर पड़ेगा कि दिल्ली अगले कई चुनावों के लिए आप बनाम बीजेपी में तब्दील हो जाएगी.

manish@chauthiduniya.com

स्टेन की क्रूर हत्या के बाद उनकी विधवा ग्लैडी स्टेन ने मिशन की पूरी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली. अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए ग्लैडी ने ग्राहम की याद में एक अस्पताल की शुरुआत की. ग्राहम स्टेन मेमोरियल नाम के इस अस्पताल के क्षमा और प्रेम के प्रतीक के रूप में ख्याति अर्जित की, जिसकी वजह से ग्लैडी को साल 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.

कुष्ठ रोगियों की ज़मीन हथियाना चाहता है प्रशासन

यह बेहद दुखद है कि ओडिशा सरकार महाराजा आर सी भंजदेव के द्वारा कुष्ठ पीड़ित लोगों के लिए दान की गई ज़मीन को वापस लेने की कोशिश कर रही है. यह जानकर और भी ज्यादा दुख हुआ कि इसकी शुरुआत उस ज़िला अधिकारी द्वारा दबाव डालने के बाद की गई, जिसके मन में कुष्ठ पीड़ित लोगों की सेवा से ज्यादा बारीपाड़ा ज़िले में बढ़ रही ज़मीन की कीमतों को लेकर लालच है. यह सबकुछ उसने अपनी इच्छानुसार किया. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने के लिए ज़िला अधिकारी ने अपने उच्चाधिकारियों को गुमराह किया और ग़लत जानकारियां दीं.

बिभूति पति

ज़मीन का वह हिस्सा जिसे ज़िला प्रशासन हथियाने का प्रयास कर रहा है, वह स्व. ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन को मयूरभंज ज़िले के कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए उपयोग में लाने को दी गई थी. मयूरभंज के राजा ने वह ज़मीन दी थी, जिस पर स्टेन रहे और कुष्ठ रोगियों की 34 साल तक सेवा की. 1999 में एक पागल भीड़ द्वारा मौत के घाट उतारे जाने के पहले तक वे रोगियों की सेवा में लगे रहे.

लोग शायद अभी तक उस घृणित और भयावह कृत्य को भूले नहीं होंगे, जिसमें एक संतस्वरूप व्यक्ति ग्राहम स्टेन और उनके दो पुत्रों, फिलिप और टिमोथी, को मौत के घाट उतारा गया था. उनकी मौत का कारण सहृदयता, ईश्वर का प्रेम फैलाना और मयूरभंज ज़िले के कुष्ठ पीड़ित लोगों की सेवा करना था. उनके द्वारा किए गए समाजसेवा के कार्यों को कट्टरपंथियों ने ग़लत तरीक़े से समझा.

हालांकि, अपने पति और दो बच्चों को खोने के बाद भी स्टेन की पत्नी ग्लैडी स्टेन ने अपने स्टेन द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों को जारी रखा. ग्लैडी को ग्राहम स्टेन के मिशन में बेहतर कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया.

ज़िला प्रशासन के ज़मीन हथियाने के इस ताज़ा क़दम से ग्लैडी काफ़ी हतप्रभ हैं, जो कि अभी भी अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही हैं. वे इस मामले में सिर्फ़ दुख प्रकट करती हैं कि मिशन के कार्य में अवरोध डालने वाले इस काम में सरकार का भी रोल है. यह मिशन 118 साल पुराना है और अपने आप में भारत का विरला मिशन है.

ज़िला अधिकारी राजेश प्रभाकर ने इस मामले में कहा कि ज़मीन सरकार की है और मिशन अपने कार्यों के लिए सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है. हमने जनता की भलाई के लिए ज़मीन का एक हिस्सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए लिया है. इस मामले में इएमएसएम (इवांजेलिकल मिशनरी सोसायटी इन मयूरभंज) की तरफ़ से कोई शिकायत नहीं मिली है.

इएमएसएम के एक अधिकारी का कहना है कि यह ज़मीन मिशन की है, जिसे महाराजा ने 1902 में दान में दिया था. 1974 के बाद से इसपर ट्रस्ट इटानी का अधिकार है, जिस पर यह संस्थान लेप्रोसी होम चलाया जा रहा है. ज़मीन का पूरा उपयोग किया जाता है और इसमें कुष्ठ पीड़ितों के लिए फ़सलें उगाई जाती हैं. ग्राहम स्टेन और उनके सहयोगियों द्वारा लगाए पेड़-पौधे यहां मौजूद हैं. इसलिए ज़िला अधिकारी का कथन सही नहीं है.

एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस ज़मीन को महाराजा आर सी भंजदेव द्वारा रोगियों के इलाज और पुनर्वास के लिए दिया गया था. यह ज़मीन 1902 में दी गई थी, उसके बाद से इस ज़मीन का इस्तेमाल कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई मिशन (होम काउंसिल) और लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है.

कुष्ठ रोगियों को ठीक करने के लिए इस मिशन की शुरुआत 1896 में महाराजा आर सी भंजदेव के आह्वान पर की गई थी. जिसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी केट एलनबाई 1897 में यहां आई थीं. बाद में उनकी बहन ग्रेस एलनबाई ने भी उनके साथ काम किया. उन्होंने मयूरभंज के कुष्ठ पीड़ितों की सेवा की. दुर्भाग्य से उस समय लोगों में इस बीमारी के ख़तरे का प्रतिशत बहुत ज्यादा था. कुष्ठ रोगियों की देखभाल करना उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी. इसे देखते हुए महाराजा ने ज़िले के बाहरी छोर पर मुर्गाबाड़ी में 36 एकड़ जमीन कुष्ठ रोगियों के इलाज और उनके पुनर्वास के लिए दी थी. 1926 में केट एलनबाई ने इस ज़मीन को ट्रस्ट के हवाले कर दिया था, जिसका नाम है इएमएसएम.

महाराजा ने इसके अलावा भी 4.5 एकड़ ज़मीन म्युनिशिपल ऑफिस के नज़दीक बाजपाड़ा कोर्ट के ठीक सामने भी दी थी. यह ज़मीन मिशनरियों के रहने और चर्च स्थापित करने के लिए दी थी. इसे मिशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है.

मिशनरी आए और यहां पर मरीजों के इलाज और उनके पुनर्वास पर काम करना शुरू कर दिया. 1965 में 24 वर्ष के ग्राहम स्टेन यहां आए. बारीपाड़ा के रहने वाले अपने पत्र मित्र इंजीनियर शांतनु सतपति के ज़रिए वे यहां आए थे.

ग्राहम स्टेन ने यहां के कुष्ठ रोगियों के लिए दिन रात काम किया, रोगियों के घाव धुले और उनमें इस सेवा के प्रति आदरभाव जगाया. इस दौरान उस ज़मीन पर मरीजों के पुनर्वास के लिए वार्ड और घर भी बनाए गए. बाक़ी बची ज़मीन का इस्तेमाल मरीजों के लिए स्वास्थ्यवर्धक फल और सब्ज़ियां उगाए जाने के लिए किया जाता रहा.

स्टेन ने कई प्रयासों के ज़रिए स्थानीय लोगों को मिशन के कार्य से जोड़ने की कोशिश की. उन्होंने मिशन में एक डेयरी फार्म भी खोला. लेकिन लेप्रोसी मिशन द्वारा इस फार्म को चलाए जाने के कारण लोगों में एक भय भी था, जिस कारण कोई भी वहां से दूध नहीं खरीदता था. डॉ. विनोद प्रसाद और उनके पुत्र विभू प्रसाद ने पहली बार यहां से दूध ख़रीदा. फार्म की स्थापना उन्होंने इसलिए कि थी कि जिससे लोगों से कुष्ठ रोग के प्रति भय को निकाला जा सके और सभी को साथ लेकर इस भयावह बीमारी को समाप्त करने के लिए साथ काम किया जा सके.

मयूरभंज लेप्रोसी मिशन की 34 सालों की सेवा के दौरान ग्राहम एक मज़बूत स्तंभ बन गए. इस दौरान आने वाली उपहार व दान राशि उन्हीं के पास आती थी, लेकिन 36 एकड़ ज़मीन पर मिशन का ही अधिकार रहा. जब ग्राहम स्टेन की हत्या हुई, उस समय तक भू व्यवस्था कार्यालय द्वारा ज़मीन के एक हिस्से के काग़ज़ात क्लीयर नहीं हो पाए थे. दान और उपहारस्वरूप आए धन से स्टेन ने उस ज़मीन में पुनर्वास के लिए वार्ड और घर के अलावा मछलियों के तालाब व साल फॉरेस्ट भी बनाया था.

स्टेन की क्रूर हत्या के बाद उनकी विधवा ग्लैडी स्टेन ने मिशन की पूरी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली. अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए ग्लैडी ने ग्राहम की याद में एक अस्पताल की शुरुआत की. ग्राहम स्टेन मेमोरियल नाम के इस अस्पताल के क्षमा और प्रेम के प्रतीक के रूप में ख्याति अर्जित की, जिसकी वजह से ग्लैडी को साल 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.

अब जब कि वे अपने काम को और वृहद स्तर पर ले जाना चाहती हैं तो उन्होंने पाया कि अभी तक उस ज़मीन को मिशन के नाम पर दर्ज ही नहीं किया गया है. इसके लिए दिए गया प्रार्थना पत्र उस समय के राजस्व अधिकारी ने ख़ारिज कर दिया था. सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि विभाग का ऐसा निर्णय न सिर्फ़ इस मिशन के कार्यों में बाधा पैदा करेगा, बल्कि भूमाफ़िया के लिए भी रास्ते खोलेगा.

स्थानीय पत्रकार जानकी शास्त्री कहती हैं कि कुष्ठ रोगियों की सेवा के उद्देश्य के साथ खोले गए इस 118 साल पुराने मिशन को अब उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है. हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि कुष्ठ रोग के मामले में शून्य के स्तर पर आ पहुंचे हैं, लेकिन सरकार इस सच्चाई से आंख चुरा रही है कि हाल में इस रोग के मामले प्रकाश में आए हैं. मिशन में लगभग हर सप्ताह नए मामले आते हैं और इसमें से कई मामले नौजवानों के भी हैं. हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं. हमें शहर में कुष्ठ रोगी सड़कों पर भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देंगे, जैसा कि तीस साल पहले हुआ करता था. यह ऑस्ट्रेलिया के लोगों का बलिदान ही है कि एलनबाई, कैमरन, ग्राहम और ग्लैडी जैसे मिशनरियों के बुलावे पर मयूरभंज ज़िले में आकर यहां के कुष्ठ रोगियों की सेवा की और ज़िले को इस बीमारी से मुक्त करने में योगदान दिया.

लोग इस मिशन में उपहार और दान देकर इसे चलाने में मदद कर रहे हैं. लेकिन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे ऐसा मानते हैं कि ईश्वर इंसानों को प्रेम करता है, क्योंकि उसने इंसानों को प्रतिमूर्ति के स्वरूप ही बनाया है. इंसानों के पास जीने का और स्वस्थ रहने का अधिकार है. यह उनके बलिदान का ही प्रतीक है कि वे ऐसा सोचते हैं कि उनकी पेंशन में से कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के लिए उपयोग किया जाए, जिन्हें इसकी ज़रूरत है. इसी वजह से यह मिशन निर्बाध रूप से चल रहा है. यह वाकई में दुखद है कि सरकार और लोगों ने अभी तक इस बात एहसास नहीं किया है कि वे इस मिशन का दबाने के बाद वे कितने निरीह हो जाएंगे. वे उसमें भागीदार ही नहीं चाहते हैं, बल्कि उसे हड़पना भी चाहते हैं जो कभी महाराजा ने कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए दान में दिया था. क्या हम उन रोगियों से भी ज्यादा ग़रीब नहीं बनते जा रहे हैं?

सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि प्रशासन ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर इस ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को भी जोड़ लिया है जो इस प्लांट का शिलान्यास करने वाले थे. लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उन सैकड़ों कुष्ठ मरीजों के बारे में नहीं सोच रहा है जिनका यहां इलाज चल रहा है. कम से कम 100 ऐसे कुष्ठ पीड़ित परिवार यहां रहते हैं, जिनका अपने गांवों में वापस लौट कर जाना मुमकिन नहीं है. वे इस रोग के ख़ात्मे से जुड़े कार्यों में भी लगे हुए हैं. इस मामले में जनता की प्रतिक्रिया के बाद मुख्यमंत्री ने प्लांट का शिलान्यास नहीं किया है. इससे यह प्रतीत होता है कि ज़िला प्रशासन ने प्लांट की ज़मीन को लेकर अपने उच्चाधिकारियों को अंधेरे में रखा हुआ था. ■

प्रशासन ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर इस ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को भी जोड़ लिया है जो इस प्लांट का शिलान्यास करने वाले थे. दुर्भाग्य से कोई भी उन सैकड़ों कुष्ठ मरीजों के बारे में नहीं सोच रहा है जिनका यहां इलाज चल रहा है. कम से कम 100 ऐसे कुष्ठ पीड़ित परिवार यहां रहते हैं, जिनका अपने गांवों में वापस लौट कर जाना मुमकिन नहीं है. वे इस रोग के ख़ात्मे से जुड़े कार्यों में भी लगे हुए हैं.

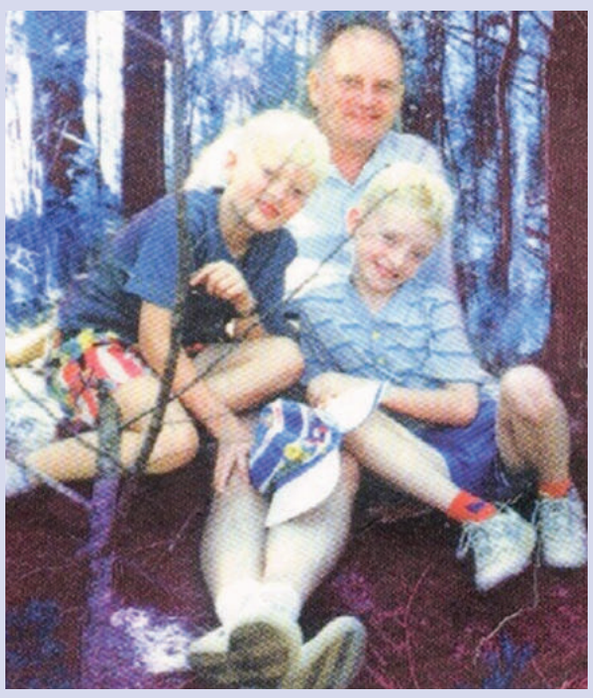

feedback@chauthiduniya.com

जनआकांक्षाओं पर फिरा पानी

एकला चलेंगे वाम

बिहार में सीपीआई कभी बड़ी वामपंथी पार्टी हुआ करती थी. उसके दर्जनों विधायक हुआ करते थे. किसी-किसी ज़िले के तो सभी विधानसभा सीटों पर उसी का क़ब्ज़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे भाकपा का जलवा कम होता गया और अब उसके पास मात्र एक विधायक हैं. इसी तरह माले के दिन भी कभी सुनहरे हुआ करते थे. फिलहाल बिहार में ये विधायक-विहीन पार्टी है.

शशि सागर

बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कुछ फुटकर नेता आपस में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे थे. राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जीत का दंभ उनके चेहरे से साफ़ झलक रही थी. नरेंद्र मोदी की हवा में दूसरी पार्टियों के उड़ जाने की बात तक हो रही थी. बात होते-होते बिहार पर आकर रुकी. गाल भर दाढ़ी और माथे पर तिलक लगाए भाजपा के एक नेता कहते हैं कि इसी लोकसभा में नीतीश को उनकी औकात का अंदाज़ा लग जाएगा. जब यह कहा गया कि आपके छाती पीट-पीटकर विश्वासघात का गाना गाने से कुछ नहीं होगा. नमो के प्रभाव का बहुत असर नहीं पड़ने वाला है बिहार में. नीतीश की विकास पुरुष की छवि सभी पर भारी पड़ेगी. इस पर बीजेपी के नेता ने कहा कि अन्य बातों को छोड़ भी दिया जाए तो अलगाव के बाद जदयू ही आपको ज्यादा कमज़ोर नज़र आएगी. उसके पास कैडर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि हमारे पास है. राजधानी के बाहर जदयू के नेता और कार्यकर्ता आपको सूचनाओं और तर्कों से लैस नहीं मिलेंगे, जबकि हमारा प्रखंड स्तर का नेता भी बता देगा कि नरेंद्र मोदी को वोट क्यों देना चाहिए.

बीजेपी दफ्तर में हुई बातें आईं-गईं हो गईं, लेकिन नेता जी की कही बातें कई मायने में सही हैं. यह सच है कि जदयू के कार्यकर्ता सूचनाओं और तर्कों से लैस नहीं हैं. साथ ही जदयू के पास कैडरों के नाम पर कुछ नहीं है. इसका मतलब यह नहीं है कि इस ओर जदयू की कोई रणनीति काम नहीं कर रही है. यही वजह है कि भाजपा से अलगाव के कुछ समय पहले से ही जदयू की तरफ से कांग्रेस को लेकर नरमी का रुख़ दिखने लगा था. अलगाव के बाद विश्वासमत के दौरान कांग्रेस ने समर्थन भी दिया. अपने एक विधायक के साथ सीपीआई ने भी सरकार को समर्थन दिया. आगामी लोकसभा चुनाव में जहां जदयू सीपीआई को दो-चार सीट देकर उसके कैडरों का फ़ायदा उठा सकती है, वहीं सीपीआई को भी उससे फ़ायदे की उम्मीद है. सीपीआई ने विधानसभा में जदयू को इस तर्क के साथ समर्थन दिया कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी से अलग होना स्वागतयोग्य क़दम है. वैसे इस समर्थन के बाद से ही बिहार में वाम गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे थे. गत महीने ही दिल्ली में वामपंथियों ने ख़ासकर सीपीएम और सीपीआई ने सांप्रदायिकता विरोधी रैली बुलाई थी. इस रैली में भी बिहार की बड़ी वाम पार्टी भाकपा-माले को आमंत्रित नहीं किया गया था. माले के साथ-साथ राजद और लोजपा को भी आमंत्रण नहीं था. जबकि जदयू की तरफ़ से ख़ुद नीतीश कुमार इस रैली में शिरकत कर रहे थे. इस बात पर माले की ख़बरदार रैली के दौरान पार्टी के महासचिव दीपांकर ने कहा भी था कि ग़ैर-सांप्रदायिक पार्टियों की रैली हो और माले को आमंत्रण तक नहीं मिले, यह कहां तक जायज़ है? साथ ही उन्होंने लालू और रामविलास के भी नहीं पूछे जाने पर सवाल खड़ा किया था. सांप्रदायिकता विरोधी रैली और माले की ख़बरदार रैली के दौरान जो संकेत मिले, उससे भी यह माना जाने लगा कि अब बिहार में वामपंथियों का एक मंच पर आना संभव नहीं है. हालांकि, इसकी औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है. बिहार की तीनों वामपंथी पार्टियां फ़िलहाल यही कहती हैं कि हम पहले वाम एकता की ही कोशिश करेंगे, लेकिन हाल के घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा साफ़ दिख रहा है कि यह संभव नहीं है.

पिछले दिनों माले ने यह घोषणा भी की थी कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में बीस सीटों पर चुनाव लड़ेगी. आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, सीवान, कटिहार, नालंदा, बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुज़फ़्फ़रपुर, वाल्मीकिनगर, झंझारपुर, गया, सासाराम, उजियारपुर, जमुई, पूर्णियां, अररिया और गोपालगंज आदि ऐसे ज़िले हैं, जहां से माले अपने उम्मीदवारों को लोकसभा के मैदान में उतारेगी. इसके साथ ही माले यह भी कह रही है कि वह पटना साहिब से वाम का संयुक्त उम्मीदवार चाहती है. माले यह भी कह रही है कि वामपंथी एकता का प्रयास जारी है, अभी इस संभावना पर विराम नहीं लगा है. सीपीआई के खेमे से यह सूचना है कि वह ग्यारह सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी. इन ग्यारह सीटों में खगड़िया, बेगूसराय, मधुबनी, बांका, पूर्वी चंपारण, गया और जहानाबाद के नाम प्रमुख हैं. राजनीतिक हलकों में पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि माले राजद के साथ समझौता कर सकती है. यह कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं. गत कई मौक़ों पर माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक-दूसरे के पक्ष में बयान देते आ रहे हैं, लेकिन माले ने पिछले दिनों साफ़ कर दिया कि कोई भी गठबंधन गैर-कांग्रेस और गैर-बीजेपी ही संभव है. माले के राज्य सचिव कुणाल स्थिति को साफ़ करते हुए कहते हैं कि सांप्रदायिकता के सवाल पर कांग्रेस का जो रुख़ रहा है, वह ख़ुद सवालों के घेरे में रहा है और कांग्रेस के आचरण से ही आज भाजपा इतनी मज़बूत स्थिति में है. कुणाल कहते हैं कि हंसब ठठाए फुलाइब गालू वाली बात नहीं होगी, लालू कांग्रेस का साथ छोड़ें तभी उनसे गठबंधन के बारे में विचार किया जा सकता है. माले यह तो कहती है कि वह वाम एकता का प्रयास कर रही है, लेकिन यह प्रयास कोई मूर्त रूप लेगा, ऐसा होता नहीं दिख रहा है. कुछ दिन पहले ही पटना में एक आयोजन के दौरान सीपीआई के पूर्व महासचिव एबी वर्धन ने नीतीश को धर्मनिरपेक्ष होने का सर्टिफिकेट दिया था और लालू को दगाबाज़ तक कहा था. साथ ही उन्होंने ग़ैर-कांग्रेस और ग़ैर-भाजपा गठबंधन पर बल भी दिया था, लेकिन सूबे के वामपंथियों को यह बात पच नहीं रही है कि विधानसभा में जदयू को समर्थन देने के मामले में तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, फिर समान दूरी की बात कहां से कर रही है. जदयू को लेकर सीपीआई का रुख़ शुरू से ही नरम रहा है. अपने 21वें महाधिवेशन के दौरान ही उन्होंने नीतीश को धर्मनिरपेक्ष कहा था, वो भी तब, जब नीतीश बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे. भाजपा-जदयू अलगाव के पहले ही रांची में माले की सभा में सीपीआई के महासचिव सुधाकर रेड्डी ने वाम एकता की वकालत की थी, लेकिन सभास्थल से बाहर आते ही उन्होंने साफ़-साफ़ शब्दों में कहा था कि अगर जदयू बीजेपी से अलग होती है तो हम जदयू के साथ होंगे. जानकारों का मानना है कि वाम एकता की छद्म कोशिश तो जारी रहेगी, लेकिन सीपीआई और सीपीएम जदयू के साथ ही जाएंगी. ग़ौर करें तो ज़रूरत दोनों को है. जहां जदयू दो चार सीट देकर सीपीआई के कैडर का इस्तेमाल करेगी, वहीं भाकपा किसी तरह क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर उतनी सीटों तक पहुंचना चाहती है, जितने में उसके राष्ट्रीय पार्टी होने का तगमा बचा रहे. राजनीतिक तालमेल के फ़ायदे का स्वाद सीपीआई ने चखा हुआ है. 1972 में वो कांग्रेस के साथ थी और उसके 35 विधायक जीतकर सदन में आए थे. इसके बाद भाकपा यह आंकड़ा कभी छू नहीं पाई.

बिहार में सीपीआई कभी बड़ी वामपंथी पार्टी हुआ करती थी. उसके दर्जनों विधायक हुआ करते थे. किसी-किसी ज़िले के तो सभी विधानसभा सीटों पर उसी का क़ब्ज़ा हुआ करता था, लेकिन

धीरे-धीरे भाकपा का जलवा कम होता गया और अब उसके पास मात्र एक विधायक है. इसी तरह माले के दिन भी कभी सुनहरे हुआ करते थे. फ़िलहाल बिहार में ये विधायक विहीन पार्टी है. माले को इस बात का गुरूर है कि वह पूरे साल जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर विपक्ष की भूमिका निभाने वाली अकेली वाम पार्टी है. वहीं माकपा को इस बात का गुमान है कि वह देश की बड़ी वाम पार्टी है. यह श्रेष्ठताबोध भी उनके गठबंधन के आड़े आता है. वाम एकता की जितनी भी बातें हो जाएं, लेकिन यह संभव नहीं है. यह जनआकांक्षाओं और जनआंदोलनों का दबाव ही है जिस वजह से वाम पार्टियों के नेता एका की बात करते हैं और यह बात तीनों वाम दल जानते हैं कि गठबंधन हो भी गया तो कोई चुनावी फायदा नहीं होने जा रहा है. सीपीआई का दंभ तो कई मसलों पर दिखा भी है. पिछले दिनों जब जदयू को समर्थन देने के सवाल पर एबी बर्धन से पूछा गया कि आपके समर्थन देने से माले नाराज़ चल रही है तो उन्होंने साफ़ कहा था कि माले और दीपांकर के जन्म के पहले से सीपीआई है. हम कोई भी फ़ैसला दीपाकंर या माले से पूछकर नहीं लेंगे. विधानसभा में समर्थन देने के बाद सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात ने भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी, लेकिन फ़िलहाल सीपीएम सीपीआई के साथ खड़ी दिखती है. सीपीएम के राज्य सचिव मंडल के सदस्य और पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जदयू से भाजपा अलग हुई यह स्वागतयोग्य क़दम है, लेकिन उसने सात वर्षों तक भाजपा को फलने-फूलने का मौक़ा दिया है. लगे हाथ सिंह यह भी कह देते हैं कि वैसे आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी सीपीआई के निर्णयों के साथ है. दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे. सीपीएम के इस बदले स्टैंड के अपने मायने हैं. जिस राष्ट्रीय पहचान को बचाने की कोशिश आज सीपीआई कर रही है, वही संकट आने वाले दिनों में सीपीएम के लिए भी आने वाला है.

पिछले दिनों केदार भवन में संसदीय राजनीति और वामपंथ पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था. उसी दौरान एक वामपंथी सदस्य ने कहा कि बिहार में वाम एकता संभव ही नहीं है और सीपीआई का तो एकदम साफ स्टैंड है कि किसी तरह राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता कर लोकसभा में पांच सीट लाई जाए. इसके लिए वो बिहार में जदयू के साथ जाएगी, ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ है ही और जयललिता और चंद्रबाबू नायडू को भी समर्थन दे ही रही है. माले के सवाल पर उन्होंने कहा कि माले को भी स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है, इसलिए वह भी 20-25 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी. उन्होंने माले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माले आत्मगत प्रयास कर रही है कि हम इस बदौलत फिर से उभर सकें, लेकिन आत्मगत प्रयासों की एक सीमा होती है. इसलिए माले को कार्यनीति और रणनीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है. बहरहाल, बिहार में वाम एकता के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो यह दिखता है कि संघर्ष के नाम पर तो ये पार्टियां एक मंच पर आती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की बारी आती है इनका गठबंधन टूट जाता है. गत लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी वामपंथी दलों में पूर्ण समझौता नहीं हो पाया था. भाकपा, माकपा उम्मीदवारों को कई सीटों पर भाकपा माले के उम्मीदवारों से ही कड़ी टक्कर मिली थी. जानकार बताते हैं कि बिहार में फिर से भाकपा की स्थिति 1956 वाली हो गई है और ऐसा पहली बार हुआ है कि माकपा का एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं है. साथ ही माले का तो सूपड़ा ही साफ हो गया है, लेकिन अपनी इस दुर्गति के बाद भी संसदीय मोह से वाम उबर नहीं पा रही है. आज भले सीपीआई लालू को कोस रही हो और नीतीश का गुणगान कर रही है, लेकिन मंडल कमीशन के नाम पर जातिगत आरक्षण का उन्होंने ही समर्थन किया था. बाद के दिनों में उनका वर्गीय जनाधार जाति के आधार पर बंटता चला गया और सीपीआई व माले से टूट कर लोग लालू के साथ चले गए. बहरहाल, बिहार की तीनों वाम पार्टियों को चाहिए कि वे अपनी-अपनी ऐतिहासिक भूल से सबक लेते हुए कोई बेहतर रास्ता निकालें. वैसे इस मसले पर राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं कि जदयू और राजद दोनों को नेशनल पार्टी बनने की आवश्यकता है ताकि वे केंद्र की राजनीति कर सकें और तीनों वाम दल फ़िलहाल एक नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे चुनाव परिणामों में कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है. बहरहाल, देखना यह है कि वाम एकता की यह छद्म कोशिश रंग लाती है या फिर ये वाम दल संसदीय राजनीति के जाल में उलझ जाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सपा से नाराज़ मुस्लिमों पर बसपा की नज़र

अजय कुमार

2013 में बसपा ने भले ही कोई बड़ा राजनैतिक धमाका नहीं किया हो, लेकिन 2104 का आग़ाज़ मायावती धमाकेदार तरीक़े से करने जा रही है. इसके लिए उन्होंने 15 जनवरी का दिन तय किया है. 15 जनवरी यानी माया का जन्मदिन. इस दिन मायावती लखनऊ में सावधान विशाल महारैली करने जा रही हैं. इसमें पूरे देश से बसपाई आएंगे. रैली मैदान पुराना वाला यानी रमाबाई अम्बेडकर मैदान ही रहेगा, जहां रैली करने का साहस माया के अलावा कोई नहीं कर पाता है. रैली को सफल बनाने के लिए मायावती पिछले कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं.

उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2013 में कोई ख़ास धमाका नहीं किया. उनकी तरफ़ से विरोधियों पर हल्के-फुल्के हमले ज़रूर किए गए, लेकिन यह औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं था. माया चुप थीं तो उनके सिपहसलारों ने भी अपवाद को छोड़कर अधिकांश मौक़ों पर मुंह बंद ही रखा. यह सिलसिला नवंबर में हुए चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय भी जारी रहा, जिसका पार्टी को नुकसान भी हुआ. माया की चुप्पी का राजनैतिक पंडितों ने समय-समय पर खूब पोस्टमार्टम किया. किसी ने कहा बहनजी यूपी की गद्दी जाने के सदमे से उबर नहीं पा रही हैं, तो कोई बोला नरेंद्र मोदी के उभार से बसपा का दलित छोड़कर अन्य वोट बैंक भाजपा की तरफ़ खिसक गया है. ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिनको लग रहा था कि माया के राजनैतिक कैरियर में विराम लग गया है. यूपी तो उनसे छिन ही गया था, दिल्ली में भी बसपा के मुक़ाबले समाजवादी नेता पूरे साल ज्यादा चमक फैलाते रहे. इस दौरान बसपा ने अगर कुछ ख़ास किया तो बस इतना कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों (लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाकर) के नामों की घोषणा कर दी. यह और बात है कि बदले राजनैतिक माहौल के बीच उन्हें अपने कई प्रत्याशी बदलना पड़ रहे हैं. माया शांत रहीं तो समाजवादी सरकार भी उनको लेकर चुपी साधे रही, लेकिन जैसे ही माया ने मुंह खोला, सपा सरकार ने भी उनके ख़िलाफ़ हल्ला बोल दिया. साल के पहले ही दिन माया टीम के कई सदस्यों, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार सहित कई मामलों में मुक़दमा दर्ज हो गया. सतर्कता विभाग के महानिदेशक एएल बनर्जी के निर्देश पर राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाने में स्मारक घोटाले में 19 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज होने के साथ ही यह साफ़ हो गया कि चुनावी मौसम आते ही बसपा और सपा को पुरानी दुश्मनी याद आने लगती है.

बहरहाल, 2013 में बसपा ने भले ही कोई बड़ा राजनैतिक धमाका नहीं किया हो, लेकिन 2104 का आग़ाज़ मायावती धमाकेदार तरीक़े से करने जा रही है. इसके लिए उन्होंने 15 जनवरी का दिन तय किया है. 15 जनवरी यानी माया का जन्मदिन. इस दिन मायावती लखनऊ में सावधान विशाल महारैली करने जा रही हैं. इसमें पूरे देश से बसपाई आएंगे. रैली मैदान पुराना वाला (रमाबाई अम्बेडकर मैदान) ही रहेगा, जहां रैली करने का साहस माया के अलावा कोई नहीं कर पाता है. रैली को सफल बनाने के लिए मायावती पिछले कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं. रैली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच हज़ार और लोकसभा क्षेत्र से 25 हज़ार की भीड़ लाने को बसपा नेताओं से कहा गया है. भीड़ को ढोने के लिए बसों और छोटे-छोटे वाहनों के अलावा क़रीब डेढ़ दर्जन रेलगाड़ियां भी बुक कराई गई हैं. बसपा से टिकट की चाह रखने वालों और जिनको टिकट मिल गया है, उन्हें अपना टिकट बचाए रखने के लिए हर हालत में भीड़ जुटाकर मायावती को प्रभावित करना होगा. वामसेफ के कार्यकर्ता इस बात पर नज़र रखेंगे कि कौन नेता कितनी भीड़ लेकर आया.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए आगाह किया गया है. भीड़ में भी मुस्लिमों की तादात अच्छी रहे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. कोशिश यह की जा रही है कि मायावती की रैली पिछले दिनों हुई भाजपा और सपा की रैलियों से हर मायने में बेजोड़ साबित हो. भीड़ का आंकड़ा मोदी-मुलायम की रैली से दोगुना रखने की कोशिश की जा रही हैं. माया अपना वोट बैंक मज़बूत करने के लिए किसानों-मुसलमानों और दलितों पर ख़ास फोकस डाल सकती हैं.

एक तरफ़ बसपा के रणनीतिकार भीड़ जुटाने का रिकॉर्ड बनाने को बेताब हैं तो दूसरी तरफ़ भाजपा, कांग्रेस और सपा नेताओं के ख़िलाफ़ बसपा सुप्रीमो उन मुद्दों को धार देंगी जो लोकसभा चुनाव के समय विरोधियों को घेरने के काम आएंगे. प्रदेश की बिगड़ी क़ानून व्यवस्था के अलावा बसपा की कोशिश उन मुस्लिमों को अपने पाले में फिर से खींचने की है जो 2012 के विधानसभा चुनाव में उससे छिटककर सपा के पास चले गए थे. इसके लिए बसपा मुज़फ़्फ़रनगर दंगों की सियासत को आगे बढ़ाएगी. वह चाहेंगी की किसी भी तरह से मुलायम एंड कंपनी को मुस्लिम विरोधी क़रार दे दिया जाए. इसी लिए दंगों के समय समाजवादी सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया जाएगा. दंगा शिविरों में रह रहे लोगों को बुलडोजर चलाकर हटाए जाने और उनके ख़िलाफ़ (दंगा पीड़ितों) मुलायम के बेतुके बयान को बसपा सुप्रीमो हवा देंगी. इसके अलावा माया ने अपने नेताओं से कह रखा है कि अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ जहां भी समाजवादी सरकार दिक्कतें और भय का माहौल बना रही हैं, वहां ऐसे मुद्दों को गंभीरता से उठाया जाए.

बसपा सुप्रीमो की कोशिश है कि मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के बहाने मुलायम को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समानान्तर खड़ा कर दिया जाए. अपनी बात सिद्ध करने के लिए मायावती पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नक़्शे-क़दम पर चलने का आरोप भी लगा चुकी हैं. उन्होंने यह कहकर सपा को कटघरे में खड़ा किया था कि कड़ाके की ठंड में राहत कैंपों में बुलडोजर चलाकर उनके जख़्मों पर वैसे ही नमक छिड़कने का काम सपा सरकार ने किया जैसा कि भाजपा की गुजरात सरकार मुसलमानों के साथ करती आई है.

बसपा नेत्री लगातार इस कोशिश मे हैं कि जनता में सपा की इमेज भाजपा के साथ एक सिक्के के दो पहलू जैसी बना दी जाए. यह ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे बसपा अपने सभी विरोधियों कांग्रेस, सपा, भाजपा और रालोद को एक साथ घेर सकती है. हालांकि, कहा यह भी जा रहा है कि यह काम इतना आसान नहीं है. माया जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की सियासत को हवा देंगी तो उनके सामने भी यह सवाल खड़ा होगा कि उनकी सरकार ने भी तो मुसलमानों की नहीं सुनी थी, आज भी उनका यही नज़रिया है. इसीलिए तो वह दंगा पीड़ितों का दुख-दर्द बांटने मुज़फ़्फ़रनगर नहीं गईं. हो सकता है इसकी सफाई वह सावधान रैली में दें. अन्य तमाम दलों के अलावा उनकी तेज़ी से उभर रही आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोच है, इसका जबाव भी जनता उनसे सुनना चाहेगी. उत्तर प्रदेश में पिछले करीब दो दशकों से बसपा ही ऐसा दल है जो समाजवादी पार्टी को चुनौती देता रहा है. इसीलिए माया की सावधान रैली पर अन्य दलों के नेताओं के अलावा सपा नेताओं की सबसे अधिक नज़रें जमी हुई हैं. सपा अभी से रैली की हवा निकालने की तैयारी में भी जुट गई है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विरोधी दल राहत शिविरों में राजनीति कर रहे हैं. उनके बड़े नेता वहां दौर करते हैं, लेकिन सुझाव मांगो तो वे नहीं देते. बल्कि अपने दौरों की ख़बर ज़रूर चलवाते हैं. समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे (मायावती) फिर पहले की तरह अपने सांसदों, विधायकों और नेताओं से जन्मदिन की चंदा वसूली में लग गई हैं. जिसमें कइयों की जानें जा चुकी हैं.

बसपा, सपा-भाजपा को एक ही थाली का बैगन बताने में जुटी है तो सपा नेता ने आरोप लगाया कि मुज़फ़्फ़रनगर के मुस्लिमों के लिए दिखावटी हमदर्दी दिखाकर भाजपा की बी टीम का फ़र्ज़ निभाने जा रही है. लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और जनता को ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा जो मानवीय त्रासदी का भी सियासी फ़ायदा उठाने की साज़िशों से बाज़ नहीं आते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

किस काम की है यह पारदर्शिता

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का एक ही आदर्श जवाब रहा है कि वे चाहते थे कि कोल ब्लॉक का आवंटन बोली लगाकर किया जाए. वह पारदर्शिता चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. समझ में नहीं आता कि अगर वे चाहते थे कि ऐसा हो तो कौन हो सकता है कि जो उनके निर्णय के विरुद्ध जाए? वह देश के प्रधानमंत्री हैं. यह बेहद चिंता का विषय है और देश के प्रधानमंत्री पर यह फ़बता भी नहीं है कि वे कहें कि मैं यह चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

पुलिस और सेना का इस्तेमाल करके लोगों को मारकर आप प्रधानमंत्री पद के मज़बूत दावेदार होने का दावा नहीं कर सकते. यह आपकी कमज़ोरी दर्शाता है, ताक़त नहीं. मैंने इस कॉलम के माध्यम से पहले भी कहा है कि जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार चुने गए, तब उन्होंने कहा कि वे सेना के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे. वास्तव में वे कोई अध्ययन नहीं करते. उन्हें समझना होगा कि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति है. वैसे भी युद्ध कोई विकल्प नहीं होता.

पिछले दिनों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उनके इस कार्यकाल की संभवत: यह तीसरी या चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री से जुड़ी कई सारी उम्मीदों पर चर्चाएं हो रही थीं. यहां तक अफ़वाह थी कि उन्हें इस पद से हटाया भी जा सकता है, जो कि निश्चित रूप से सत्य से परे थी. बहरहाल, आख़िर यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना आवाज़ का पटाखा साबित हुई. सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने पंद्रह मिनट का जो शुरुआती वक्तव्य दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तब तक जो आंकड़े गिनाए और बताया कि वे क्या कर चुके हैं और यह सब कुछ सबके सामने है. बेहतर तो यह होता कि वे इन आंकड़ों का इस्तेमाल उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देने में करते. दूसरे, पत्रकारों ने जो सवाल पूछे, वह भी उन्हीं निर्धारित लाइनों पर थे जो कि पहले से ही पूछे जा रहे हैं. इस तरह मीडिया के सवालों में भी भटकाव रहा.

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का एक ही आदर्श जवाब रहा है कि वे चाहते थे कि कोल ब्लॉक का आवंटन बोली लगाकर किया जाए. वह पारदर्शिता चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. समझ में नहीं आता कि अगर वे चाहते थे कि ऐसा हो तो कौन हो सकता है कि जो उनके निर्णय के विरुद्ध जाए? वह देश के प्रधानमंत्री हैं. यह बेहद चिंता का विषय है और देश के प्रधानमंत्री पर यह फ़बता भी नहीं है कि वे कहें कि मैं यह चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आपकी बात नहीं मानी गई तो आपको संबंधित मंत्री को बर्ख़ास्त कर देना चाहिए था. संबंधित अधिकारी पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए था. अगर आपकी बात ही नहीं मानी जा रही है फिर आप सरकार कैसे चला सकते हैं? अपनी टेफलॉन इमेज को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि मैं वही अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह हूं, जिसने हमेशा ही पारदर्शिता और स्पष्टता में विश्वास किया है. लेकिन अब जब आप पॉवर में हैं तो यह कह कर बच नहीं सकते. यह वक्त है कि आप क्रियान्वयन करें और करके दिखाएं. पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार भी किसी भी मामले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली. ऐसा कोई भी क़दम कांग्रेस पार्टी को कोई मदद नहीं देगा.

हालांकि, उन्होंने यह ज़रूर कहा कि राहुल गांधी एक योग्य व्यक्ति हैं और यह संकेत भी दिया कि वे पार्टी की तरफ़ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं. हां, उनके पूरे वक्तव्य का जो सबसे सही हिस्सा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक स्पष्ट स्टैंड लिया. उन्होंने कहा कि अगर आपकी निगाह में ताक़तवर व्यक्ति वह है जो अहमदाबाद की गलियों में मासूम नागरिकों की हत्या का अपराधी हो तो देश के प्रधानमंत्री को ऐसी ताक़त की ज़रूरत नहीं है. मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य उचित था, भले ही देर से आया, लेकिन सही वक्तव्य.

पुलिस और सेना का इस्तेमाल करके लोगों को मारकर आप प्रधानमंत्री पद के मज़बूत दावेदार होने का दावा नहीं कर सकते. यह आपकी कमज़ोरी दर्शाता है, ताक़त नहीं. मैंने इस कॉलम के माध्यम से पहले भी कहा है कि जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार चुने गए, तब उन्होंने कहा कि वे सेना के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे. वास्तव में वे कोई अध्ययन नहीं करते. उन्हें समझना होगा कि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति है. वैसे भी युद्ध कोई विकल्प नहीं होता. भारत में हमें स्थिर राजनीतिक परिवेश मिला है और हम ऐसे बात नहीं कर सकते. निश्चित रूप से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाओं का मज़बूत बने रहना ज़रूरी है, और हमारी सेनाएं मज़बूत हैं. मुश्किल राजनीति का कमज़ोर होना है और नरेंद्र मोदी इस पक्ष को मज़बूत करने की बात करने के बजाए यह कह रहे हैं कि यह एक कमज़ोर सरकार है, मैं एक मज़बूत सरकार दूंगा और पाकिस्तान से रिश्ते सुधारूंगा. मोदी यह भी कहते हैं कि वे पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, इसलिए मोदी के व्यक्तित्व में अलग तरह की कमज़ोरी भी झलकती है और इसे प्रधानमंत्री बेहतरीन तरीक़े से लोगों के सामने ले आए.

फिर भी भ्रष्टाचार के मुद्‌दे पर प्रधानमंत्री बैकफुट पर दिखे. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कई बार मीडिया कुछ मुद्‌दों को लेकर अतिरेक बरतता है और कई बार सीएजी भी ऐसा ही व्यवहार करता है, जबकि सभी आंकड़े सीएजी को भेज दिए गए हैं. यह कोई मसला नहीं है. असली मसला तो यह है कि सीएजी पहले ही यह कह चुका है कि जो नुकसान हुआ है वह सरकारी कार्यविधि के चलते हुआ है और प्रधानमंत्री ने इसे अपनी स्वीकृति भी दी है. और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वे बोली के माध्यम से नीलामी के पक्ष में थे और वे पारदर्शिता के पक्षधर हैं. वास्तव में दोनों के विचारों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक रूप से प्रधानमंत्री इन मुद्दों से किनारा कर गए.

यह स्थितियां हमें उस सवाल की ओर ले जाती हैं कि अगले चुनाव में क्या होगा? यह एक गंभीर और विचारणीय मुद्दा है. हम लोग ख़ुशक़िस्मत हैं कि हमें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी जैसा व्यक्ति मिला है जिसे लेकर यह भरोसा है कि आख़िर कोई तो है जो परिस्थितियों पर एक संपूर्ण दृष्टिकोण रखता है.

राजनीतिक पार्टियां जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं अगर वही व्यवहार जारी रखती हैं तो निश्चित तौर पर हम बुरे दौर से गुज़र रहे हैं और इसे देश के लिए बेहतर स्थिति नहीं कहा जा सकता.

सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि एक साथ बैठकर यह हल निकालें कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जाए. सही है कि एक दिन में सब कुछ नहीं बदला जा सकता. पाकिस्तान के मसले को एक दिन में नहीं हल किया जा सकता. कश्मीर विवाद पिछले 60 वर्षों से चला आ रहा है, इससे एक दिन में तो नहीं निबटा जा सकता. आपको परिस्थितियों को और परिपक्वता से समझना होगा. मौजूदा व्यवस्था के साथ ही नहीं चला जा सकता. आप केवल धमकी के भरोसे नहीं चल सकते. यह बचपना है, लेकिन आज के राजनेता यही कर रहे हैं.

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई. देश को एक नया संदेश मिला, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसे देखते हुए अभी यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि वास्तव में उनकी सोच क्या है. हम उनकी विचारधारा को नहीं जानते. क्या वे कॉरपोरेट सेक्टर के हितैषी हैं?

क्या वे पब्लिक सेक्टर के पक्ष में हैं. हम जानते हैं कि वे भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का विरोध मात्र ही पर्याप्त नहीं है. हां, यह ज़रूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं. केवल भ्रष्टाचार का विरोध करने मात्र से ही देश की सारी समस्याएं हल नहीं हो जातीं. आपके ख़ुद के क्या विचार हैं? आप देश के युवाओं की ऊर्जा का किस तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं? आप किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मज़बूत करेंगे जो कि हक़ीक़त में आपके अधीन है ही नहीं. यह तो केंद्र सरकार के पास है. इसलिए हम यक़ीक़न यह नहीं जानते कि यह पार्टी कहां खड़ी होती है, और यह तब तक मुश्किल रहेगा, जब तक वे वे आने वाले दिनों में अपने विचारों को तराश कर देश के सामने नहीं रखते. वास्तव में आने वाले चुनावों के दौरान एक बेहद भ्रामक माहौल रहेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्र की एकता को बचाइए

ठाकुर दास बंग

यह दिशा सही है तो गांव के सारे आपसी विवाद सत्याग्रह की पद्धति से हल होने चाहिए. सत्याग्रह की अहिंसक रीति-नीति आमने-सामने के संवाद से शुरू होती है. इस शस्त्रागर में अस्त्र-शस्त्रों की कमी नहीं है? परिस्थिति के अनुसार अस्त्र विशेष का प्रयोग किया जा सकता है, शर्त इतनी ही है कि सत्याग्रह में सरकार के न्याय और सरकार की बंदूक का सहारा नहीं लिया जा सकता. अंतिम समाधान सत्याग्रही उपायों से ही संभव है.

पहला चरण-लक्ष्य और कार्यक्रम

1. ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखकर हम अगले चरण के लक्ष्य और कार्यक्रम स्थिर कर सकते हैं. आज देश को जिस व्यापक जागृति की आवश्यकता है वह नव-जागरण से ही संभव है, लोक चेतना को नए विचार और राष्ट्रभावना का स्पर्श मिलना चाहिए. उसके बिना निर्माण-कारी पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलना कठिन है. नवजागरण की भूमिका में समग्र कार्यक्रम विकसित होगा.
2. अगले चुनाव में जनता उम्मीदवार हमारे आंदोलन का एक छोर गांव है और दूसरा संसद और विधानसभा. दोनों बिंदुओं पर साथ-साथ लोक-शक्ति प्रकट होनी चाहिए.
3. गांव-गांव की ग्राम-सभाएं नगर-सभाएं-आवश्यकतानुसार मुहल्ला-सभाएं भी अपनी आंतरिक व्यवस्था के अधिक से अधिक क्षेत्रों में स्वायत्तता की घोषणा करें. उनकी ओर से मांग हो कि उनकी स्वायत्तता की दृष्टि से संविधान का संशोधन भी हो ताकि ग्राम और नगर इकाइयों के अधिकार-क्षेत्र निर्धारित किए जा सकें.
4. खेतिहर मज़दूर दस्तकार-ग्राहक के लिए उचित मूल्य का अभियान हो.
5. प्रेस की स्वतंत्रता की पूरी शक्ति लगाकर रक्षा की जाए
6. गांव के उद्योग विकसित किए जाएं जो माल गांव में कच्चे माल से तैयार हो सके वह गांव में ही तैयार हो.
7. व्यक्तिगत तथा गांवों द्वारा सामूहिक स्तर पर संकल्प हों कि वे ग्रामोद्योगों की ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और उनके लिए बड़े उद्योंगो का बहिष्कार करेंगे.
8. हर पंचायत में कम से कम एक कार्यकर्ता हो
9. राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर सक्रिय और समर्पित साथियों का भाईचारा बने जिनकी अगुवाई में सारा काम हो.

ये पहले चरण में संगठित कार्य के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं. सबको मिलाकर अहिंसक क्रांति का एक संपूर्ण, समग्र, कार्यक्रम बनता है, हमे अपने राष्ट्र की नियति तथा लोकशक्ति की संभावनाओं में अटूट श्रद्धा रखकर आगे बढ़ना है. आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो जलमग्न पृथ्वी के बीच मार्कण्डेय बनकर नई सृष्टि का उद्‌गम बन सकते हैं

व्यूह रचना

- लक्ष्य, मूल्य तथा कार्यक्रम की एकता के आधार पर व्यक्तियों तथा संगठनों का भाईचारा, जिनमें परस्पर विश्वास और आदर की भावना हो.
- अहिंसा की भूमिका में डाइनेमिक सत्याग्रह-व्यक्तिगत और सामूहिक-के नए प्रयोग, जो नैतिक लोकशक्ति को प्रकट करने में समर्थ हों. इस दृष्टि से स्थानीय प्रश्न व्यापक रूप से हाथ में लिए जाएं.
- उचित मूल्य के लिए अभियान की तैयारी
- राष्ट्रीय तथा स्थानीय, दोनों स्तरों पर साथ-साथ काम हो, जन-जागरण और कुछ प्रश्नों पर लोकमत का निर्माण, लोकशक्तिमूलक रचनात्मक कार्यक्रम, अनीति का प्रतिकार और लोक-उम्मीदवार पर शक्ति केंद्रित की जाए.

आज भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मुझे जो नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है वह है लड़ाई की! लड़ाई किसके विरुद्ध? राष्ट्रीय जीवन में बढ़ती जा रही खंडता, विभाजन सभी क्षेत्रों में स्वार्थान्धता, मूल्यच्युति, दिशाहीन पथभ्रष्टता, अशुचिता के प्रति. सन 1920 में गांधी जी को भारत में ऐसी ही लड़ाई की ज़रूरत महसूस हुई थी. उन्होंने जनता को अस्त्र दिया था असहयोग का. तब वह अस्त्र कार्यक्षम था, क्योंकि लड़ाई बाहरी शासन द्वारा यहां हो रहे आर्थिक नियंत्रण तथा सांस्कृतिक उन्मूलन के प्रति थी. उसके प्रतिकार के लिए सियासी आज़ादी की प्राथमिक आवश्यकता अवश्य थी, लेकिन वही एकमात्र लक्ष्य नहीं थी. इस अलावा उस समय हमें (गांधी-जीवन-दर्शन के अनुसार सामाजिक कार्य करनेवालों को) सत्ता हाथ में लेकर शासन संभालने की आवश्यकता नहीं थी, ज़िम्मेवारी भी नहीं थी. शासक वर्ग को सुधार के लिए दिशा-निर्देश करते हुए अपना मुख्य कार्य जनता में सद्‌विचार-संचार का, लोक-शिक्षण का था. उभयदिशा का वह कार्य अपक्षित परिणाम में एवं गहराई से हो नहीं पाया. यह हम अनुभव करते ही होंगे और आज की दशा से उसका संबंध बैठाते होंगे.

अब आज लड़ाई के दो मोर्चे रहना अनिवार्य हो गया है 1-सत्ताधरण में आए हुए प्रदूषणों को निकालने एवं शासन-शुद्धि के लिए राजनैतिक क्षेत्र में प्रयत्न 2- सत्तावाहक वर्ग आत्मभान न भूले, पथभ्रष्ट न हो-इसकी चौकसी रखते हुए उसे चेतावनी देते रहनेवाला तथा संतुलन रखनेवाला दूसरा वर्ग.

ऐसा द्विविध कार्य करने के लिए देशभर में बिखरे हुए गांधी-जीवन-दर्शन के विश्वासी एवं तदानुसार जीनेवाले व्यक्तियों, छोटी-छोटी स्थानीय संस्थाओं एवं सर्वोदय-विचारधारा के अंतर्गत विविध रचनात्मक कार्य एवं सद्‌प्रवृत्तियां चलाने वाले समूहों को एक मंच पर आ जुटना होगा. उक्त प्रकार से दो मोर्चे संभाल-कर सम्मिलित शक्ति लगानी होगी. सत्ता के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना गांधी-जीवन-दर्शन को जिलाना संभव नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें स्वयं इतना जीवट है कि जो उसे अमर बनाए रखें, लेकिन गांधी विचार तुरही एक पुकार करती रहे और सर्वग्रासी शासन की दुन्दुभि कुछ और ही नाद गुंजाती हुई जनता के दिल-दिमाग़ को बधिर करती चली जाए-दोनों की दिशाएं सवर्था विरोधी हों, तो राष्ट्र की एकता बचाई नहीं जा सकेगी. राष्ट्र की एकता को बचाने के लिए गांधी की विचारधारा के व्यक्ति एकत्र हों, उक्त प्रकार से द्विविध मोर्चा संभालने को, तभी काम बनेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

आज भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मुझे जो नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है वह है लड़ाई की! लड़ाई किसके विरुद्ध? राष्ट्रीय जीवन में बढ़ती जा रही खंडता, विभाजन सभी क्षेत्रों में स्वार्थान्धता, मूल्यच्युति, दिशाहीन पथभ्रष्टता, अशुचिता के प्रति. सन 1920 में गांधी जी को भारत में ऐसी ही लड़ाई की ज़रूरत महसूस हुई थी. उन्होंने जनता को अस्त्र दिया था असहयोग का. तब वह अस्त्र कार्यक्षम था, क्योंकि लड़ाई बाहरी शासन द्वारा यहां हो रहे आर्थिक नियंत्रण तथा सांस्कृतिक उन्मूलन के प्रति थी.

पाठकों की दुनिया

आप का उदय

आम आदमी पार्टी का उदय देश की बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनौती है, जिसे राजनीतिक पार्टियां नकार नहीं सकती. आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है वह कोई नई बात नहीं है. यह मुद्दे ऐसे हैं जो पहले से ही देश में मौजूद हैं. उसे ही आप ने राजनीतिक एजेंडा बनाया. बाकी पार्टियां भी चाहतीं तो उसे अपना एजेंडा बना सकती थी लेकिन पार्टियों ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया या वह जनता के सामने इन मुद्दों को रखने में नाकाम रहीं जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिला. यदि अब भी ये पार्टियां अपने आप को नहीं बदलेंगी तो हो सकता है, आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही चमत्कार कर सकती है. लोकसभा चुनावों में यह आसान नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो हवा पूरे देश में है उसे कम कर पाना आसान नहीं है. आम आदमी पार्टी ने ही अपने एक सर्वे में कहा है कि आप को जो सपोर्ट करते हैं उसमें से लगभग 32 प्रतिशत या उससे ज्यादा लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनें. नरेंद्र मोदी या भाजपा जाहिर न होने दें, लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी के माथे पर तनाव जरूर देखा जा सकता है. भाजपा ने बहुत सावधानी से दिल्ली में सरकार न बनाने का फैसला किया, जो सही था. यदि वह सरकार भी बनाती तो उसकी सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाती क्योंकि भाजपा ने पहले कह ही दिया था कि हम समर्थन न लेंगे न देंगे. आप पार्टी को कांग्रेस से समर्थन का नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि आप ने इन दोनों पार्टियों को भ्रष्ट बताया था और उन्हीं में से एक कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई है. भाजपा को आप के खिलाफ एक मुद्दा मिला गया जो वह चुनावों के पहले से उठाती रही है कि आप और कांग्रेस का अंदरूनी गठबंधन है. अभी लोकसभा चुनाव में कम से कम लगभग 6 महीने का समय है अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन पार्टी बाजी मारती है और जनता किसे देश का सिंहासन सौपती है.

विक्रांत, *दरभंगा*

देश के लिए घातक कौन

आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट यूपीए सरकार की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मुझे पाक-साफ लिखा जाएगा. जी हां, प्रधानमंत्री जी देश के इतिहास में आपके बारे में जरूर लिखा जाएगा लेकिन पाक-साफ नहीं बल्कि देश की महानतम भ्रष्ट सरकार की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तौर पर. यदि ईमानदार और सफल प्रशासक होते तो यूपीए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए मजबूर होती. जिस प्रकार मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया. मनमोहन सिंह एक प्रशासक और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेराजगारी हर मोर्चे पर फेल हुए हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रत्येक मोर्चे पर सफल हैं और उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ी है. यूपीए सरकार ने जिस प्रकार से लूटा है उसका ही नतीजा है कि नरेंद्र मोदी उभरे हैं और देश में लोकप्रिय हुए हैं. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की बर्बादी होगी. प्रधानमंत्री जी आपने तो देश को बर्बाद करने के बाद बॉय-बॉय कहा है. नरेंद्र मोदी ने तो गुजरात को बर्बाद नहीं आबाद किया है और जो आपने मोदी को देश के लिए घातक बताया है, वह जनता देख चुकी है कि 10 सालों में देश के लिए सबसे घातक कौन है?

मनोहर, *छपरा*

गठबंधन के संकेत

आगामी लोक सभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा या नहीं यह तो चुनाव बाद साफ हो जाएगा, लेकिन अभी से पार्टियां गठबंठन को लेकर एक-दूसरे के साथ जोड़-तोड़ में जुट गई हैं. अभी से जो चुनाव में गठबंधन के समीकरण उभर रहे हैं, उसे देखकर लगता है जो पार्टियों एक दूसरे को चुनाव में गाली देती फिरती है चुनाव बाद उसी से अनेकों बहाने कर गठबंधन करती दिखती है. अंदर खाने गंठबंधन हो जाता है और जनता के सामने कुछ और दिखाया जाता है और कांग्रेस तो इसमें माहिर है. अभी जो दिल्ली में गठबंधन के समीकरण देखने को मिले हैं उससे किसी को अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद भ्रष्ट पार्टियां एक-दूसरे को ईमानदार दिखने लगती है. सत्ता के लोभ में पार्टियां भ्रष्टाचार पर अपने द्धारा उठाए गए मुद्दो से भी समझौता करती है. पार्टियां कसम खाएं या कुछ करें, क्योंकि आप के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने बच्चों की कसम खाते थे. उन्होंने देश की कांग्रेस, जिसके खिलाफ जनता ने उनको 28 सीटों तक पहुंचाया उसी से गठबंधन करके सरकार बनाई है. वह चाहे जो सफाई दें कि हमने तो कोई गठबंधन नहीं किया. लेकिन ऐसा तो सारी पार्टियां कहती हैं. अंदरखाने कुछ और होता है. वह जनता देख चुकी है. उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं और केंद्र में समर्थन देते हैं. केजरीवाल कहते हैं कि संसद में सब चोर हैं, उनको जदयू विधायक शोएब इकबाल ने समर्थन दिया है और विधानसभा में विश्वासमत के दौरान उन्होंने जो किया वह सबने देखा. आप पार्टी ईमानदार है तो समर्थन लेने से क्यों नहीं इनकार किया? यह सब दिखावा है और कुछ नहीं है. यदि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो अब यही 2014 लोकसभा चुनाव में भी होगा. कांग्रेस इसमें माहिर है. अंदर खाने खेल खेलेगी और जिस प्रकार आप को दिल्ली में समर्थन दिया है वैसे ही केंद्र में भी देगी और फिर एक भ्रष्ट सरकार देश को मिलेगी.

मनोज, *लखनऊ*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

बिहार नये समीकरण की ओर बढ़ रहा है

बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है. पिछले कई सालों से रामविलास पासवान और लालू यादव की पार्टी एक-दूसरे के साथ खड़ी थी और उनका गठबंधन था. लालू यादव के जेल जाने के बाद भी रामविलास पासवान लालू यादव के साथ खड़े रहे. जेल से जो भी लोग लालू यादव से मिलकर लौटते थे, वे यह बताते थे कि लालू यादव रामविलास पासवान को लेकर बहुत संतुष्ट नहीं हैं. उन्हें ये लगता है कि लोकसभा चुनावों में रामविलास की सीटों के बारे में शायद फिर सोचना पड़ सकता है. दरअसल, पिछले लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी. पर उसके उम्मीदवारों ने कुछ जगहों पर अच्छा प्रदर्शन किया था.

लालू यादव अपने को शायद मुसीबत में घिरा हुआ देख रहे हैं. अगले ग्यारह साल तक वो ख़ुद चुनाव नहीं लड़ सकते. और जिस तरह के संकेत देश के लोग दे रहे हैं, इससे यह लगता है कि परिवार को भी लोग अब शायद ज्यादा पसंद न करें. लालू यादव जी के परिवार में तीन लोग हैं जो लोकसभा में पहुंचकर लालू जी की जगह संभाल सकते हैं. पहली ख़ुद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो बिहार की मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी रहीं. दूसरे उनके पुत्र तेजस्वी और तीसरी उनकी बड़ी बेटी मिसा. समाचार निकल के आते हैं कि लालू के दोनों बेटों-तेजस्वी और तेजप्रताप में कुछ प्रतिस्पर्धा है. राष्ट्रीय जनता दल में या किसी भी पार्टी में परिवार के अलावा कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता. माहौल ऐसा है कि सबसे बड़े नेता को हमेशा यह डर बना रहता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन गया तो वो उनकी रातनीति पर विराम लगा सकता है. अपनी इसी परेशानी में लालू यादव बिहार में अपने को पुन: प्रतिष्ठित करना चाहते हैं. इस प्रक्रिया में वो पार्टी के इन नेताओं से अपने पूरे जेल प्रवास के दौरान बातचीत करते रहे. ये बातचीत गुप्त नहीं रह गई और रामविलास पासवान के पास ये सारी ख़बरें पहुंचने लगीं. सबसे आख़िर में रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रेस के सामने यह कहा कि रामविलास पासवान की सीटें तभी तय होंगी, जब वे अपने उम्मीदवारों का नाम बताएंगे.

सारे समाचारों से बौखलाए रामविलास पासवान को ये सबसे अपमानजनक लगा. यहीं से उन्होंने बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर अकेले जाने का फ़ैसला लिया. लालू यादव ये भूल गए कि लालू यादव और रामविलास पासवान का मेल सिर्फ़ सीटों के लिए नहीं है, बल्कि ये मेल पिछड़े और दलित की एकता का संकेत भी है. लालू यादव संपूर्ण पिछड़े वर्ग के नेता नहीं रह गए हैं. अति पिछड़े नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं. इसी तरह रामविलास पासवान भी संपूर्ण दलितों के नेता नहीं रह गए हैं. उनके साथ रहा एक बड़ा वर्ग अब महादलित के नाम पर नीतीश कुमार के साथ चला गया है. लेकिन इसके बावजूद पिछड़े नेताओं में सबसे बड़ा क़द लालू यादव का है. इसके बाद नीतीश कुमार सहित तमाम नेता आते हैं. दलितों में तो निर्विवाद रूप से रामविलास पासवान का सबसे बड़ा क़द बिहार में है ही. इस चीज़ पर बिना ध्यान दिए सीटों को लेकर खींचतान की वजह से लालू यादव ने अपना और रामविलास पासवान का रिश्ता यानी पिछड़ों और दलितों का रिश्ता तोड़ने की शुरुआत कर दी.

यहीं पर नीतीश कुमार का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने रामविलास पासवान से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया. उन्होंने रामविलास पासवान के प्रति अपनी आतुरता बिल्कुल नहीं छिपाई. उन्होंने कहा कि अगर रामविलास पासवान उनके साथ आते हैं, तो रामविलास पासवान के साथ सीटों के बंटवारे की समस्या नहीं आएगी. वे रामविलास का साथ वैचारिक आधार पर भी और रणनीति के आधार पर भी लेना चाहते थे. रामविलास पासवान पर एक तरफ राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम बड़े नेता डोरे डाल रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग रामविलास पासवान के साथ समझौता करने की बात कर रहे थे. रामविलास का यह कहना था कि हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लालू यादव को साथ लेकर कैसे लड़ सकते हैं. अगर राहुल गांधी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अध्यादेश, जो क़ानून बनने वाला था, की प्रति सार्वजनिक रूप से फाड़ सकते हैं, तो फिर कांग्रेस लालू यादव को लेकर देश में कैसे घूम सकती है. हालांकि, लालू यादव पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है. निचली अदालत में मुक़दमा चल रहा है. हमारे देश में जबतक सुप्रीम कोर्ट आख़िरी फ़ैसला न दे दे, फ़ैसला नहीं माना जाता. कांग्रेस के जो लोग रामविलास पासवान से मिलते थे, उनमें कुछ सिर्फ़ कांग्रेस और रामविलास पासवान के गठजोड़ की बात करते थे और कुछ रामविलास पासवान, लालू यादव और कांग्रेस के गठजोड़ की बात करते थे. यहीं से शायद रामविलास पासवान को ये लगा होगा कि कांग्रेस में ख़ुद ही एका नहीं है, तो ये रास्ता वैसा ही गड़बड़ है, जैसा लालू यादव के साथ जाने में.

रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार से वैचारिक मुद्‌दों पर भी बातचीत करने की बात की और नीतीश कुमार ने तत्काल इन सवालों का सकारात्मक जवाब रामविलास पासवान को दिया. रामविलास पासवान को ये डर था कि नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच अगर कोई मतभेद हैं, जिस तरह की ख़बरें जदयू के नेता समय-समय पर बाहर निकालते रहते हैं तो इनका यह सारा प्रयास व्यर्थ जा सकता है. इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पहल कर शरद यादव से भी संपर्क स्थापित किया. और इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत में जदयू के महासचिव केसी त्यागी सामने आए, जिन्होंने एक तरफ नीतीश कुमार को नये समीकरण की संभावनाओं के लिए तैयार किया और दूसरी ओर शरद यादव को उन्होंने इस गठबंधन के भविष्य के फ़ायदे समझाए. दरअसल, केसी त्यागी का ये मानना है कि रामविलास पासवान देश में दलितों का सौम्य चेहरा है जो आक्रामक भी हो सकता है, लेकिन रामविलास पासवान का एक चेहरा ऐसा भी है जो दलितों के अलावा ग़ैर-दलितों को भी पसंद आता है. और रामविलास उनसे बातचीत में कभी भी फैनेटिसिज्म नहीं दिखाते हैं. इसलिए रामविलास पासवान भविष्य के एक बड़े सहयोगी हो सकते हैं.

बिहार में रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ़ लालू यादव हैं और तीसरी तरफ़ कांग्रेस है. कांग्रेस अभी तक इस दुविधा में है कि वो बिहार में करे तो क्या करे. ये कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वह चुनाव से पहले कभी नहीं सोचती कि उसे राज्यों के संगठन को चुस्त-दुरुस्त भी करना है या संगठन को गतिशील बनाना है. जब चुनाव आता है तो कांग्रेस की कॉस्मेटिक सर्जरी शुरू होती है और कांग्रेस की इस रणनीति ने या कांग्रेस की इस काहिली ने कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को मायूस कर दिया है. बिहार में लोकसभा चुनाव में एक नई चुनौती खड़ी हो रही है और वो नई चुनौती आम आदमी पार्टी की है. बिहार में आम आदमी पार्टी अन्ना की पार्टी कही जाती है. बिहार में मैंने जितने लोगों से फोन पर बात की, सबका यही मानना है कि दिल्ली में अन्ना की सरकार बन गई है. इस भ्रम के बावजूद अरविंद केजरीवाल के प्रति पार्टियों से बाहर के लोग एक स्वाभाविक आकर्षण में बंध गए हैं और ये आकर्षण जहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण है, वहीं लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के लिए भी चिंता का कारण हो सकता है. बिहार को टेस्ट केस इसलिए मान रहे हैं, क्योंकि अभी-अभी बिहार में बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटा है. इसके बाद नीतीश कुमार घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं. उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है. लेकिन वो भीड़ कितनी कन्सॉलिडेट हो रही है, यह अभी नहीं कहा जा सकता. ऐसे समय रामविलास पासवान और नीतीश कुमार का मिलना बिहार में एक तरह का संकेत है तो दूसरी तरह का संकेत वहां पर आम आदमी पार्टी के नाम पर लड़ने वाले लोगों का भी है. पर आम आदमी पार्टी की विडंबना ये है कि वो कितनी जगहों पर नये लोगों को खड़ा करेगी, यह नहीं कहा जा सकता है. वहां पर बीजेपी, कांग्रेस छोड़कर आने वालों की तादाद बढ़ रही है. बल्कि कहें कि हर जगह बढ़ रही है और वो सब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. दिल्ली में जीत के पीछे एक सबसे बड़ा कारण खाली स्लेट थी. ऐसे उम्मीदवार लड़े, जिनका कोई इतिहास नहीं रहा. लोगों ने उन्हें समर्थन दिया और विधायक बनाया. पर जिनके बारे में लोग जानते हैं, अगर वो अच्छे लोग नहीं हैं, साख़ वाले लोग नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह से जनता का समर्थन मिलेगा, अभी नहीं कह सकते. बिहार शायद नये समीकरणों की ओर बढ़ने वाला पहला प्रदेश बन रहा है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राजनीतिक बदलाव का वर्ष

साल 2014 में दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे. क्या कांग्रेस इतनी भरपाई कर पाएगी कि वह कम से कम एक सम्मानजनक हार का सामना करेगी और तीन अंकों तक अपनी सीट पहुंचा पाएगी या फिर वह 80 सीटों से भी कम पर सिमट कर रह जाएगी? दूसरा सवाल यह हैं कि क्या आम आदमी पार्टी राजनीति में टिक पाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन पाएगी?

प्रणब मुखर्जी जब भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे, उस समय उन्होंने कहा था कि 13 का अंक भारत के लिए दुर्भाग्यशाली नहीं है. हालांकि, ऐसे लोगों की संख्या कम ही है जिनके लिए वर्ष 2013 का अंत देखना सुखद होगा. राजनीतिक दृष्टि से बीता वर्ष कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है. किसे याद होगा कि बीती जनवरी में राहुल गांधी ने नाटकीय रूप से अपनी मां के हाथों राजनीति का ज़हरीला पात्र लिया था और अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया था. वे उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे और उन्होंने कहा था कि उनकी मां ने उन्हें बताया कि राजनीति ज़हर है. उस समय भाजपा के सामने यह चुनौती खड़ी हो गई थी कि वह किसी ऐसे नेता की तलाश करे जो राहुल की तरह युवाओं की पसंद बन सके .

अब जबकि साल के आख़िरी समय में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो परिप्रेक्ष्य कुछ अलग तरीक़े का दिखाई पड़ता है. शुरुआत में तो कांग्रेस पीएम प्रत्याशी का नाम घोषित करने को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रही थी. उनके पास पीएम पद का प्रत्याशी चुनने का अपना एक अनोखा तरीक़ा है. लेकिन पीएम प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए सारे अनुमान काफ़ी ग़लत साबित हुए. यह वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक ग़लत अनुमान था. समय बीतने के साथ ही बीते 8 दिसंबर को कांग्रेस को बहुत भयावह परिणामों का सामना करना पड़ा.

राजनीति में अब बहुत बड़ा बदलाव आया है. न सिर्फ़ नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक ज्ञानियों के सारे अनुमानों को बदल कर रख दिया, बल्कि सम्मान की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे निकले जिन्होंने मतदाताओं को सबसे अच्छे ढंग से सुना. मंडल की राजनीति का ज़माना अब निकल गया है अब मतदाता पहचान की राजनीति को तरज़ीह दे रहे हैं. अरविंद केजरीवाल और मंडल के बाद की राजनीति क्षेत्रीय पार्टियों को चेतावनी दे रहे हैं जो तीसरा मोर्चा बनाने का सपना पाले हुए हैं.

साल 2014 में दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे. क्या कांग्रेस इतनी भरपाई कर पाएगी कि वह कम से कम एक सम्मानजनक हार का सामना करेगी और तीन अंकों तक अपनी सीट पहुंचा पाएगी या फिर वह 80 सीटों से भी कम पर सिमट कर रह जाएगी? दूसरा सवाल यह है कि क्या आप पार्टी राजनीति में टिक पाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन पाएगी. क्या वह कांग्रेस और वाम दलों को धकेलकर देश की दूसरी बड़ी पार्टी बन जाएगी?

हालांकि, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है लेकिन जितना ही ज्यादा वह लड़ती है, हास्यास्पद रूप से उसे उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि उसने कितनी देर कर दी है. दो वर्ष पूर्व राहुल गांधी नियमागिरी गए थे जहां उन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही थी. इससे कांग्रेसी मंत्रियों को इस बात के स्पष्ट संकेत मिल गए थे कि आदिवासियों और पर्यावरण के बचाव में सभी खनन और ढांचागत निवेश को रोकना होगा. अपने एक भाषण के दौरान दो साल पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि संविधान संशोधन करके लोकपाल बिल बनना चाहिए. उनका यह भाषण एक गेम चेंजर की तरह साबित हुआ और आख़िरकार कांग्रेस गेम हार ही गई. अब राहुल उसी राजनीति को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, जिसे लेकर वे कुछ समय पहले काफ़ी परेशान हो गए थे. हालांकि, उनकी राजनीतिक खोज में अभी तक दो साल बर्बाद हो चुके हैं.

हमें यह बताया गया था कि कांग्रेस राहुल गांधी को अपना पीएम प्रत्याशी घोषित करेगी. आश्चर्यजनक बात है! पार्टी को यह बात महसूस हो जानी चाहिए कि उसके पास एक मात्र चुनावी संपत्ति सोनिया गांधी ही हैं. राहुल गांधी को प्रचार अभियानों में शामिल होकर अधिक से अधिक अपनी मां की मदद करनी चाहिए. वह चाहें तो भारत दर्शन यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें शांत रहना चाहिए. यह एकमात्र उपाय है जिससे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में तीन अंकों के आकड़े को छू सकेगी.

यह आप पार्टी ही है जो कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल कर भाजपा के विकल्प के रूप में उभर सकती है. यह पार्टी नई, आधुनिक और गैर-सांप्रदायिक है. इसकी नीतियां लोकलुभावन हैं, जिससे सरकारी ख़ज़ाने पर बोझ पड़ता है.

राजनीति में अब बहुत बड़ा बदलाव आया है. न सिर्फ़ नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक ज्ञानियों के सारे अनुमानों को बदल कर रख दिया, बल्कि सम्मान की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे निकले, जिन्होंने मतदाताओं को सबसे अच्छे ढंग से सुना. मंडल की राजनीति का ज़माना अब निकल गया है. अब मतदाता पहचान की राजनीति को तरज़ीह दे रहे हैं.

हमें यह देखना होगा कि राजनीतिक सच्चाइयों के साथ यह पार्टी कितने दिनों तक रह पाती है. लेकिन हाल में इसने कुछ ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं जिससे राजनीति की पुरानी अवधारणा टूटी है. एक पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का अस्तित्व बने रहने की कोई गारंटी नहीं है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, जब कांग्रेस 80 सीटों से भी कम सीट लेकर आए. ब्रिटेन में 1905 में लेबर पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर आई थी, लेकिन उसके बाद वह कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकी. इसके बाद लेबर पार्टी पूरी बीसवीं सदी में ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी रही.

भारत एक जवान देश है और इसे नई राजनीति चाहिए, जिसमें मतभेद कम हों, जो ज्यादा काम करना चाहती हो, जहां काम को अधिक महत्व दिया जाए. अब साल 2014 के चुनावों को देखना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो बीमार

द्वितीय अपील कैसे करें

चौथी दुनिया ब्यूरो

जब लोक सूचना अधिकारी आपके आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या आपको पूरी सूचना नहीं देता है, तब आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है, आप प्रथम अपील करते होंगे. प्रथम अपील का प्रारूप भी चौथी दुनिया में प्रकाशित किया जा चुका है. हम आपको केंद्रीय सूचना आयोग में ऑनलाइन अपील कैसे दर्ज कराते हैं, इसके बारे में भी बता चुके हैं. बहरहाल, प्रथम अपील के बाद भी अगर आपको संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है तो द्वितीय अपील करने की नौबत आती है. राज्य सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील राज्य सूचना आयोग और केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की जाती है. लेकिन आरटीआई आवेदक के लिए सबसे बड़ी परेशानी है द्वितीय अपील तैयार करना. दरअसल, द्वितीय अपील का प्रारूप बनाने का काम थोड़ा पेचीदा बना दिया गया है, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वैसे बता दें कि पहली अपील करने के 90 दिनों के अंदर अथवा पहली अपील के निर्णय आने की तिथि के 90 दिनों के अंदर आप दूसरी अपील दाख़िल कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी हर समस्या के समाधान के लिए आपके साथ है. इस अंक में हम आपके लिए द्वितीय अपील का एक प्रारूप प्रकाशित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

द्वितीय अपील का प्रारूप

सेवा में,
केंद्रीय/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
पता----------

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील.

क्रमांक वांछित सूचनाएं
आवेदक द्वारा भरी जाएं

1 आवेदक का नाम और पता.
2 (क) लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता, जिसके विरुद्ध अपील है.
(ख) आवेदन की तिथि.
(ग) लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की तिथि.
3 (क) प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता.
(ख) प्रथम अपील जमा करने की तिथि.
(ग) प्राप्त जवाब की तिथि.
4 जिन आदेशों के विरुद्ध अपील की जानी है, उनका विवरण.
5 अपील का संक्षिप्त विवरण.
6 लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नामंजूर किए जाने की दशा में आवेदन की तिथि और विषय वस्तु का विवरण.
7 आयोग से निवेदन या राहत.

लोक सूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क के तुरंत सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दें. साथ ही लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कानून की धारा 20(1) के तहत जुर्माना लगाएं और धारा 20(2) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश भी करें. आयोग से निवेदन है कि मैं इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूं. अत: मुझे सुनवाई की अग्रिम सूचना अवश्य दें.

8 अन्य कोई सूचना, जो अपील निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो.

मैं.....उपरोक्त अपील को दिनांक .....को सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है. इस अपील में प्रदान की गईं सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं.

संलग्नक सूची

1. आवेदन की प्रति. 2. शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति. 3. आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद की प्रति. 4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रति. 5. प्रथम अपील की प्रति. 6. प्रथम अपील को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद की प्रति. 7. प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रति. 8. द्वितीय अपील की प्रति को लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भेजे जाने का प्रमाण.

नाम---------
पता---------
स्थान---------
तिथि---------

नोट : द्वितीय अपील को डबल स्पेसिंग लाइन में बनाएं, यानी लाइनों के बीच दोगुनी जगह छोड़ें. द्वितीय अपील की एक-एक प्रति लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भेजें. द्वितीय अपील की दो प्रतियां सूचना आयोग में भेजें. साथ ही एक प्रति अपने पास रखें. ■

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
यह सप्ताह आपके लिए वित्तीय तौर पर मजबूत रहेगा. आपकी स्थिति इस सप्ताह काफी मजबूत रहेगी. आपके काम और कारोबार का असर कई लोगों पर पड़ेगा. आप लोगों को सामाजिक समस्याओं पर भी जागरूक करेंगे. आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. ध्यान रखें आप गिने-चुने लोगों से ही बात करें. आप प्रॉपर्टी या घर से जुड़े कोई भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी. इस सप्ताह आप उदास और तनाव भी महसूस कर सकते हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह आपको कोई भावुक समाचार सुनने को मिलेगा. अपने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से आप तनाव दूर कर सकेंगे. आप जिंदगी का नया नजरिया समझेंगे. वित्तीय हालत सुधरेगी और इस सप्ताह आप नये काम की भी शुरुआत करेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आप अपने पार्टनर के साथ एक-दूजे का साथ निभाने को लेकर कमिटमेंट कर सकते हैं. कुछ समय आप अकेले बिताएं. कुछ समझौते भी आपको इस सप्ताह करने पड़ सकते हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
यह सप्ताह आपके लिए ढेर सारी खुशियां और कुछ नई चुनौतियां लेकर आने वाला है. कुछ लोग, जो आपसे दूर हो गए हैं, उनसे आपको फिर से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा. किसी खास के साथ यात्रा करेंगे. जमीन-जायदाद से जुड़ा काम आपको फायदा पहुंचाएगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह कुछ आश्चर्यजनक उपहार मिलने वाला है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी. इस समय अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आने वाले समय में आपको अच्छा फायदा होगा. आप अपने किसी करीबी की वित्तीय मदद करेंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आप अपने वर्तमान पार्टनर के साथ थोड़ा सावधानी बरतें. आप कुछ तनाव में रहेंगे. आपको हालात को समझने की जरूरत है. प्रमोशन और पब्लिसिटी से जुड़े मामले में भी सावधान रहें. अपनी पदवी को संभालें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आपको किसी मामले में आखिरी मिनट पर अपने प्लान बदलने पड़ सकते हैं. आपका सामाजिक जीवन तेजी से बदलेगा. अपने खर्चे पर संयम बरतें. आपको अपने काम में सम्मान मिलेगा. अपने निर्णय स्वयं के विवेक से लेने होंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह न चाहते हुए भी आप किसी का दिल दुखाने वाले हैं. उन लोगों को धन्यवाद कहें, जो आपके साथ हर अच्छे-बुरे वक्त में खड़े रहते हैं. वित्तीय तौर पर इस सप्ताह आप मजबूत होंगे. आपका सकारात्मक व्यवहार आपके जीवन में खुशियां लाएगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
कुछ भी बोलने से पहले आप विचार करें. आप अपने परिवार के किसी समारोह में शिरकत कर सकते हैं. आप जमीन और रियल एस्टेट से जुड़े कुछ काम करेंगे. आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ नई खुशियां आने वाली हैं. आपको नये काम के लिए पैसे का प्रबंध करना पड़ सकता है. भावुक होकर कोई निर्णय न लें. अपने कुछ कार्य योजना भी तैयार रखें. आप घर और अन्य चीजों पर निवेश कर सकते हैं.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आप किसी भी स्थिति में अपना संयम न छोड़ें. वो वादे बिल्कुल न करें, जिसे आप पूरे नहीं कर सकते. कुछ नये आय के स्त्रोत बनेंगे. कुछ नई वित्तीय संभावानाएं आपके सामने आने वाली हैं.

csastrologer@gmail.com

ज़रा हट के

मुर्गी के इश्क में मुर्गा हुआ घायल

अभी तक आप प्यार के ढेरों अनोखे अंदाज देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में प्यार का एक अनोखा मामला सामने आया है, जो हट कर है. अलीराजपुर जिले के गांव ढेकाकुंड में एक आदमी अपनी मुर्गी को अपने छोटे भाई के मुर्गे के साथ इश्क लड़ाते देखकर आगबबुला हो गया. उसने मुर्गे को तीर से मारकर घायल कर दिया. इसके बाद मामला थाने पहुंच गया. पुलिस ने मुर्गा मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि जगलिया भील का मुर्गा घर से निकलकर दालान में दाना चुग रहा था. इसी दौरान उसके छोटे भाई ज्ञानसिंह भील की मुर्गी भी बाहर आ गई. मुर्गी को देख मुर्गा इश्क लड़ाने उसके पास जा पहुंचा. मुर्गे को अपनी मुर्गी के साथ चोंच लड़ाना ज्ञानसिंह को बेहद नागवार गुजरा. वह घर के अंदर से धनुष-तीर लेकर आया और मुर्गे पर वार कर दिया. तीर मुर्गे के शरीर के आर-पार हो गया. मुर्गा मालिक जगलिया भील को जब यह पता चला तो वह हैरान रह गया. वह तुरंत अपने घायल मुर्गे को लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा. पुलिस ने मुर्गे को पशु चिकित्सालय भेजा. डॉक्टरों ने तीर निकालने से पहले मुर्गे की हालत में सुधार होने का इंतजार किया. उनका कहना था कि अगर तीर तुरत शरीर से निकाल दिया जाता तो अधिक मात्रा में खून बहने से मुर्गे की मौत हो जाती. फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद मुर्गा स्वस्थ हो गया है. थाना प्रभारी आशाराम वर्मा ने बताया कि आरोपी ज्ञानसिंह भील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ■

सांप ने लगाई घर में आग

कई गांवों में ऐसे इलाके हैं, जहां सांप को मारने के बाद उसे जिंदा जलाने की परंपरा है. इसके पीछे लोगों ने अनेक कारण गिनाए हैं और उनकी सोच भी इस पर अलग-अलग है. गुस्से का आलम देखिए कि एक महिला सांप को जलाने के चक्कर में अपना सबकुछ जला बैठी. अमेरिका के टेक्सास में एक महिला ने घर में घुस आए सांप को जिंदा जलाने के चक्कर में अपना पूरा घर ही फूंक दिया. मौके पर पहुंचने वाली स्थानीय दमकलकर्मी टीम का कहना है कि महिला सांप को जलाकर मारना चाहती थी और इस चक्कर में उसने अपना पूरा घर ही जला कर खाक कर दिया. दरअसल, हुआ कुछ यूं कि इस महिला ने अपने घर में सांप देखा और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी. सांप में आग लग चुकी थी और वो इधर-उधर भागने लगा, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई. जिसके बाद ये महिला बुरी तरह घबरा गई और फिर उसने पुलिस की मदद लेने में ही भलाई समझी.

जन्नत में शतरंज खेलने के लिए की हत्या

आप बाजार या कहीं और जाने के लिए किसी न किसी को साथ लेकर ही जाते हैं. ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन चीन में घटी इसका घटना के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. शतरंज खेलने के शौकीन केवल पूर्व भारतीय नवाब ही नहीं थे, साम्यवादी चीन के लोग भी शतरंज के खेलने के शौकीन हैं, लेकिन चीन के शतरंज खिलाड़ी ने आत्महत्या करने से पहले अपने साथ शतरंज खेलने वाले पड़ोसी की भी हत्या कर दी, ताकि वह उसके साथ मरने के बाद जन्नत में भी खेल सके. 54 वर्षीय लिआओ ने आत्महत्या करने से पहले अपने 57 वर्षीय पड़ोसी की हत्या कर दी, ताकि मरने के बाद भी उसका खेल में साथ निभा सके.

लिआओ ने इसका खुलासा आत्महत्या पूर्व के अपने पत्र में किया है. पड़ोसी का शव उसकी मकान मालकिन को तब मिला, जब वह झेजिआंग प्रांत में स्थित मकान का किराया वसूलने के लिए पहुंची. पुलिस का कहना कि उन्होंने गला घोंटने का सबूत एकत्र कर लिया है और लिआओ का शव बगल के कमरे में मिला. उस कमरे से दो पत्र और कुछ दवाएं भी मिली. पारिवारिक झगड़े के कारण लिआओ ने आत्महत्या करने की ठानी और पड़ोसी की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि मौत के बाद उसे अकेलेपन का डर सता रहा था. मकान मालकिन ने लिआओ को अपने आप में खोया रहने वाला बताया. ■

भारत के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अनुबंध में साफ कहा जाता है कि कंपनी ने कोई एजेंट नहीं रखा है या कोई गलत बात नहीं की. अगर यह साबित हो जाता है कि इस अनुबंध का उल्लंघन हुआ है तो सौदा अपने–आप रद्द हो जाता है. सवाल यह उठता है कि अगर मामले की जांच चल रही है तो यह साबित कैसे हो सकता है?

रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ा

ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा

भारत सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा रद्द कर दिया है. इस सौदे को लेकर इटली में जांच चल रही थी और भारत की खुफिया एजेंसी सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही थी. सवाल उठ रहे हैं कि रिश्वतखोरी के लग रहे आरोपों के कारण अपने दामन पर लगने वाले संभावित दाग को देखते हुए कहीं सरकार ने इस सौदे को रद्द तो नहीं कर दिया?

राजीव रंजन

रिश्वतखोरी के आरोप में विवादास्पद ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा रद्द हो चुका है. रक्षा मंत्रालय ने एकपक्षीय तौर पर यह सौदा रद्द कर दिया है. भारत सरकार ने फिनमैकेनिका की सहयोगी कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड से 8 अक्टूबर, 2010 को 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए सौदा किया था. रक्षा मंत्रालय ने सौदा रद्द होने के पीछे ऑगस्टा वेस्टलैंड द्वारा विश्वासघात को कारण बताया है. सरकार का कहना है कि कंपनी ने विश्वसनीयता करार का उल्लंघन किया है. इस मामले में भारत के रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा है कि उन्हें ऑगस्टा वेस्टलैंड के इस इन्कार पर यकीन नहीं था कि उसने 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए सौदा अपने पक्ष में करने के लिए बड़े नेताओं को रिश्वत दी थी. हालांकि सरकार पर आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में यह सौदा रद्द कर दिया है. यह सौदा रद्द होने के बाद अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चला गया है. रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी या दलाली कोई नई बात नहीं है. ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार किसी रक्षा सौदे को रद्द किया गया हो या सौदा रद्द होने के बाद पहली बार कोई मामला अंतरराष्ट्रीय पंचाट में गया हो. इसके पहले भी कई मामले अंतरराष्ट्रीय पंचाट में गए हैं, लेकिन कई मामलों में नतीजे आ चुके हैं और कई मामलों में आने बाकी हैं. आपको यह जानकर हैरत होगी कि अंतरराष्ट्रीय पंचाट में कई मामले सालों तक चलते रहते हैं और उनके खर्च कुल सौदों से भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चलने वाले मामलों की प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है.

आर्बिट्रेशन आउटलेट्स कैंसिलेशन

इस मामले को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में जाना ही था. इसके लिए दोनों पक्षों के राजी होने की शर्त नहीं है. इसे ही कहते हैं आर्बिट्रेशन आउटलेट्स कैंसिलेशन. पंचाट में तीन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं. एक भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से, दूसरा अगस्ता वेस्टलैंड की ओर से और तीसरा आपसी सहमति से. अगर किसी व्यक्ति पर आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो फ्रांस में स्थित अंतरराष्ट्रीय पंचाट के मुख्यालय की ओर से सदस्य नियुक्त किया जाता है. अंतरराष्ट्रीय पंचाट में यह मामला वर्षों चल सकता है और उसका फैसला भारत और ऑगस्टा वेस्टलैंड पर बाध्यकारी होगा. इसीलिए यह तय है कि स्थिति अभी और ज़्यादा उलझेगी.

मुश्किल में सरकार

ऑगस्टा वेस्टलैंड से सौदा रद्द होना सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिन 12 हेलीकॉप्टरों का सौदा हुआ था, उनमें से तीन को भारत को सौंपा जा चुका है और उसके लिए करीब एक तिहाई कीमत भी चुकाई जा चुकी है. भारत ने 3600 करोड़ रुपये के 12 हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिनमें से तीन पहले ही मिल गए हैं, नौ आने बाकी थे. यह मामला इसलिए भी और ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि कंपनी इन हेलीकॉप्टरों को वापस लेगी नहीं और इंडियन एयरफोर्स इन्हें चला नहीं सकती, क्योंकि इन तीन हेलीकॉप्टरों को चलाने के लिए भी उसे कल–पुर्जे, सर्विसिंग और बैकअप चाहिए. ऐसे में यह इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बेहद मुश्किल सवाल होगा कि वह इन हेलीकॉप्टरों का क्या करे? इस सौदे के रद्द होने से भारत की साख पर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि यह सौदा अभी चल रहा था और इसमें पैसा दिया जाना बाकी था, साथ ही हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति अभी की जा रही थी. इसके अतिरिक्त भारत को अभी और भी बहुत हथियार खरीदने हैं तो असर लाजिमी है.

इसी के साथ यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि कहीं भारत सरकार ने इस सौदे को रद्द करने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्योंकि एक तरफ इटली में इस सौदे को लेकर जांच चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत की खुफिया जांच एजेंसी सीबीआई भी इसकी जांच कर रही थी. ऐसे में कहा जा रहा है कि इस सौदे को रद्द करने का निर्णय चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में लिया गया. विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से सरकार की हाल में भ्रष्टाचार को लेकर किरकिरी हुई है और हालिया चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, उसके कारण सरकार फूंक–फूंक कर कदम उठा रही है और सौदे को रद्द करना जनता को विश्वास में लेना है कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है, क्योंकि भले ही सौदों में भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी नहीं हुई हो, लेकिन जनता के बीच सरकार का रवैया इस तरह से हो गया है कि कहीं भ्रष्टाचार को लेकर कोई शंका भी जाहिर करता है, तो जनता यह मान बैठती है कि जरूर कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ किया होगा. हालांकि कंपनी की विश्व में जिस तरह की छवि है, उसे देखकर रिश्वतख–ोरी से इंकार नहीं किया जा सकता. ये भी हो सकता है कि रिश्वतखोरी के संभावित दाग को देखते हुए सरकार ने इस सौदे को पहले ही रद्द कर देना उचित समझा हो. खैर, मामला जो भी हो, आने वाले समय में पता चल जाएगा.

भारत का पक्ष

भारत के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जो अनुबंध किया जाता है, उसमें साफ कहा जाता है कि कंपनी ने कोई एजेंट नहीं रखा है या कोई गलत बात नहीं की. अगर यह साबित हो जाता है कि इस अनुबंध का उल्लंघन हुआ है तो सौदा अपने–आप रद्द हो जाता है. सवाल यह उठता है कि

अगर मामले की जांच चल रही है तो यह साबित कैसे हो सकता है? आरोप यह भी है कि सरकार द्वारा पिछले साल जून–जुलाई में इस सौदे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की घोषणा की गई, लेकिन न तो अभी तक कोई समिति बनी है और न ही उसके सदस्य तय हुए.

विपक्ष का सवाल

सूत्रों के अनुसार इटली की अदालत में दाखिल आर–ोप पत्र में कहा गया है कि भारत के किसी परिवार को हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में 200 करोड़ रुपये बतौर रिश्वत दिया गया है. इस सवाल पर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने पूछा है कि भारत का वह परिवार कौन है, जिसे 200 करोड़ की रिश्वत मिली है. पार्टी ने हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले की तहकीकात विशेष जांच दल से या उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग करते हुए भारत के एक परिवार को रिश्वत दिए जाने के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग की है.

फिनमैकेनिका का साम्राज्य

हेलीकॉप्टर घोटाले में फिनमैकेनिका नाम की कंपनी कठघरे में है. इस कंपनी का कारोबार दुनिया के सौ से ज्यादा देशों में फैला हुआ है. यह कंपनी सिर्फ हेलीकॉप्टर बेचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कई अलग–अलग सेक्टरों पर भी इस कंपनी ने कब्जा जमा रखा है. फिनमैकेनिका की सहयोगी कंपनियों ने भारत में कई सरकारी एजेंसियों से समझौता कर रखा है. हजारों करोड़ के अहम सरकारी ठेके इन सहयोगी कंपनियों के नाम हैं. कई ऐसे सेक्टर हैं, जिस पर तो पूरा कब्जा ही फिनमैकेनिका की सहयोगी कंपनियों सेलेक्स गैलीलियो, एनसाल्डो एसटीएस और ऑगस्टा वेस्टलैंड का है. ऑगस्टा वेस्टलैंड तो 1970 से ही भारत में कारोबार कर रही है. इसका टाटा संस के साथ इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड नाम से ज्वॉइंट वेंचर है. इसमें टाटा की 74 फीसद हिस–ेदारी है. इस ज्वॉइंट वेंचर के तहत एडब्लयू 119 हेलीकॉप्टर तैयार किया जाता है. कंपनी अब तक 40 ऐसे हेलीकॉप्टर बेच चुकी है. एडब्लयू 119 आठ सीटर हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल कॉरपोरेट घराने करते हैं. कई राज्य सरकारों को भी ये हेलीकॉप्टर बेचे जा चुके हैं.

पूर्व वायु सेनाध्यक्ष पर रिश्वत का आरोप

रक्षा सौदों में घोटालों को लेकर भारत के पूर्व वायु सेनाध्यक्ष एसपी त्यागी पर भी आरोप हैं. एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के सौदे में कंपनी फिनमैकेनिका ने त्यागी को रिश्वत दी थी. सूत्रों के मुताबिक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के नियमों में फेरबदल किया गया था. आरोप है कि करीब 3,600 करोड़ रुपये के सौदे को हथियाने के लिए भारत में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की रिश्वत बांटी गई.

कंपनी का अंदाज है निराला

इटली की कंपनी फिनमैकेनिका के काम करने का अंदाल भी निराला है. कहा जाता है कि फिनमैकेनिका की कार्य प्रणाली को समझना बहुत मुश्किल है. यह कंपनी विभिन्न देशों के मंत्रियों और सरकारी उच्चाधिकारियों को नौकरी देकर सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाती है और उसके बाद सिस्टम में सेंधमारी कर दलाली करवाती है. यह कंपनी ताकतवर और रसूखदार लोगों को रिटायरमेंट के बाद अपने यहां उच्च पदों पर रखती है. सवाल यह उठता है कि अगर कंपनी अपने यहां इन अधिकारियों को रखती है, तो उसका मकसद क्या हो सकता है? सूत्रों के मुताबिक डिफेंस डील की बारीकियां जानने वाले ये रसू–खदार लोग अपनी ऊंची पहुंच के जरिये ऑगस्टा वेस्टलैंड को कई रक्षा ठेके दिलवाए हैं. सवाल उठता है कि क्या फिनमैकेनिका भारत में भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही थी?

रिकॉर्ड खराब

ऑगस्टा वेस्टलैंड का नाम एक अन्य हेलीकॉप्टर विवाद में भी सामने आ रहा है. सूत्रों के अनुसार ऑगस्टा वेस्टलैंड ने दिल्ली पुलिस को हेलीकॉप्टरों और उसके कल–पुर्जों की आपूर्ति के सौदे के लिए एक कंपनी को कमीशन देने का प्रस्ताव भी दिया था. हालांकि यह सौदा नहीं हुआ. भ्रष्टाचार के मामले में कंपनी के सीईओ की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है. सीईओ के बाद अब ऑगस्टा–वेस्टलैंड के प्रमुख ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को भी नजरबंद कर दिया गया है. स्विट्जरलैंड पुलिस ने गुइडो राल्फ हाशके नामक 62 वर्षीय कंसल्टेंट को भी गिरफ्तार किया था. कंपनी की दलाली या येन–केन–प्रकारेण विभिन्न देशों की सरकारों से डील फाइनल कराने की प्रवृत्ति को देखते हुए ओबामा ने भी इस कंपनी से एक डील को रद्द कर दिया था. कंपनी जिस तरह से विभिन्न देशों के सरकारी अधिकारियों को अपने यहां वरिष्ठ पदों पर स्थापित करने का प्रलोभन देती है, उसे देखते हुए कंपनी की नीतियों और उसके नापाक इरादों पर सवाल उठना लाजिमी है. ■

क्या है ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदा

भारत के रक्षा मंत्रालय ने एंग्लो–इटैलियन हेलीकॉप्टर कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ 8 फरवरी, 2010 को 3600 करोड़ रुपये का अनुबंध किया था, जिसके तहत आला नेताओं व उच्चाधिकारियों की यात्रा सुरक्षा व सहजता के साथ संपन्न कराने की खातिर उच्च कीमत वाले 12 वीवीआईपी एडब्ल्यू–101 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे.

feedback@chauthiduniya.com

साई

माया से मुक्त होने का एक मात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल साई बाबा की शरण में जाना ही है. वेद-वेदांत भी मायारूपी सागर से पार नहीं उतार सकते. यह कार्य तो केवल सद्गुरु के द्वारा ही संभव है. समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर-दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है.

एक बार...

साई सबके आश्रयदाता हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा सभी भक्तों पर दया करते थे और साई समस्त प्राणियों के जीवन व आश्रयदाता थे. वे परमबह्म के पूर्ण अवतार थे. साई समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और भक्तों के आश्रयदाता थे. हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए. साई बाबा ने अनेक बार भक्तों को समझाया कि मैं, कौन है. इस मैं को ढूंढ़ने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है. तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंत:करण और समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं और यही मैं का स्वरूप है. ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो. यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी. भक्तों को हमेशा सभी देवी-देवताओं, संतों और भक्तों का सम्मान करना चाहिए. साई सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वह मेरे हृदय को दु:ख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है. इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है, वह मुझे अधिक प्रिय है. बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं. समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है. इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्त्रोत उनके मुख से सदैव झरता रहता था. अत: जो प्रेमपूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे या उन्हें भक्तिपूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साई से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी. जन-साधारण का ऐसा मानना है कि गंगा सागर में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है. ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है. सच्चिदानंद साई महाराज की जय हो. वे तो भक्तों के लिए काम कल्पतरु, दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं. साई की कथाओं के श्रवण से भक्तों की श्रद्धा जागृत हो जाती है. घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार साई की कथाओं से सार सिंधु से प्रकटित एक जल के कण से ही पाठकों और श्रोताओं का हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भर जाता है. आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल-पल पर रोमांच हो उठे, ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत हो जाए. पारस्परिक वैमनस्य, वर्ग-अपवर्ग का भेद-भाव नष्ट हो जाए. यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु-कृपा के लक्षण जानो. इन भावों को अंत:करण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे. माया से मुक्त होने का एक मात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल साई बाबा की शरण में जाना ही है. वेद-वेदांत भी मायारूपी सागर से पार नहीं उतार सकते. यह कार्य तो केवल सद्गुरु के द्वारा ही संभव है. समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर-दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है.

भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई. उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे. मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा, जिस दिन तुम ऐंद्रिक-विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे. कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए. उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई आसक्ति शेष न रही. वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. साई के चरणों का सानिध्य जिसे प्राप्त हुआ, वह धन्य हो गया.

इसी पर आधारित एक कहानी के बारे में आपको बताते हैं. सखाराम हरी उर्फ बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी बुवा विष्णु जोग के काका थे. वे सरकारी नौकरी करते थे. सेवानिवृत्ति के पश्चात वे शिरडी में आकर रहने लगे. उनकी कोई संतान न थी. पति और पत्नी दोनों की ही साई चरणों में श्रद्धा थी. वे दोनों पूरे दिन उनकी पूजा और सेवा करने में ही व्यतीत किया करते थे. मेघा (जोग की पत्नी) की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब जोग ने बाबा की महासमाधि, मस्जिद और चावड़ी में आरती की. उन्हें साठे बाड़ा में ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था. इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की कि-हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार. आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है. मैं इन श्री चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूं, लेकिन क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूं. मेरे इस जीवन में कौन-सा सुख है, यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बन कर आपके श्री चरणों में मग्न नहीं होता. क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी तब आएगी, जब आपकी मुझ पर कृपादृष्टि होगी.

भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई. उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे. मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा, जिस दिन तुम ऐंद्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे. कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए. उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई आसक्ति शेष न रही. वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. साई के चरणों का सानिध्य जिसे प्राप्त हुआ, वह धन्य हो गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

कर्म में विश्वास रखें

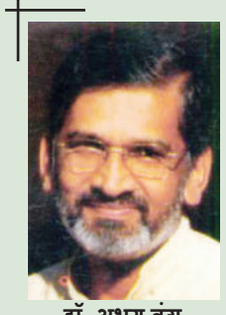

डॉ. अभय बंग

मेरे भीतर का लोभ, स्वार्थ कम करना, अनावश्यक जरूरतें कम करना, यह मेरे आध्यात्मिक विकास का आवश्यक भाग है तो फिर आज का समाज बदल कर अनुकूल समाज निर्माण करना, यह क्या उसी अध्यात्म का अविभाज्य सामाजिक आशय नहीं है? व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना क्या सामाजिक अध्यात्म के उत्तरदायित्व से निर्लिप्त रह सकती है? ऑर्निश की उपचार-पद्धति सामाजिक विषय में मौन थी. महात्मा गांधी का अद्वितीय स्वरूप यहां समझ में आया. व्यक्तिगत शुद्धि के लिए उन्होंने जो एकादश व्रत स्वीकार किए (उनमें से अधिकांश भारतीय यम-नियम से लिए गए हैं), शोध ग्राम में शाम की प्रार्थना में रोज हम उनका स्मरण करते हैं. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र, भयवर्जन, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी, स्पर्श भावना, विनम्र व्रत निष्ठा से यह एकादश व्रत सेव्य हैं, लेकिन इसका एक व्रत बड़ा कठिन है. उसका आचरण मुझे करना हो तो समाज उसके अनुकूल होना चाहिए. असंग्रह का यह व्रत और आज का अधिक कमाओ, अधिक खरीदो की स्पर्धा, ये दोनों कैसे साथ चल सकते हैं? ईशवरोपनिषद में बताए गए महासंदेश के ठीक विपरीत आज का समाज चल रहा है.

ईशवास्या कहता है, उसके नाम से त्यागकर, तू यथा प्राप्त भोगता जा. किसी के भी धन की वासना मत रख.

आज का समाज कहता है, ज्यादा कमाओ, लोभ करो, दूसरे की धन-सम्पदा के प्रति खूब ईर्ष्या रखो और उसे पाने के लिए खूब प्रयत्न और उठा-पटक करो.

इहलोक में कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा रखो. जब तक संभव हो तब तक काम न करते हुए, आराम करने व भोग करने की इच्छा रखो. कर्म नहीं फल की वासना मनुष्य से चिपक जाती है.

फल के लिए ही तो कर्म करना चाहिए. जितनी अधिक फल की वासना, उतना अधिक कर्म. उसके लिए व्यक्ति की फल-वासना में तेल डालकर उसे खूब भड़काओ.

आज के समाज के मूल्य ईशावास्य विरोधी हैं. ईशावास्य यदि सही है, तो आज के समाज के मूल्य मनुष्य को सुखी नहीं कर सकेंगे. यह महासत्य है.

यदि मुझे हृदय रोग से मरना नहीं है तो कैसी समाज रचना होनी चाहिए? वैसा समाज कौन लाएगा? मेरे सामने इसका अर्थ स्पष्ट होने लगा.

मुझे मीठे, तले हुए पदार्थ अथवा दूध-घी युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए. मैदे से बनी हुई वस्तुएं नहीं खानी चाहिए. फायबररहित वस्तुएं नहीं खानी चाहिए. यानी कि आज ब्रेड, बिस्किट चॉकलेट-आईसक्रीम से लेकर मिठाई, मक्खन, इतना ही नहीं पकौड़े समोसे और पूरी ये सब मेरे भोजन में नहीं होने

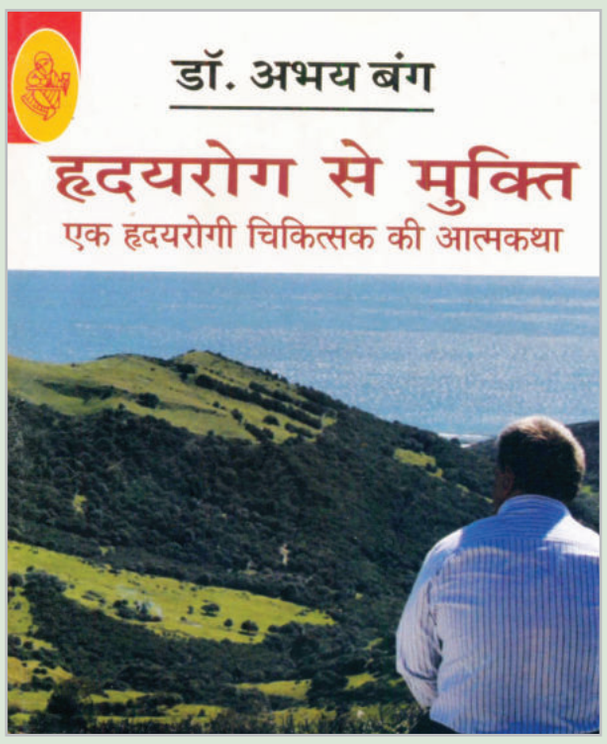

चाहिए. इसका अर्थ यह हुआ कि ये सब बनाने वाले डेयरी उद्योग, बेकरी उद्योग, फ्रूड प्रोसेसिंग उद्योग एवं होटल उद्योग इन सब उद्योगों को अपने-अपने व्यवसाय में खूब बदलाव लाना चाहिए. विज्ञापनों की दुनिया की दिशा पूरी तरह बदलकर बिक्री के लिए माल के प्रमोट करने की जगह आरोग्य प्रमोट करना चाहिए. इसके अलावा, तंबाकू, गुटका, बीड़ी-सिगरेट, शराब इनका प्रभुत्व तो घर-घर में, चौक-चौराहे से लेकर टीवी द्वारा पूरी दुनिया पर छाया हुआ है. यह भी बदलना चाहिए. पैदल चलने की आदत के विरोधी कार, स्कूटर, लिफ्ट, एसक्लेटर का निर्माण करने वाले उद्योग तथा निष्क्रिय मनोरंजन को प्रोत्साहन देने वाले टीवी मनोरंजन उद्योग को बदलना चाहिए.

उपभोग करो यह संदेश बदलना चाहिए. खरीदो और आराम करो यह संदेश बदलने चाहिए. अधिक कमाओ, अधिक जमाओ, अधिक खाओ, पिओ, मजा करो, यह बदलना चाहिए, पैसा, सत्ता, मान, प्रसिद्ध पद, प्रमोशन के लिए चाहे जो करो. ऐसे संस्कार एवं प्रोत्साहन ही नहीं, अपितु इनके पीछे दौड़ाने के लिए चाबुक इस्तेमाल करने वाली समाज-व्यवस्था भी मेरे लिए घातक है.

गरीबी से भूख एवं कुपोषण का निर्माण होता है. गरीब स्त्री का आहार कम होने से उसके बच्चे भी गर्भावस्था में कुपोषित होकर कम वजन के पैदा होते हैं. भारत के करीब 35 प्रतिशत बच्चे ढाई किलो से कम वजन के, अर्थात लो बर्थ वेट या गर्भ-कुपोषित पैदा होते हैं. ऐसे बच्चों को बड़े होकर हृदय रोग होने का खतरा कई गुना अधिक होता है. अर्थात गरीबी, कुपोषण एवं स्त्री को आधा पेट रखने वाली जीवन की सब बातें हृदय रोग कारक हैं. इन सबको बदलना होगा. स्वार्थी, अकेला, दूसरों से कटा हुआ मनुष्य हृदयरोग से मरता है. दूसरों से नाता जोड़ना यदि जीवन के लिए आवश्यक है, तो ईर्ष्या और स्वार्थ को भड़काकर दूसरों से नाता तोड़नेवाली मुक्त अर्थव्यवस्था जीवन के लिए घातक ही कही जाएगी. व्यक्तिवाद का भोंपू बजाने के बदले ओम सहनाववतु, सहनौभुनक्तू, सहवीर्यं कर्वावहै, यह सबके साथ नाता जोड़ने वाला सामूहिकता का दर्शन जीवन के अनुकूल है. मनुष्य को स्वार्थ का, अकेलेपन का पिंजरा नहीं चाहिए-चाहे उसे व्यक्ति स्वातंत्र्य अथवा मुक्त अर्थव्यवस्था जैसे आकर्षक नाम क्यों न हों. अर्थव्यवस्था को नहीं मानव को मुक्त होना चाहिए.

मेरे हार्ट अटैक और उसके बाद के नव-जीवन का एक वर्ष पूरा हुआ. मेरे हृदय रोग के अनुभव एवं उपचार लोगों के लिए उपयोगी हैं. यह बात मेरी समझ में आई. असंख्य लोग मेरे जैसे बीमार हैं अथवा गलत राह पर चल रहें हैं. यह सब मेरे सह-रोगी हैं. उन्हें मेरे अनुभवों से कैसे मिल सकती है? मेरे सहयोगी कैसे बन सकते हैं? तीन वर्ष पूर्व मैं जिस संकट से गुजरा, वह मात्र व्यक्तिगत अनुभव न होकर दिन-पर-दिन एक बड़ा और व्यापक प्रश्न बनता जा रहा है. असंक्रामक रोग, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्त चाप, मोटापा-ये भारत में एक महामारी के रूप में फैल चुके हैं. भारतीय समाज को रोग के इस ज्वार का सामना करना उसे हर संभव तरीके से टालना व उसका उपचार करना सीखना ही होगा. आज की जीवनशैली में बदलाव लाकर हमें ऐसी जीवनशैली अपनानी होगी, जो हृदयरोग को नकार सके, जो सामाजिक रिश्तों एवं पर्यावरण दोनों से सुसंवादी हो, जो मानसिक तनाव से मुक्त हो और आध्यात्मिक हो. 21वीं सदी में यही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती है. शोधग्राम में हम ऐसी धीरे-धीरे ऐसी जीवन-पद्धति अपनाने का प्रयत्न करने लगे. आदिवासियों के बीच रोगियों का उपचार व रोग निर्मूलन पर अनुसंधान करते हुए स्वयं भी निरोगी एवं आनंदमय जीवन जीने का मार्ग खोजने लगा. मेरा कर्मक्षेत्र व धर्मक्षेत्र एक हो गए थे. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

सुख की तलाश

चांदपुर इलाक़े के राजा कुंवर सिंह जी बड़े अमीर थे. उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था. बीमारी के कारण वह हमेशा परेशान रहते थे. कई वैद्यों ने उनका इलाज़ किया, लेकिन उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. राजा की बीमारी बढ़ती गई. सारे नगर में यह बात फैल गई. तब एक बूढ़े व्यक्ति ने राजा के पास आकर कहा कि महाराज, आप अपनी बीमारी का इलाज़ करने की मुझे आज्ञा दीजिए.

राजा ने उसे अनुमति दे दी. तब उस व्यक्ति ने कहा, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे. बूढ़े की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन राजा ने सोचा, इतने इलाज़ कराएं हैं तो एक और सही. राजा के सेवकों ने सुखी मनुष्य की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला. सभी लोगों को किसी न किसी बात का दुख था. अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े. बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे. जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था. राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान की आंखें चमक उठी, चेहरा मुस्करा उठा. वह बोला, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है. यह सुनकर राजा का अंग-अंग मुस्करा उठा. उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ़ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है. राजा समझ गया कि श्रम करने के कारण ही यह किसान सच्चा सुखी है. उन्होंने आराम-चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया. थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई.

शिक्षा-परिश्रम ही सभी दुखों का हल है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

> हम हिंदी साहित्य के लोग भूमंडलीकरण, फासीवाद, बाज़ारवाद, वैश्वीकरण आदि आदि शब्दों से आक्रांत होने की सीमा तक भयभीत दिखते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं. भयाक्रांत दिखने की ये प्रवृत्ति हमें पलायनवादी तर्क गढ़ने के लिए मजबूर करती है.

साहित्य पत्रिकाओं की सार्थकता

अनंत विजय

यदा-कदा साहित्यिक आयोजनों और विचार गोष्ठियों में जाने-बोलने का अवसर मिलता है. ज्यादातर गोष्ठियों में वामपंथी विचारधारा के अनुयायी या उनसे जुड़े लेखकों का ही जमावड़ा रहता है. उन गोष्ठियों में अमूमन भूमंडलीकरण के आसन्न ख़तरे से लेकर सांप्रदायिकता, फासीवाद और बाज़ारवाद के बढ़ते प्रभाव को लेकर छाती कूटी जाती है. ये सिलसिला लंबे समय से देख रहा हूं, ठीक उसी तरह जैसे दो दशक पहले जब मैं पत्रकारिता में आया था तो उस वक्त सुना था कि हिंदी पत्रकारिता चौराहे पर खड़ी है. अब भी पत्रकारिता की गोष्ठियों में बहुधा ये सुनने को मिलता है कि पत्रकारिता चौराहे पर खड़ी है. इसी तरह साहित्य में दशकों से फासीवाद का रोना और नब्बे के दशक के बाद बाज़ारबाद का ख़तरा सिर उठाए खड़ा है. पता नहीं कब तक ये ख़तरा खड़ा ही रहेगा, कब ये आगे बढ़कर ख़तरनाक होगा. दरअसल, हम हिंदी साहित्य के लोग भूमंडलीकरण, फासीवाद, बाज़ारवाद, वैश्वीकरण आदि-आदि शब्दों से आक्रांत होने की सीमा तक भयभीत दिखते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं. भयाक्रांत दिखने की ये प्रवृत्ति हमें पलायनवादी तर्क गढ़ने के लिए मजबूर करती है. भूमंडलीकरण का भय दिखाकर और बाज़ारवाद का हौवा खड़ा करके साहित्य में कुछ लोगों की दुकानदारी चल रही है. वैसे ही लोग और लेखक फासीवाद, बाज़ारवाद, भूमंडलीकरण आदि आदि का ख़तरा बनाकर रखना चाहते हैं. प्रतिरोध की विचारधारा की बुनियाद पर लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत हुई थी और बाद में इसे असंगठित पूंजी से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिकाएं घोषित किया गया. लंबे समय तक लघु पत्रिका आंदोलन चला, अब भी कुछ पत्रिकाएं गंभीरता से लघु पत्रिका धर्म का निर्वाह करते हुए निकल रही हैं. लेकिन अगर लघु पत्रिकाओं की भीड़ पर नज़र डालेंगे तो एक बहुत ही महीन लकीर आपको दिखाई देगी, जिसे रेखांकित करना आवश्यक है, क्योंकि वो प्रतिरोध के नाम पर फ़ायदा उठाने की जुगत भर है.

पहले रचनाकारों और उनके अवदानों को केंद्र में रखकर विशेषांक निकालने की प्रवृत्ति थी, जो किसी ख़ास मौक़े या अवसर पर प्रकाशित होते थे. हाल के दिनों में मुझे कई ऐसी लघु पत्रिकाएं मिलीं, जो विषय विशेष को केंद्र में रखकर निकाली गई हैं. जैसे लिव इन रिलेशनशिप की कहानियों का विशेषांक, पुरुष विमर्श विशेषांक, स्त्री मन की कहानियां, प्रेम में धोखा विशेषांक आदि-आदि. पहली नज़र में तो यह काम महत्वपूर्ण लगता है और ये भी आभास होता है कि पक्षिका निकालने वालों की मंशा पाठकों को विषय विशेष पर विभिन्न रचनाकारों की रचनाएं इकट्ठा कर देने की हैं. बाद के दिनों में जब उन्हीं विषयों पर किताबें दिखाई दीं तो मैं चौंका. पड़ताल करने पर पता चला कि यह सब एक रणनीति के तहत किया जाता है. पहले पत्रिका निकालो और फिर किताब बनाकर बाज़ार में बेचो. अब यहीं से सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं. बाज़ार को दिन रात कोसने वाले लोग बाज़ार का फ़ायदा उठाने में जुटे हैं. चलो एक मिनट को इसको दरकिनार कर भी दिया जाए तो इससे पाठकों का कैसे भला हो सकता है. पहले पचास रुपये में पत्रिका बेची फिर दो-ढाई सौ रुपये में किताब. इस तरह के विशेषांकों के केंद्र में अगर पाठक हैं तो फिर पत्रिका को किताब बनाकर बेचने का छल क्यों? और अगर बाज़ार को भुनाने और मुनाफ़ा कमाने की दबी हुई आकांक्षा है तो फिर बाज़ार को गलियाने का क्या फ़ायदा? इन विचारधारा वीर लेखकों को सोचना चाहिए कि इस आधुनिक युग में चेहरे का मुखौटा हटते देर नहीं लगती और न ही विलंब होता है, दोहरे चरित्र को उजागर होने में.

इन सबके बीच कुछ सरकारी, गैर-सरकारी और व्यक्तिगत प्रयासों से साहित्यिक पत्रिकाएं निकल रही हैं. अभी हाल में मुझे कई साहित्यिक पत्रिकाएं देखने-पढ़ने का मौक़ा मिला. जब से दिल्ली के श्रीराम सेंटर स्थित किताबों की दुकान बंद हुई है, तब से साहित्यिक पत्रिकाओं को देखने, पलटने और ख़रीदने का अवसर भी ख़त्म हो गया है. इस बीच मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट के सामने पटरी पर तीन पत्र-पत्रिकाओं की दुकान सजती है. इन दुकानों को मैं नब्बे के शुरुआती दशक से देख रहा हूं जब मयूर विहार में रहा करता था. उनसे थोड़ी जान-पहचान भी है. दफ्तर जाते वक्त उधर से एक चक्कर इस लालच में लगाता हूं कि कोई साहित्यिक पत्रिका मिल जाए. कई बार मिल भी जाती है और कई बार निराश होना पड़ता है. इसके अलावा कुछ कृपालु संपादक अपनी पत्रिकाएं भेज देते हैं. मयूर विहार के ही स्टॉल पर द पब्लिक एजेंडा का साहित्य विशेषांक मिला. हालांकि, ये पिछले साल का नवंबर का अंक है, लेकिन मुझे दिसंबर के दूसरे हफ्ते में दिखा. इस पत्रिका के कार्यकारी संपादक हिंदी के वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल हैं और सहयोगी संपादक मशहूर कवि मदन कश्यप हैं. दो वरिष्ठ कवियों की मेहनत इस अंक में दिखाई दे रही है. इसमें ग्लोबल समय में साहित्य विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है. बाज़ारवाद, नवउदारवाद आदि-आदि पर विश्वनाथ त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, विमल थोराट और प्रणय कृष्ण के विचार संकलित किए गए हैं. इस बहस का दायरा बढ़ाने से एक मुकम्मल तस्वीर बनती. इस अंक में वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ कवियों की कविताएं प्रकाशित हैं. संयज कुंदन और अनिमेष की कविताओं के अलावा युवा कवियों की कविता प्रभावित नहीं करती हैं. लीलाधर मंडलोई अच्छे कवि हैं, लेकिन इस अंक की कविताओं ने निराश किया. पूर्व सांसद और लेखक जाबिर हुसेन के संपादन में पिछले सात वर्षों से दोआबा का प्रकाशन हो रहा है. दोआबा एक गंभीर पत्रिका के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है. जाबिर साहब ख़ुद संजीदा लेखक हैं. दोआबा के इस अंक में जाबिर साहब ने अपने गुरु का क़र्ज़ उतारा है और उनसे संस्मरण लिखवाए हैं. उनके शिक्षक महताब अली का संस्मरणात्मक आत्मकथ्य रोचक है और उससे इतिहास की तस्वीर और गाढ़ी होती है. इसके अलावा भी इस अंक में गंभीर पाठकों के लिए काफ़ी कुछ है, जिससे साहित्य का आस्वादन संभव है.

पंकज बिष्ट के संपादन में लंबे समय से समयांतर पत्रिका निकल रही है. इसके कई अंक पंकज बिष्ट की तीखी संपादकीय टिप्पणियों से चर्चित होते रहे हैं. पंकज बिष्ट की अपनी एक विचारधारा है और समयांतर उसी गाढ़े लाल विचारधारा का ध्वजवाहक बनी रहती है. लेख से टिप्पणियों तक में. मैं लंबे समय से समयांतर नहीं देख रहा था. अचानक दिसंबर के अंक पर नज़र पड़ी तो ख़रीद लाया, कवर पर राजेंद्र यादव का रेखाचित्र देखकर. इस अंक में असहमति के सहयात्री शीर्षक से पंकज बिष्ट ने राजेंद्र यादव पर लंबा लेख लिखा है. पंकज का ये लेख भावनाओं के ज्वार से मुक्त होकर राजेंद्र यादव को देखता है. श्रद्धांजलि लेख होने के बावजूद पंकज इसमें यादव जी के व्यक्तित्व को कई जगह कसौटी पर कसते हैं, वस्तुनिष्ठ होकर. यादव जी के निधन के बाद उनपर लिखे गए चंद बेहतरीन लेखों में से पंकज बिष्ट का यह लेख है. इस अंक में दो विवादों पर भी सामग्री है- एक तो जन संस्कृति मंच में मचे गदर पर और दूसरे बिहार में आयोजित कवि सम्मेलन पर. दोनों पर विस्तार से लिखने की मेरी योजना है अपने इसी स्तंभ में. इस बीच संस्कृतिकर्मी अजित राय के संपादन में दूरदर्शन की पत्रिका दृश्यांतर का तीसरा अंक बाज़ार में आ गया है. सिर्फ़ तीन अंक के आधार पर किसी भी पत्रिका के बारे में राय नहीं बनाई जा सकती है, पाठकों के साथ-साथ आलोचकों को भी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए.■

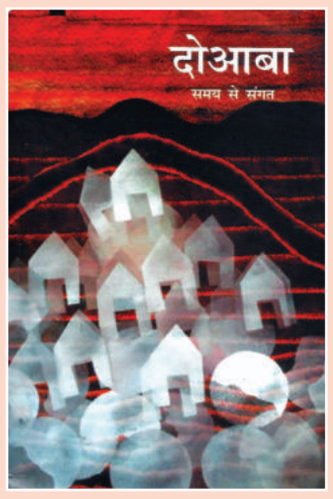

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

चुनाव

श्वेता तिवारी

अनंत उदासी से भरा मेरा मन
फिर भी
अपनी सांसों की लय को टूटने नहीं दिया
अजीब अपनों के बीच
मेरा सामना था
बचपन से
मनुष्य वेश के जानवरों से, जो मर्द थे
जो लांछित और अपमानित ही करते रहे
अपने को बचाए रखा किसी तरह
जीने का प्रयत्न किया
उनका प्रतिरोध करते हुए
इस आशा में कि एक न एक दिन
मुझे भी मिलेगा
विशेष स्नेह और संवेदना
मुझे प्रेम करता हुआ
कोई मुझे सोचता हुआ
महसूस करता हुआ मुझे अपने भीतर अतल में
आएगा एक न एक दिन ज़रूर
अपने अस्तित्व को स्थापित करूंगी
तब, विपरीत परिस्थितियों और कुसभ्यता के विरुद्ध
मिलेगा मुझे महाजीवन
इसलिए मैंने प्रतिपक्ष चुना.

समीक्षा

समाज का दर्पण है 'प्रिय कहानियां'

राजीव मणि

जाने-माने कवि, कथाकार व उपन्यासकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह की कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ है. 'प्रिय कहानियां' शीर्षक वाले इस संग्रह में कुल नौ कहानियां हैं. इसे लालजी साहित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है. डॉ. सिंह पिछले 19 वर्षों से सक्रिय हैं और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अभी तक उनकी 38 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं. दो कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह जल्द ही बाज़ार में आने वाला है.

डॉ. लालजी प्रसाद सिंह की एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपनी कहानी में समाज के वैसे सभी विषयों, चरित्रों को छूने की कोशिश की है, जिसपर दूसरे कथाकार व उपन्यासकार ने कभी हिम्मत नहीं की. वजह साफ है, गुटबाजी, खेमेबाजी और चापलूसी इस कथाकार को नहीं आती. इससे भी बड़ी बात यह कि किसी परिधि से बाहर निकलकर लिखने के लिए कलेजा चाहिए होता है, और यह इस कथाकार के पास दिखता है.

कुछ ऐसी ही इनकी कहानियां हैं 'हिन्दी के तालिबान', 'नियोग', 'गुलबिया के बच्चे', 'तमाचा', 'महान प्रतिभा', 'तुम्हारी किताब'. इनमें 'हिंदी के तालिबान' को छोड़कर शेष सभी 'प्रिय कहानियां' संग्रह में हैं. इनके अलावा 'स्वर्ग में कर्फ्यू', 'रातरानी', 'मर्सीकिलिंग', और 'अब वह तवायफ नहीं' आदि कहानियां भी इस कहानी में पढ़ने को मिलेंगी. कहानी की भाषा सरल और बोलचाल वाली भाषा है. वातावरण आसपास का. शैली प्रभावशाली.

पूरी किताब पढ़ने के बाद जिस कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह है 'मर्सीकिलिंग'. इस कहानी को बार-बार पढ़ने का मन करता है. सुंदर शुरुआत, सजीव सामाजिक तानाबाना और गिरते सामाजिक-पारिवारिक मूल्यों के बीच ज़िंदा इंसानियत ने कहानी को अनमोल बना दिया है. मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ने से जो सुख मिलता है, वही सब इसमें भी है. ये पंक्तियां ही काफी कुछ कह देती हैं-'... तुम्हें तो मालूम ही है सुंदर-मेरे गोतिया-देयाद निरवंशिया समझकर मुझसे नफरत करते-मुझसे दूर भागते हैं. मुझे अपने किसी उत्सव या काज-परोजन में पूछते तक नहीं. अब तो तुम्हीं लोग मेरे वंश-खानदान हो, मेरे सब कुछ. मेरा सारा कुछ तुम्हीं लोगों पर न्योछावर है- तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है.' कहते हुए बाढ़ू दादा एक कमरे के अंदर जाकर अपने पुराने बक्से में कुछ ढूंढने लगे. कुछ क्षण बाद ही पलटे. उनके हाथों में बहू के लिए सोने की सिकड़ी तथा कानों एवं पैरों में पहनने के लिए कुछ सोने-चांदी के जेवर चमक रहे थे. उन्होंने बहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा-'ये लो बेटी, ये सब तुम्हारे लिए. कुछ कम है बेटा. पर मन छोटा मत करना. तुम्हारा बाढ़ू दादा बूढ़ा हो चुका, थक चुका है, ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा.'

सुंदर की आंखें डबडबा गईं- 'आज मुझे रुलाने पर तुले हैं दादा? आपने इतना कुछ कर दिया और कहते हैं कि ...! मेरा भी इस दुनिया में अपना कोई होता तो इससे ज्यादा क्या कुछ कर देता?' फिर आंसू पोंछते हुए उसने कहा-'सुगनी आपसे कुछ कहना चाहती है, दादा.'

'कहो बेटी.' बाढ़ू दादा भावुकता से लबरेज थे-'जो कुछ कहना चाहती हो.'

'यही कहना चाहती हूं दादाजी कि आज से आपका चूल्हा-चक्की करना सब बंद. दोनों जून का खाना मैं बना दिया करूंगी.'

वह मुख्य गेट से अंदर कैम्पस में अभी कुछ ही दूर गया होगा कि सुगनी की सेवा में लगी नर्स आती दिखलाई पड़ी. उसने हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया- 'सिस्टर जी ...!'

'अरे तुम ... सुन्दर! कहां गायब हो गया था ? तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मिठाई खिलाओ. सुगनी कोमा से बाहर आ चुकी है.'

सुंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि किसका शुक्रिया अदा करे और कैसे? उसने भगवान को याद किया. उसके मन-मस्तिष्क में तुरंत बाढ़ू दादा की तस्वीर अंकित हो गई. वह बार-बार भगवान को याद करना चाहता और बार-बार बाढ़ू दादा की तस्वीर ही इसके जेहन में आती.

कहानी 'मर्सीकिलिंग' पढ़कर जो महसूस हुआ, वह सबकुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता. बस उसका कुछ अंश मात्र हम शब्दों के सहारे व्यक्त कर सकते हैं. संग्रह की दूसरी कहानी है- नियोग. यह आधुनिक जीवन शैली के बीच नि:संतान पति-पत्नी की कहानी है. संतान के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता और अंत में दंपत्ति को वह सब करना ही पड़ा. दरअसल, यह कोई कहानी नहीं, बल्कि समाज का कटु यथार्थ है, जिसे पढ़कर पचा लेना कठिन काम है.

इसके बाद 'गुलबिया के बच्चे' कहानी ने जैसे तथाकथित सभ्य समाज की पोल ही खोल दी हो. वहीं 'तमाचा' के माध्यम से कथाकार ने वित्तरहित कॉलेज शिक्षकों और महासंघ की सच्चाई रखी है. डॉ. लालजी प्रसाद सिंह खुद एक वित्तरहित कॉलेज में पढ़ाते हैं. इसके बावजूद सत्य के मार्ग पर चलना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा. दूसरी तरफ 'महान प्रतिभा' कहानी के माध्यम से राजनीति में फैली गंदगी को लाया गया है.

अंत में है 'तुम्हारी किताब'. यह कहानी कई लेखकों, कथाकारों को अच्छी नहीं लगेगी. इसलिए नहीं कि इसमें बकवास लिखा गया है, बल्कि इसलिए कि सच को पचाने की क्षमता कुछेक में ही होती है. इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता. हां, कुछेक पंक्तियां यहां रख रहा हूं-

लेकिन भास्कर अब सोचे क्यों नहीं? अभी ही तो वह सोचने का अवसर आ चुका. आखिर उसकी पुस्तक में अचानक सुरखाब के पर कैसे लग गए! दिल्ली जाकर ऐसा कौन-सा करिश्मा कर दिखलाया? आखिर डॉ. कामवीर सिंह इस पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? आखिर शहर की साहित्यिक गोष्ठी में रति के अंदर उन्होंने वैसा क्या कुछ देखा कि उसकी रचना के साथ पति-पत्नी को दिल्ली साथ चलने का आमंत्रण दे डाला.

सचमुच उनका शक सही निकला- रति दिल्ली से मां बनने वाली बनकर लौटी है जो! वैसे वह अब तक उनके संयोग से मां बनने से तो रही. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संग्रह की सभी कहानियां ठीक-ठाक हैं. छपाई साफ व सुंदर है. संग्रह की कीमत 150 रुपये रखी गई है. उम्मीद है तमाम पाठकों को पसंद आएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

बजाज जल्द ही पल्सर के नया वैरिएंट पेश करेगी. नए पल्सर की बड़ी खासियत यह है कि इसमें कंपनी 375 सीसी की क्षमता का इंजन इस्तेमाल करेगी. इसके अलावा, हाल ही में कोयंबटूर में आयोजित पल्सर स्टंट मेनिया में बजाज ऑटो लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर श्याम सुंदर नारायण ने बताया कि कंपनी भविष्य में तीन नए मॉडलों को पेश करने जा रही है.

35 दिनों का बैटरी बैकअप देगा यह फोन

इस फोन में 1.8 इंच की स्क्रीन लगी है. इसकी कॉन्टेक्ट सेविंग क्षमता है 500. फोन में पहले से सेव की गई 32 रिंगटोन हैं. इस फोन में 800 एमएच की बैटरी लगी है, जो 10 घंटे टॉक टाइम और 35 दिनों का स्टैंड बाय बैटरी बैकअप देती है.

मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोज मोबाइल फोन में फेरबदल करती रहती हैं. अगर आप ऐसा मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं जो लंबी बैटरी बैकअप दे तो नोकिया का 106 आपके लिए बेहतरीन साबित होगा. जी हां, यह फोन कीमत में भी काफी कम है. इसकी कीमत है मात्र 1,399 रुपये. कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर 35 दिनों तक स्टैंडबाय बैटरी बैकअप देने में सक्षम है. नोकिया 106 काले, लाल और सफेद तीन रंगों में उपलब्ध है. इस फोन में 1.8 इंच की स्क्रीन लगी है. इसकी कॉन्टेक्ट सेविंग क्षमता है 500. फोन में पहले से सेव की गईं 32 रिंगटोन हैं. इस फोन में 800 एमएच की बैटरी लगी है, जो 10 घंटे टॉक टाइम और 35 दिनों का स्टैंड बाय बैटरी बैकअप देती है. यह फोन उन लोगों के लिए बढ़िया है जो फोन ज्यादा प्रयोग करते हैं. इस फोन में एफएम रेडियो भी है. इसमें सामान्य इस्तेमाल के लगभग तमाम फीचर्स दिए गए हैं. एफएम रेडियो, डिजिटल घड़ी, कैल्कुलेटर, फ्लैशलाइट, कैलेंडर, स्पीकिंग क्लॉक, अलार्म क्लॉक और रिमाइंडर की सुविधा भी है. ■

निसान ने लॉन्च की तीन स्पोर्ट्स कारें

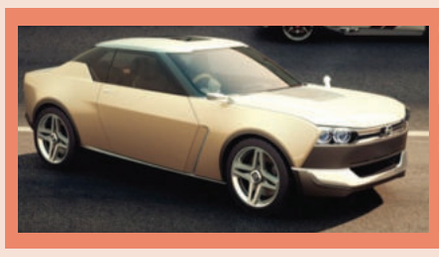

निसान एक साथ तीन नई स्पोर्ट कारें पेश करने वाली है. ये अपनी खास डिजाइन के लिए इन दिनों चर्चा में हैं.

हाल ही में टोकियो मोटर शो के दौरान निसान कार कंपनी ने अपनी दो स्पोर्ट कॉन्सेप्ट कार निसान आईडीएक्स फ्रीफ्लो और आईडीएक्स निस्मो को पेश किया था. कंपनी इन दोनों स्पोर्ट कारों को नॉर्थ अमेरीकन इंटरनेशनल ऑटो शो में भी प्रदर्शित करेगी. साथ ही कंपनी इस ऑटो शो में अपनी एक और स्पोर्ट सेडान कॉन्सेप्ट कार को भी उतारेगी. कंपनी ने इस स्पोर्ट सेडान कॉन्सेप्ट कार की तस्वीर भी जारी की है.

इस तस्वीर में कार की शानदार डिजाइन और आकर्षक हेड लाइट काफी मनमोहक लग रही है. निसान की ये तीनों कॉन्सेप्ट कार 13 जनवरी, 2014 रिलीज हो जाएगी. ■

ट्रांसपेरेंट टैबलेट

फीचर्स

प्रोसेसर: कोरटैक्स ए-9
ओएस: जेलीबीन और किटकैट
स्क्रीन: 7 इंच एलसीडी स्क्रीन
कनेक्टिविटी: वाईफाई, ब्लूटूथ
स्टोरेज: 8 जीबी, 32 जीबी एक्सपेंडेबल
रैम : 1 जीबी

एलसीडी स्क्रीन में कई सतह होती हैं, जिन पर बैकलाइट से प्रकाश पड़ता है. इनमें दो डिफ्यूजरों की सतह होती हैं. यह आईने के पीछे लगी परत की तरह होती हैं, जिससे स्क्रीन पर दिखने वाली पिक्चर ज्यादा चमकदार दिखाई देती है. टैब डिजाइनरों ने डिफ्यूजर की एक सतह को हटा दिया. इससे स्क्रीन 25 फीसदी तक ट्रांसपेरेंट हो गई. इसके बाद दूसरी स्क्रीन को इसमें जोड़ा गया.

टैब की स्क्रीन 25 फीसदी ट्रांसपेरेंट है. फ्रंट स्क्रीन पर अंगूठे के इस्तेमाल के लिए थंब टच इनपुट दिया है. पीछे भी मल्टीटच पैनल है. टैब को पकड़ने के दौरान यूजर पीछे वाली स्क्रीन पर टिकी अंगुलियों से काम कर सकते हैं. इसमें रिमोट ट्रांसमीटर भी लगा है. इसे टीवी और डीवीडी के रिमोट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

शुरुआत में टैब को डिजाइन करने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया था. धीरे-धीरे काडबोर्ड का यह डिजाइन दुनिया के पहले पारदर्शी टैबलेट का आधार बना. कंपनी का कहना है कि टैब इस्तेमाल करने के दौरान लोग राइट साइड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इसे देखते हुए कंपनी ने अधिक इस्तेमाल होने वाली की टैब के राइट साइड में ही रखी हैं. ■

डुकाटी देगी बाइक्स कंपनियों को कड़ी टक्कर

भारत में इस समय डुकाटी की मॉन्स्टर, मल्टीस्ट्राडा, स्ट्रीटफाइटर, हाईपर मोटोराड, डीयावेल और सुपर बाइक्स सीरीज जैसी कई दमदार मोटरसाइकिलें उपलब्ध हैं.

मशहूर इटैलियन मोटरसाइकिल कंपनी डुकाटी ने भारतीय मार्केट में सीधे प्रवेश करने वाली है. हालांकि अभी तक डुकाटी के बिजनेस को मैनेज करने वाली कंपनी प्रिसिजन मोटर्स कुछ क्षेत्रों में आगे भी डुकाटी का बिजनेस संभालती रहेगी. प्रिसिजन मोटर्स के लिए डुकाटी मोटरसाइकिलों को आयात करके भारतीय मार्केट में बेचना काफी मुश्किल हो रहा था और इसके साथ ही कंपनी ग्राहकों को अच्छी सर्विस भी नहीं दे पा रही थी. भारतीय मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कंपनी ने यह फैसला किया है. भारत में इस समय डुकाटी की मॉन्स्टर, मल्टीस्ट्राडा, स्ट्रीटफाइटर, हाईपर मोटोराड, डीयावेल और सुपर बाइक्स सीरीज जैसी कई दमदार मोटरसाइकिलें उपलब्ध हैं. इनमें से सबसे कम कीमत मॉन्स्टर 795 की है, जिसकी कीमत लगभग 5.9 लाख रुपये है. ■

बजाज की सुपर बाइक्स

देश की टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो भारतीय बाजार में अपनी बाइक मॉडल रेंज में इजाफा करने की योजना बनी रही है. कंपनी आगामी दिल्ली ऑटो एक्सपो में दो से तीन नए बाइक मॉडलों को पेश करने वाली है. फरवरी 2014 को दिल्ली में होने वाले ऑटो शो में कई नए मॉडल देखने को मिलेंगे. बजाज जल्द ही पल्सर के नए वैरिएंट पेश करेगी. नए पल्सर की बड़ी खासियत यह है कि इसमें कंपनी 375 सीसी की क्षमता का इंजन इस्तेमाल करेगी. इसके अलावा, हाल ही में कोयंबटूर में आयोजित पल्सर स्टंट मेनिया में बजाज ऑटो लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर श्याम सुंदर नारायण ने बताया कि, कंपनी भविष्य में तीन नए मॉडलों को पेश करने जा रही है. कंपनी की इस नई योजना के तहत पल्सर सीरीज के 150 सीसी सेगमेंट में नए रीडिजाइन पल्सर को पेश किया जाएगा. ■

महंगी होने जा रही है नैनो

टाटा मोटर्स ड्रीम कार नैनो प्रोजेक्ट में एक अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुकी है, लेकिन इससे कमाई करने के मामले में कंपनी अभी कोसो दूर ही है. पिछले 4 साल में कंपनी ने 2,42,431 नैनो बेची हैं. 2009 में इसे लॉन्च करते समय कंपनी ने हर साल 2,50,000 नैनो बेचने का सपना देखा था. हाल ही में कंपनी ने कहा कि अब इसकी भरपाई के लिए वह नए कॉन्सेप्ट कर काम कर रही है. कंपनी नैनो के ए मॉडल को अलग-अलग फीचर्स के साथ अलग-अलग कीमतों पर रिलॉन्च करने की तैयारी में है. नई नैनो की कीमत 1.75 लाख से 3.25 लाख रुपये के बीच होगी. 5 ट्रिम लेवल्स के साथ कंपनी इस कार को 4 इंजन ऑप्शंस में लाने जा रही है. इसमें दो पेट्रोल वर्जन होंगे. एक में डीजल इंजन और एक सीएनजी से चलेगी. कार में पावर स्टीयरिंग, बेहतर इंजन और अच्छे फीचर्स होंगे. नैनो को लेकर कंपनी की रणनीति अब बदल गई है. वह कार को लेकर वही चीजें बनाए रखना चाहती है, जिससे मार्केट खुश है. उन चीजों को हटाया जा रहा है, जिनसे इसकी इमेज खराब हुई है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कम बजट में बेहतरीन फोन

3जी नेटवर्क पर अधिकतम 7.2 एमबीपीएस तक की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है.

इंटेक्स ने एक्वा सीरीज के तहत अपना नया हैंडसेट आई4+ पेश किया है. फोन में 5.0 इंच की एफडब्यूवीजीए स्क्रीन दी गई है और स्क्रीन रेजॉलूशन 854–480 पिक्सल है. हालांकि आज एचडी स्क्रीन का चलन है, ऐसे में इस रेजॉल्यूशन को थोड़ा कम कहा जा सकता है, पर फिर भी इस बजट में ज्यादातर फोन इसी रेजॉल्यूशन या इससे भी कम रेजॉल्यूशन में आते हैं. इंटेक्स एक्वा आई4+ 1.2 गीगाहर्ट्ज का डुअलकोर प्रोसेसर और 512 एमबी की रैम के साथ काम करता है. वाई-फाई कनेक्टिविटी के अलावा यह 3जी सपोर्ट भी करता है. 3जी नेटवर्क पर अधिकतम 7.2 एमबीपीएस तक की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है. अन्य कनेक्टिविटी ऑप्शन में आपको यूएसबी और ब्लूटूथ मिलेगा. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 4.2.2) जेलीबीन आधारित इस डिवायस में 8.0 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है, जबकि सेकेंड्री कैमरा 1.3 मेगापिक्सेल का है. फोन की इंटरनल मेमोरी 4 जीबी है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. पावर बैकअप के लिए इसमें 2000 एमएएच की बैटरी दी गई है और कंपनी 6 घंटे टॉक टाइम और 220 घंटे स्टैंडबाय का दावा करती है. फोन की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इसमें कई बेहतर एप्लिकेशन पहले से मौजूद हैं. जैसे वीचैट और ओएलएक्स इत्यादि. खास बात यह भी है कि इसके एप्लिकेशन के जरिए आप हिंदी, उर्दू, तमिल और बंगाली सहित 22 भाषाओं में टाइपिंग कर सकते हैं. फोन में इंटेक्स प्ले एप्लिकेशन है, जहां से आप फोन के कंपैटिबल एप्लिकेशन और गेम डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए 5 जीबी तक का क्लाउड स्टोरेज भी मुफ्त में उपलब्ध है. इंटेक्स एक्वा आई4+ की कीमत 7,600 रुपए है. इस रेंज में फोन को माइक्रोमैक्स ए74 और कार्बन ए30 जैसे फोन में कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है. दोनों फोन लगभग समान स्पेसिफिकेशन के साथ उपलब्ध हैं.■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

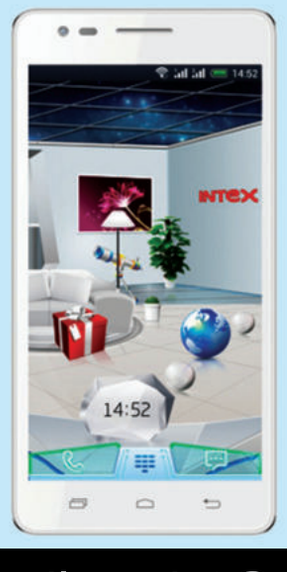

> आईसीसी डीआरएस को ओआरएस की मदद से सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम कर रही है. आईसीसी हमेशा से तकनीक के उपयोग से अपायरिंग को सटीक और त्रुटिहीन बनाने की हर संभव कोशिश करता रहा है, ताकि वैश्विक तौर पर खेल के स्तर में सुधार लाया जा सके. आईसीसी ने 2008 में डीआरएस की प्रयोग के तौर पर शुरुआत की थी.

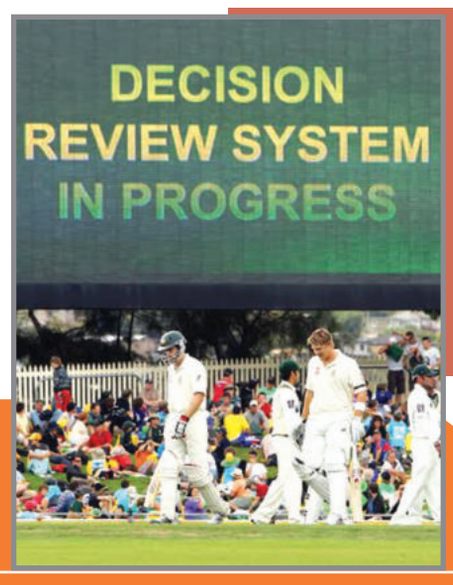

तीसरे अंपायर को मजबूत बनाने की कवायद

डीआरएस से ओआरएस की ओर

डीआरएस की कमियों को दूर करने के लिए आईसीसी ने एक कदम और बढ़ाते हुए ऑफिशियेटिंग री-प्ले सिस्टम(ओआरएस) पर काम कर रहा है, जिसमें तीसरे अंपायर को मैच के सभी एंगल के सीधे री-प्ले मुहैया कराए जाएंगे. इस नई तकनीक का ट्रायल पिछले साल एशेज सीरीज के दौरान ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ था. अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली गई सीरीज के पांचवें मैच में भी इसका ट्रायल हुआ जो कि इसके बाद हुई टेस्ट सीरीज में भी जारी रहा. आईसीसी के ओआरएस की दिशा में काम करने की बात पिछले साल जुलाई में एशेज श्रृंखला के दौरान प्रकाश में आई थी.

नवीन चौहान

क्रिकेट की दुनिया में अंपायरों के निर्णयों को लेकर हमेशा से विवाद की स्थिति खड़ी होती रही है. खास कर तब जब दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों मसलन भारत-पाकिस्तान, इंग्लैंड- ऑस्ट्रेलिया या किन्हीं और टीमों के बीच कांटे की टक्कर चल रही हो. अंपायर के एक गलत निर्णय की वजह से मैच का पूरा रुख ही बदल जाता है. ऐसे में गलत फैसले का शिकार हुए खिलाड़ी के पास खीझने और गुस्सा करने के बाद फैसले को मान लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति से बचने और रन-आउट और स्टंपिंग के करीबी फैसलों को ध्यान में रखकर ही तीसरे अंपायर की परिकल्पना की गई और इसे मूर्त रूप दिया गया. पहले इसकी भूमिका मैदानी अंपायरों के लिए एक सहयोगी की तरह होती थी, लेकिन बदलती तकनीक और खेल ने तीसरे अंपायर को निर्णय की धुरि के रूप में स्थापित कर दिया. जैसे-जैसे खेल में गति आ रही है, मानवीय भूलों के लिए खेल में कोई जगह नहीं रह गई है. यदि कहीं पर इसकी थोड़ी गुंजाइश भी है तो उसे भी खत्म करने की पूरी कोशिश आईसीसी करता रहा है.

क्रिकेट में एक बार फिर तकनीक के अंपायरिंग में उपयोग को लेकर बड़ी बहस शुरू होने वाली है. चूंकि आईसीसी डीआरएस को ओआरएस की मदद से सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम कर रही है. आईसीसी हमेशा से तकनीक के उपयोग से अपायरिंग को सटीक और त्रुटिहीन बनाने की हर संभव कोशिश करता रहा है, ताकि वैश्विक तौर पर खेल के स्तर में सुधार लाया जा सके. आईसीसी ने 2008 में डीआरएस की प्रयोग के तौर पर शुरुआत की थी. भारत शुरू से ही डीआरएस का मुखर होकर विरोध करता रहा है. जिस किसी प्रतियोगिता या श्रृंखला में डीआरएस के प्रयोग की अनुमति थी, उसमें भारत के पक्ष में बहुत ही कम फैसले गए. डीआरएस की अपनी तकनीकी सीमाओं को लेकर भी कई विवाद हुए. साथ ही तकनीक के तोड़ के तौर पर खिलाड़ियों द्वारा उपयोग में लाए गए नुस्खे भी सुर्खियां बने और यह बात सिद्ध हुई कि कोई भी तकनीक सौ प्रतिशत प्रभावी नहीं हो सकती है, लेकिन त्रुटियों में बड़े पैमाने पर बदलाव लाया जा सकता है. डीआरएस की कमियों को दूर करने के लिए आईसीसी ने एक कदम और बढ़ाते हुए ऑफिशियेटिंग री-प्ले सिस्टम(ओआरएस) पर काम कर रहा है, जिसमें तीसरे अंपायर को मैच के सभी एंगल के सीधे री-प्ले मुहैया कराए जाएंगे. इस नई तकनीक का ट्रायल पिछले साल एशेज सीरीज के दौरान ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ था. अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली गई सीरीज के पांचवें मैंच में भी इसका ट्रायल हुआ जो कि इसके बाद हुई टेस्ट सीरीज में भी जारी रहा. आईसीसी के ओआरएस की दिशा में काम करने की बात पिछले साल जुलाई में एशेज श्रृंखला के दौरान प्रकाश में आई थी. जब स्टुअर्ट ब्रॉड के बल्ले को किनारे लेकर गई गेंद कैच कर ली गई थी और अंपायर ने ब्रॉड को नाट-ऑउट करार दिया था. तब आईसीसी ने तीसरे अंपायर को री-प्ले पर नियंत्रण के और अधिकार दे दिए थे, ताकि वह अपनी जरूरत के हिसाब से री-प्ले देख सके. निर्णय के लिए उसे आधिकारिक प्रसारणकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले री-प्ले पर निर्भर नहीं रहना पड़े.

ऑफिशियेटिंग री-प्ले सिस्टम(ओआरएस) में टीवी अंपायर एक अलग ब्रॉडकास्टिंग ट्रैक में बैठता है, जिसमें बहुत सारी टीवी स्क्रीन लगी होती हैं. जहां वह एक ही शॉट को निर्णय लेने के लिए आवश्यक एंगल्स से देख सकता है. साथ ही अपनी आवश्यकता के अनुसार कैमरे के एंगल्स को मर्ज भी कर सकता है. ओआरएस के लागू हो जाने से अंपायर के हाथ में हर तरह के कैमरा एंगल पर नियंत्रण आ जाएगा. इससे उसे प्रसारणकर्ता द्वारा किए जा सकने वाले पक्षपात से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी. निर्णय लेने के समय में व्यापक कमी भी आएगी. पांच बार सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार जीत चुके ऑस्ट्रेलिया के साइमन टफेल आजकल आईसीसी में अंपायर्स ट्रेनिंग ऐंड परफॉर्मेंस मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं. ओआरएस को लेकर उनका कहना है कि वह जैसा, जिस एंगल वाला व्यू देखना चाहते हैं, सारे उनकी आंखों के सामने मौजूद है. मसलन नो बॉल, गेंद अथवा खिलाड़ी की सीमा रेखा को छूना उनके बगल में बैठे ऑपरेटर के सामने मौजूद है. वर्तमान में अंपायर के मॉनीटर पर वही फीड उपलब्ध होती थी जो आधिकारिक प्रसारणकर्ता उपलब्ध कराता है. यह वही फीड है जो एक सामान्य टीवी दर्शक अपनी टीवी पर देख रहा होता है, वही फीड अंपायर के पास भी उपलब्ध होती है. जितनी बार भी टीवी अंपायर को फैसला लेने को कहा जाता है, उतनी बार अंपायर को प्रसारणकर्ता को फुटेज उपलब्ध कराने के लिए निवेदन करना पड़ता है, लेकिन ओआरएस के होने पर वह प्रसारणकर्ता से मुक्त हो जाएगा. निश्चित तौर पर यह टीवी अंपायर की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ सकता है. इसकी मदद से डीएसआर और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा.

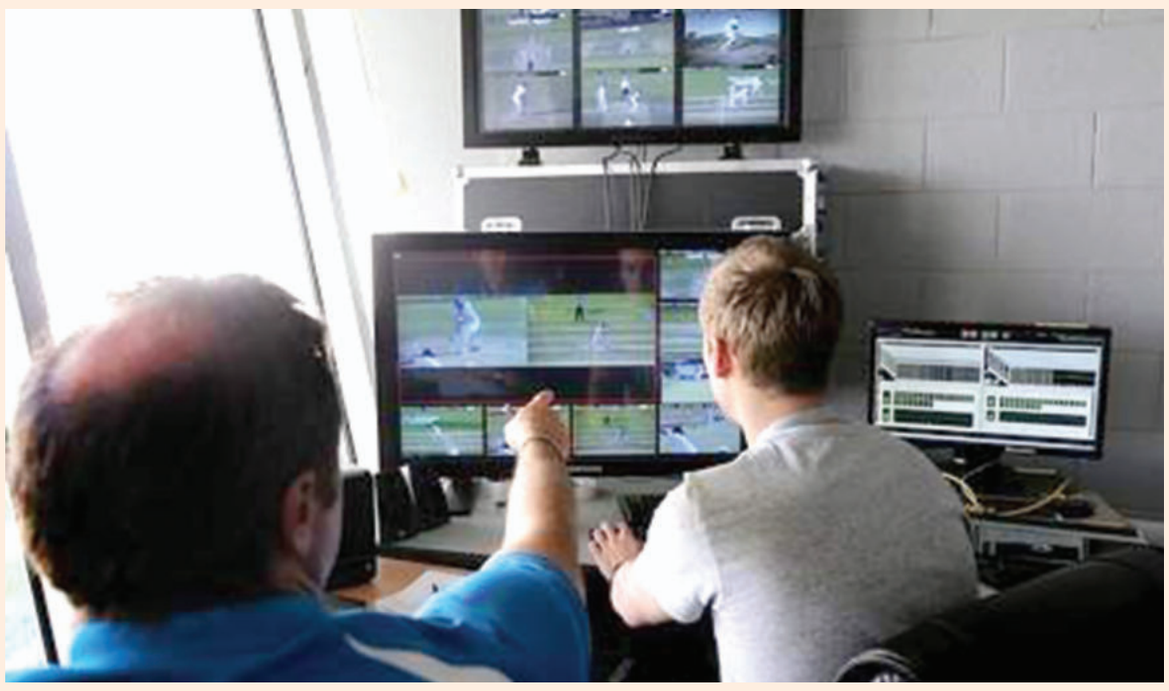

इस सिस्टम पर पैनी निगाह रखने वाले टफेल का कहना है कि ओआरएस के माध्यम से हम एक बहुत ही अलग तरह का स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण कर रहे हैं. हम बहुत से ऐसे विकल्पों की ओर ध्यान दे रहे हैं, जिससे खेल में कम से कम व्यवधान उत्पन्न हो और टीवी अंपायरों द्वारा सटीक निर्णय लेने की क्षमता में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. मुझे यकीन है कि ओआरएस टीवी अंपायर के काम को ज्यादा आसान बना देगा. गौरतलब है कि टीवी अंपायर मैदानी अंपायरों की तुलना में केवल एक से दो प्रतिशत निर्णयों में भूमिका अदा करते हैं. ऐसे में एक से दो प्रतिशत निर्णयों के लिए लागत में इजाफा करना कहां तक जायज है. यह तकनीक सामान्य तौर पर कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो सकती. इसकी लागत को कम करने को लेकर भी काम किया जा रहा है, नहीं तो निश्चित तौर पर बड़ी लागत इसे लागू करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी.

यह आईसीसी के टेक्नोलॉजी रिव्यू ग्रुप पर निर्भर करता है कि वह इसे लागू करने के लिए सभी बोर्डों को किस तरह सहमत कर पाता है, लेकिन कई पूर्व खिलाड़ी आईसीसी के इस दिशा में काम करने की प्रशंसा कर चुके हैं. उन्हीं खिलाड़ियों में से एक पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कॉमेंटेटर रमीज़ रज़ा का कहना है कि यह नई प्रणाली दो तरह से उपयोगी हो सकती है. पहला, यदि अब तक प्रसारणकर्ता री-प्ले उपलब्ध कराने में किसी तरह का पक्षपात करते रहे हैं तो, यह उसे पूरी तरह लगाम लगा देगा. दूसरा यह तीसरे अंपायर द्वारा निर्णय लेने में लिए जाने वाले समय में सीधे तौर पर कमी लाएगा. इन दोनों ही बातों के आधार माना जा रहा है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसकी क्षमता और उपयोगिता का सही-सही आकलन इसके उपयोग में आने के बाद ही हो सकेगा.

अंपायरिंग का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर सेवा और बेहतर निर्णय उपलब्ध कराना होता है और यह तकनीक इस थ्योरी पर खरी उतरती है. समय के साथ तकनीक और खेल दोनों में व्यापक बदलाव हुए हैं. खेल को रोचक और लोकप्रिय बनाए रखने के लिए दोनों के अनुरूप काम करना होगा. ओआरएस टीवी अंपायर को और भी ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराएगा. आईसीसी को लगता है कि ओआरएस, डीआरएस को और ज्यादा कारगर बनाने में प्रभावी होगा, लेकिन जब तक भारत इसे अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक डीआरएस को आवश्यक रूप से लागू नहीं कर पाएगी. इसकी लागत को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन अंपायर के फैसले के खिलाफ अपील करने की सीमा जैसी और कई बाधाएं हैं. ब्रॉड को अंपायर द्वारा नॉट-आउट करार देने के फैसले को एशेज ऑस्ट्रेलिया चुनौती नहीं दे सकी थी, क्योंकि उसकी अपील की सीमा खत्म हो चुकी थी. ऐसा लगता है कि कुछ टीमों के लिए यह अंपायर के सहयोगी से ज्यादा एक नीतिगत हथियार साबित होगा.■

navinchauhan@chauthiduniya.com

कोरी एंडरसन के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरी एंडरसन के लिए नया साल एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ क्विंस टाउन में खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच में क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा कर दिखाया. अपने एकदिवसीय करियर के सातवें मैंच में उन्होंने 36 गेंदों में शतक जड़कर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. अफरीदी ने 37 गेंदों में शतक बनाया था. आफरीदी ने यह शतक वर्ष 1996 में अपने करियर के महज दूसरे एकदिवसीय मैच में श्रीलंका के खिलाफ केन्या की राजधानी नैरोबी में लगाया था. 18 साल से इस रिकॉर्ड के आस-पास भी कोई खिलाडी नहीं फटक सका था, लेकिन कोरी ने एक अनजान खिलाड़ी के रूप में इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया. कोरी ने अपनी आतिशी पारी में 47 गेंदों में नाबाद 131 रन बनाए. उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 14 छक्के और 6 चौके भी लगाए, लेकिन वह एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके. जिस तरह एक पारी से शाहिद अफरीदी अन-ाजान खिलाड़ी से स्टार बन गए थे. शायद कोरी भी अफरीदी की राह पर चल पड़े हैं. 23 वर्षीय यह खिलाड़ी इस बार आईपीएल में सबसे ज्यादा बोली वाले खिलाड़ी बन सकता है. सारी फ्रेंचाइजीज की नजरें नीलामी के दौरान इस खिलाड़ी पर होगी. अपने रिकॉर्ड के तोड़े जाने पर शाहिद अफरीदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किसी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मैं चाहता था कि मेरे क्रिकेट खेलते रहने तक मेरा यह रिकॉर्ड कायम रहे, पर ऐसा हो नहीं सका. 18 साल तक उनका यह रिकॉर्ड कायम रहा, यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है. ■

कैलिस की हरफनमौला टेस्ट पारी का अंत

दुनिया के महानतम ऑल- राउंडर जैक कैलिस ने 18 साल लंबे अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया है. कैलिस ने अपने करियर के आखिरी टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाया. वह अपनी शतकीय पारी के दौरान कैलिस सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए. कैलिस पिछले 18 साल से अपनी टीम को अपनी गेंदबाजी के बल पर एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज का फायदा दिलाते रहे. उनके टीम से जाने के बाद यकीनन टीम को दोहरी कमी खलेगी. अड़तीस बरस के कैलिस के नाम 166 टेस्ट में 13289 रन हैं. वह मात्र सचिन तेंदुलकर (15921) और रिकी पोंटिंग (13378) से ही पीछे रहे. उनका बल्लेबाजी औसत 55.37 रहा, जबकि उन्होंने 292 विकेट लेने के अलावा 200 कैच भी लपके. टेस्ट क्रिकेट में तेंदुलकर (51) के बाद उन्होंने सर्वाधिक 45 शतक जमाए हैं. किंग ऑफ ऑल-राउंडर्स कहे जाने वाले कैलिस फिलहाल एकदिवसीय क्रिकेट खेलते रहेंगे. कैलिस ने अपने टेस्ट करियर का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ दिसंबर 1995 में किया था. संन्यास के बाद कैलिस ने कहा कि यह अद्भुत है, जिस तरीके से लोगों ने आकर मेरी हौसलाफजाई की. साउथ अफ्रीका और मेरी टीम ने इसे मेरे लिए एक खास मैच बना दिया. मैं इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकता था. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कठिन है. इस मैच से पहले मुझे बेचैनी हो रही थी. एमएस धोनी और भारतीय टीम को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

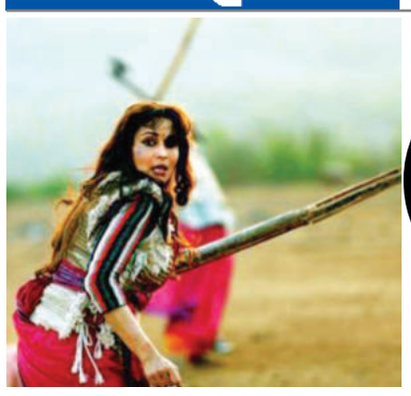

बुंदेलखंड के गुलाब गैंग पर बनी फिल्म गुलाब गैंग को निर्देशित किया है सौमिक सेन ने और प्रोड्यूस किया है अनुभव सिन्हा ने. इस फिल्म की मुख्य कलाकार हैं माधुरी दीक्षित और जूही चावला. माधुरी इस फिल्म में रज्जो की भूमिका में हैं, जबकि जूही सुमित्रा देवी की भूमिका में.

2014: इन फिल्मों का रहेगा इंतज़ार

2013 बॉलीवुड के लिए कई मायनों में ख़ास रहा. इस साल कई फिल्मों ने 100 करोड़ का कारोबार किया और कुछ ने तो 200 करोड़ का आकड़ा भी छू लिया, वहीं बॉलीवुड में इस साल और भी कई प्रयोग हुए. सिने प्रेमियों को इंतज़ार है अब 2014 में रिलीज होने वाली फिल्मों का. इस साल बड़े स्टार्स के साथ ही कई नये कलाकारों की फिल्में भी रिलीज होंगी. हम आपको बता रहे हैं इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में...

जनवरी से मार्च तक रिलीज होने वाली फिल्में

इस साल जनवरी से मार्च के बीच रिलीज होने वाली फिल्में हैं शोले (3डी), श्री जोबी कार्वाल्हो, डेढ़ इश्किया, यारियां, कर ले प्यार कर ले, लक्ष्मी, जय हो, टोटल सियापा, हंसी तो फंसी, बेरहम, गुंडे, शादी के साइड इफेक्ट, देसी मैजिक, गुलाब गैंग, ओ तेरी, हेट स्टोरी, बेवकुफियां, होलीडे और हैप्पी एंडिंग.

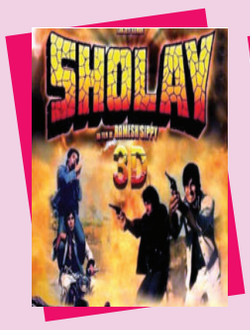

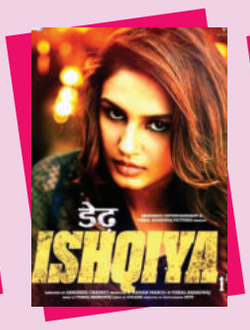

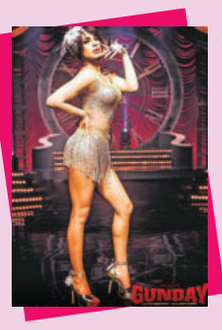

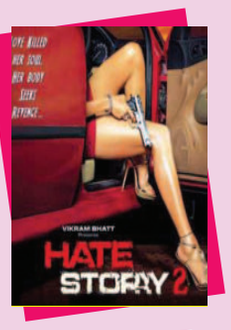

शोले (3डी) 1975 की फिल्म शोले का संस्करण है. इस फिल्म को बनाया है जयंतीलाल गाडा ने. रमेश सिप्पी निर्देशित शोले भारतीय सिनेमा में खास मायने रखती है. फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और अमजद खान मुख्य भूमिका में हैं. समीर तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है शीतल मालवीय और भोलाराम मालवीय ने. फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अरशद वारसी, सोहा अली खान, जावेद जाफरी और विजय राज. इस फिल्म में अरशद वारसी एक जासूस की भूमिका में हैं, जबकि सोहा अली खान एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं. सोहा इसमें कई रूपों में दिखेंगी. इस फिल्म में वह पुलिस ऑफिसर, कैबरे डांसर और अप्सरा के रूप में दिखेंगी. अरशद के किरदार का नाम इस फिल्म में कार्लोस है. डेढ़ इश्किया फिल्म इश्किया की सिक्वल है. काफी समय बाद माधुरी दीक्षित इस फिल्म से पर्दे पर वापसी करेंगी. उनके साथ इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी भी हैं. यारियां दिया खोसला के निर्देशन में बनी है. इस फिल्म के सारे कलाकर नये हैं. यह कॉलेज गोइंग दोस्तों की कहानी है. फिल्म ढिस्कियाऊं को निर्देशित किया है सनमजीत सिंह तलवार ने. इस फिल्म के मुख्य कलाकर हैं सन्नी देओल और हरमन बावेजा. नगेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी फिल्म लक्ष्मी के मुख्य कलाकार हैं मोनाली ठाकुर, राम कपूर, सतीश कौशिक, शेफाली शेट्टी और नगेश कुकुनूर. फिल्म जय हो सोहेल खान के निर्देशन में बनी है. यह एक ऐक्शन ड्रामा और कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं सलमान खान, डेजी शाह, सना ख़ान और तब्बू. टोटल सियापा ईश्वर निवास के निर्देशन में बनी एक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं यामी गौतम, अली जफ़र, सारा ख़ान, अनुपम खेर, किरण खेर. यह फिल्म एक पंजाबी लड़की और पाकिस्तानी लड़के के प्यार की कहानी है. शेखर सुमन ने अपने बेटे अध्ययन को लेकर एक फिल्म बनाई है हार्टलेस. यह एक थ्रिलर फिल्म है. देविका भगत के निर्देशन में बनी फिल्म वन बाई टू रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है और इसके मुख्य कलाकार हैं अभय देओल, प्रीति देसाई, रति अग्निहोत्री, जयंत कृपलानी और लिलेट दूबे. रोमांस और ऐक्शन से भरपूर गुंडे को निर्देशित किया है अली अब्बास जफर ने. मुख्य कलाकार हैं रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान ख़ान और सुशांत सिंह ने. हाइवे को निर्देशित किया है इम्तियाज अली ने. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं रणदीप हुड्डा और अलिया भट्ट. शादी के साइड इफेक्ट को निर्देशित किया है साकेत चौधरी ने. मुख्य कलाकार हैं फरहान अख्तर, विद्या बालन, राम कपूर, गौतमी, पूरब कोहली और रति अग्निहोत्री. विकास बहल के निर्देशन में बनी फिल्म क्वीन को प्रोड्यूस किया है अनुराग कश्यप ने. मुख्य कलाकार हैं कंगना रनावत, राज कुमार यादव. देशी मैजिक को निर्देशित किया है मेहुल अथा ने. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अमीषा पटेल, लिलेट दूबे, ज़ायद ख़ान और रवि किशन.

बुंदेलखंड के गुलाब गैंग पर बनी फिल्म गुलाब गैंग को निर्देशित किया है सौमिक सेन ने. इस फिल्म के मुख्य कलाकर हैं माधुरी दीक्षित और जुही चावला. हेट स्टोरी 2 को निर्देशित किया है विशाल पांडे ने. यह एक थ्रिलर एडल्ट फिल्म है और इसके मुख्य कलाकार हैं सुशांत सिंह और सुरवीन चावला. फिल्म बेवकुफियां को निर्देशित किया है नुपूर अस्थाना ने. यह आयुष्मान खुराना और सोनम कपूर की फिल्म है. ऐक्शन थ्रिलर से भरपूर होलीडे को निर्देशित किया है एआर मुरुगादास ने. इस फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा साथ दिखेंगे. हैप्पी एंडिंग एक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं सैफ अली ख़ान, इलियाना डिक्रूज, गोविंदा, प्रीति जिंटा, रणवीर शौरी, कल्की कोचलीन और करीना कपूर.

अप्रैल से जून में जो फिल्में आएंगी

अप्रैल और जून में मैं तेरा हीरो, एक्शन जैक्शन, भूतनाथ रिटर्न्स, 2 स्टेट्स, हवा हवाई, सम्राट ऐंड कं. इट्स ऐंटरटेनमेंट, सिटी लाइफ, दावत-ए- इश्क, पीके, हमशक्ल, रॉय, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां जैसी फिल्म रिलीज होंगी. मैं तेरा हीरो रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है. इस फिल्म को निर्देशित किया है डेविड धवन ने. मुख्य कलाकर हैं वरुण धवन, इलियाना डिक्रूज और नर्गिस फाखरी. प्रभु देवा के निर्देशन में बनी फिल्म ऐक्शन जैक्शन एक कॉमेडी फिल्म है. कलाकार हैं अजय देवगन, सेनाक्षी सिन्हा, यामी गौतम और कुनाल रॉय कपूर. बच्चों की फिल्म है भूतनाथ रिटर्न्स. इसे निर्देशित किया है नितेश तिवारी ने और कलाकर हैं भूषण कुमार और अभय चोपड़ा. 2 स्टेट्स एक रोमांटिक फिल्म है. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट. इट्स ऐंटरटेनमेंट एक कॉमेडी फिल्म है. इसे निर्देशित किया है साज़िद फ़रहाद ने. मुख्य कलाकार हैं अक्षय कुमार, तमन्ना भाटिया, प्रकाश राज, सोनू सूद और मिथुन चक्रवर्ती. दावत-ए- इश्क, एक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म को निर्देशित किया है हबीब फ़ैज़ल ने और मुख्य कलाकर हैं आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा. पीके को राजकुमार हिरानी ने निर्देशित किया है. मुख्य कलाकार हैं आमिर ख़ान और अनुष्का शर्मा. हमशक्ल एक कॉमेडी फिल्म है और इसे निर्देशित किया है साज़िद ख़ान ने. मुख्य कलाकार हैं सैफ़ अली ख़ान, ईशा गुप्ता, राम कपूर, रितेश देशमुख, तमन्ना भाटिया. रोमांस और ड्रामा से भरपूर रॉय को निर्देशित किया है विक्रमजीत सिंह ने. मुख्य कलाकार हैं रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और जैक्लीन फर्नांडिज. हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां को निर्देशित किया है शशांक खेतान ने और कलाकर हैं वरुण धवन और अलिया भट्ट.

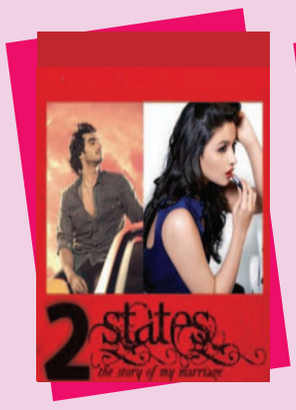

जुलाई से सितंबर में ये फिल्में मचाएंगी धूम

जुलाई से सितंबर के बीच फाइंडिंग फन्नी फर्नांडिज, मर्द और किक रिलीज होंगी. फाइंडिंग फन्नी फर्नांडिज को होमी अडजानिया ने निर्देशित किया है. मुख्य कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, पंकज कपूर, डिंपल कपाड़िया. प्रदीप सरकार के निर्देशन में बनी फिल्म मर्द ड्रामा ऐक्शन से भरपूर है. यह रानी मुखर्जी की फिल्म है. साज़िद नाडियाडवाला के निर्देशन में बनी किक एक ऐक्शन कॉमेडी फिल्म है. मुख्य कलाकर हैं सलमान ख़ान, जैक्लिन फर्नांडिज और रणदीप हुड्डा.

अक्टूबर से दिसंबर में ये फिल्में आएंगी दर्शकों के बीच

अक्टूबर से दिसंबर के बीच रिलीज होने वाली फिल्में हैं बंग-बंग, हैप्पी न्यू ईयर, डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी और बॉम्बे वैलवेट. बंग-बंग एक ऐक्शन कॉमेडी फिल्म है. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं रितिक रोशन, कैटरीना कैफ, डैनी, जावेद जाफ़री, बिपाशा बसु. फ़राह ख़ान के निर्देशन में बनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर एक कॉमेडी फिल्म है. कलाकार हैं शाहरुख़ ख़ान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन इरानी, विवान शाह, सोनू सूद. डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी को दिबाकर बैनर्जी ने बनाया है. यह एक कॉमेडी फिल्म है. मुख्य कलाकार हैं सुशांत सिंह राजपूत. बॉम्बे वैलवेट को निर्देशित किया है अनुराग कश्यप ने. मुख्य कलाकार हैं रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, करण जौहर और केके मेनन.

इनका चलेगा जादू

इस साल बॉलीवुड के ख़ान सलमान, शाहरुख और आमिर छाए रहेंगे. हालांकि सलमान की 2013 में एक भी फिल्म नहीं आई थी, लेकिन 2014 जनवरी में उनकी फिल्म जय हो रिलीज होगी. यह एक ऐक्शन फिल्म है. साजिद नाडियाडवाला की सलमान स्टारर फिल्म किक भी इस साल रिलीज होगी. इसका अधिकतर हिस्सा विदेशों में शूट किया गया है. दोनों ही फिल्में साउथ की रिमेक हैं. शाहरुख ख़ान की इस साल दो फिल्में रिलीज होंगी. हैप्पी न्यू ईयर और दूसरी फैन. हैप्पी न्यू ईयर फ़राह ख़ान की फिल्म है. इसमें शाहरुख के साथ अभिषेक बच्चन भी हैं. इसके अलावा, आदित्य चोपड़ा की एसआरके स्टारर फैन भी अगले साल ही रिलीज होगी. इस साल आमिर राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म पीके में नजर आएंगे. इस फिल्म में आमिर ख़ान के साथ सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा भी होंगी. राजकुमार हिरानी ने ही फिल्म थ्री इडियट्स बनाई थी. उम्मीद किया जा रहा है कि यह फिल्म भी साल के बेहतरीन फि ल्मों में से एक होगी. आमिर साल में एक ही फिल्म करते हैं, लेकिन लोगों को उनकी फिल्म का इंतज़ार रहता है. इस साल रणबीर कपूर की दो फिल्में बॉम्बे वैलवेट और जग्गा जासूस रिलीज हो रही हैं. बॉम्बे वैलवेट से तो ज़्यादा उम्मीदें नहीं जताई जा रही हैं, लेकिन जग्गा जासूस से अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि दोनों ही फिल्में कॉमर्शियल नहीं मानी जा रही हैं. अगले साल अर्जुन कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रणवीर सिंह की फिल्में भी रिलीज होंगी. अर्जुन और रणवीर की गुंडे भी 2014 में रिलीज हो रही है. कृष 3 की कामयाबी के बाद रितिक रोशन की फिल्म बंग-बंग 2014 के अक्टूबर में रिलीज होगी. बड़ी फिल्मों में एक और फिल्म है रॉय. विक्रमादित्य सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म के फर्स्ट लुक से यह फिल्म एक जासूसी फिल्म लगती है. ■

चौथी दुनिया

13 जनवरी –19 जनवरी 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार – झारखंड

फोटो–प्रभात पाण्डेय

दही चूड़ा के बाद तालमेल का तिलकुट

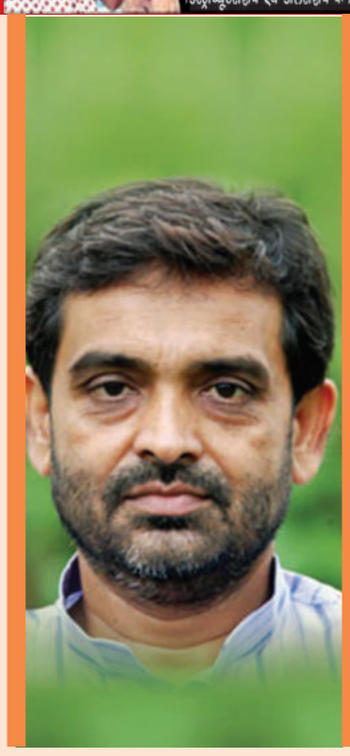

सूबे के लिए नए सियासी समीकरण की कवायद उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन जदयू ने भाजपा से अलग होने का ऐलान किया था. उस दिन यह तय हो गया था कि हर दल को यहां नए सिरे से अपने सहयोगी खोजने होंगे. खासकर भाजपा व जदयू के लिए तो यह अनिवार्य हो गया था लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर राजद व लोजपा के बीच पेंच ऐसा फंसा कि यह दोनों पुराने दोस्त भी अब दो छोर पर खड़े हैं. गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है पर उससे पहले का सारा काम पूरा हो गया है. एक-दूसरे की आलोचना और उलाहना देने का जो सिलसिला चला वह रुक ही नहीं रहा है.

सरोज सिंह

महीना खरमास का चल रहा है इसलिए सूबे की नई राजनीतिक तस्वीर से अभी परदा नहीं उठा है लेकिन अंदरखाने जो तैयारी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दही–चूड़ा यानि मकर संक्रांति के बाद जब इस सियासी तस्वीर से परदा उठेगा तो तालमेल का तिलकुट तैयार मिलेगा और बिहार के कई राजनीतिक सूरमा अपने अब तक के विरोधियों के साथ गले मिलकर इस तिलकुट का मजा लेते नजर आएंगे. दरअसल इस खरमास ने नेताओं को अपने नए साथी चुनने और उनके साथ राजनीतिक सौदेबाजी का कुछ समय दे दिया नहीं तो जितनी तेजी से बात हो रही है उससे पिछले साल ही तालमेल का खाका सामने आ जाता. सूबे के लिए नए सियासी समीकरण की कवायद उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन जदयू ने भाजपा से अलग होने का ऐलान किया था. उस दिन यह तय हो गया था कि हर दल को यहां नए सिरे से अपने सहयोगी खोजने होंगे. खासकर भाजपा व जदयू के लिए तो यह अनिवार्य हो गया था लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर राजद व लोजपा के बीच पेंच ऐसा फंसा कि यह दोनों पुराने दोस्त भी अब दो छोर पर खड़े हैं. गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है पर उससे पहले का सारा काम पूरा हो गया है. एक–दूसरे की आलोचना और उलाहना देने का जो सिलसिला चला वह रुक ही नहीं रहा है. कांग्रेस व वामदलों को भी साथी चाहिए पर ये दल वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं. मतलब यह है कि बिहार के राजनीतिक हालात ही ऐसे हो गए कि हर दल अपना नया दोस्त खोज रहा है ताकि संसद के गलियारे में उनके सांसद मुस्कुराते हुए फोटे खींचवाते दिख जाएं पर यह इस बार इतना आसान नहीं है इसे सभी दल शिद्दत से महसूस भी कर रहे हैं. यही वजह है कि पूरी तरह ठोंक बजा कर होमवर्क हो रहा है ताकि अंतिम मुकाबले में कोई चूक न रह जाए और पार्टी और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बचा रह जाए. जैसा कि चौथी दुनिया ने पहले भी अपने पाठकों से कहा था कि राजद व लोजपा की दोस्ती अब लंबे समय तक चलने वाली नहीं हैं. इसका एक मात्र कारण यह है कि लोजपा को उतनी सीटें नहीं दी जा रही है जितनी वह अपेक्षा रखती है. दो टूक कहा जाए तो पिछली बार राजद ने लोजपा के लिए 12 सीटें छोड़ी थीं इसलिए लोजपा उन पुरानी सीटों को फिर से अपने लिए चाहती है. एक रियायत वह अपनी तरफ से पहले ही देने का ऐलान कर चुकी है कि अगर कांग्रेस भी इस गठबंधन में आती है तो दो से तीन सीटों को वह छोड़ सकती है. पिछले दिनों कांग्रेस व लोजपा के दो बड़े नेताओं की बातचीत में यह फार्मूला सामने आया था कि 19 सीटों पर राजद, दस–दस पर कांग्रेस और लोजपा और एक सीट पर एनसीपी चुनाव लड़े. लेकिन इस फार्मूले की भनक मिलते ही राजद के नेता बिगड़ गए. लालू प्रसाद लाख कह रहे हों कि गठबंधन के लिए वह कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं पर सूत्र बताते हैं कि पार्टी के भीतर के दबाव के कारण वह 25 सीट से कम पर मानने वाले नहीं हैं. कांग्रेस को तो वह मुंहमांगी सीटें दे देंगे पर इसका नुकसान लोजपा को उठाना पड़ सकता है. यही स्थिति लोजपा के नेताओं को डरा रही है. रघुवंश सिंह के बयानों से हालात और बिगड़ गए. लोजपा नेताओं का कहना है कि बिना लालू प्रसाद के इशारे के रघुवंश सिंह यह नहीं बोल सकते हैं कि अपने पहलवान लाओ और टिकट पाओ. इसलिए लोजपा प्लान बी के लिए रात दिन होमवर्क में जुटी है. जदयू के रणनीतिकार लोजपा के प्लान बी को काफी तवज्जो दे रहे हैं. दिल्ली में सांसद के सी त्यागी के निवास पर इस सिलसिले में कई दौर की बातचीत हो चुकी है. लोजपा के लगभग सभी बड़े नेता दिल्ली में जुटे हैं और प्लान बी के नफा नुकसान का आंकलन कर रहे हैं. हालांकि कुछ नेता चाहते हैं कि राजद से गठबंधन बना रहे लेकिन ज्यादातर की राय है कि अगर टिकट ही नहीं मिलेगा तो लालू प्रसाद के साथ रहने से क्या फायदा? दिल्ली में लोजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह बात भी सामने आई कि पिछले चुनावों में राजद का आधार वोट लोजपा के प्रत्याशियों को नहीं मिल पाया. इसलिए राजद के साथ रहने से कोई फायदा नहीं होगा. अगर जदयू से गठबंधन होता है तो कम से कम दलितों की एक मजबूत गोलबंदी होगी और इसका पूरा फायदा लोजपा के प्रत्याशियों को मिलेगा और भाजपा को इसका भारी नुकसान होगा. इसके अलावा ज्यादा सीटें मिलने से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा. यह बात भी चर्चा में रही कि जदयू के रणनीतिकार चाहते हैं कि लोजपा नीतीश सरकार में शामिल हो और पशुपति पारस सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएं. जदयू की सोच है कि इससे पहला तो गठबंधन पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और दूसरी बात यह होगी कि पासवान समाज में यह संदेश जाएगा कि जो हुआ सो हुआ पर अब नीतीश सरकार इस समाज को उचित सम्मान और हिस्सेदारी देना चाहती है. इसलिए प्लान बी का जो मसौदा बनाया गया है उसमें पहली शर्त ही यह है कि पासवान समाज को उचित सम्मान और उसका उचित हक देना होगा. दूसरी शर्त सम्मानजनक सीट है. सरकार में हिस्सेदारी को लेकर लोजपा ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है. यहां तक तो बात पटरी पर आ गई है लेकिन असली पेंच कांग्रेस की तरफ से फंस रहा है. लोजपा चाहती है कि इस तालमेल में कांग्रेस भी शिरकत करे ताकि मुसलमानों में यह संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी की चुनौती को बिहार में जदयू लोजपा और कांग्रेस का गठबंधन ही ध्वस्त कर सकता है. कांग्रेस में इसे लेकर दो तरह की धाराएं हैं. एक धारा ऐसे नेताओं की है जो चाहता है कि लालू प्रसाद को साथ रखा जाए क्योंकि सांप्रदायिकता के खिलाफ वह लड़ाई लड़ते आए हैं. जबकि दूसरी धारा में वे नेता हैं जो चाहते हैं कि जदयू के साथ तालमेल हो क्योंकि चारा घोटाले में लालू प्रसाद सजा पा चुके हैं और इस समय देश में दूसरी हवा बह रही है. राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वह जो मुहिम चला रहे हैं उसमें कोई ब्रेक लगे. दूसरी तरफ लालू प्रसाद की रणनीति है कि कुछ भी हो और चाहे कोई भी कीमत क्यों नहीं देनी पड़े कांग्रेस का साथ लिया जाए. एक बार कांग्रेस का साथ मिल गया तो रामविलास पासवान को तो मना ही लेंगे. लालू प्रसाद ने इस सिलसिले में दो बार फोन से रामविलास पासवान से बात की है और उन्हें यह समझाने का प्रयास किया है कि आपको नुकसान नहीं होगा. यह भी प्रस्ताव लालू प्रसाद की तरफ से गया है कि दही चूड़ा के दिन या तो मैं आपके यहां आ जाऊं या फिर आप दही चूड़ा खाने मेरे यहां आप आ जाएं ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो सकें. लोजपा की तरफ से अभी इस प्रस्ताव का कोई जबाव नहीं दिया गया. लोजपा कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रही है अगर कांग्रेस उसे सम्मानजनक सीट दिलवा पाई तो फिर गठबंधन बच सकता है लेकिन अगर कांग्रेस खुद जदयू के साथ जाने का फैसला कर लेती है तो फिर तो लालू अकेले पड़ जाएंगे और लोजपा–कांग्रेस और जदयू का गठबंधन मकर संक्रांति के बाद अस्तित्व में आ जाएगा. कांग्रेस का एक खेमा हिसाब–किताब जोड़ रहा है कि पार्टी अकेले लड़े तो क्या हर्ज है? इसलिए कि केंद्र में सरकार बनाने के नाम पर भाजपा विरोधी वोटर सीधे कांग्रेस से जुड़ेंगे. उनकी नजर अल्पसंख्यक वोटरों पर है. कांग्रेस की राज्य इकाई इन दिनों पिछले चुनाव के आधार पर लड़ने लायक सीटों की तलाश कर रही है.

परिणाम का विश्लेषण तीन आधार पर किया जा रहा है. इसमें जीती हुई दो सीटें हैं. ये हैं सासाराम और किशनगंज. दूसरे नंबर की सीटों के तौर पर सीतामढ़ी, सुपौल एवं पूर्णियां की शिनाख्त की गई हैं. कांग्रेस ने पूर्णियां में निर्दलीय को समर्थन किया था. कांग्रेस के उम्मीदवार तीन सीटों पर एक लाख से अधिक वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे. ये सीटें हैं मधुबनी,मुजफफरपुर एवं खगड़िया. इसके अलावा 15 ऐसी सीटों की भी पहचान की गई हैं, जहां कांग्रेस को 50 हजार से अधिक और एक लाख से कम वोट मिले थे. इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, झंझारपुर, अररिया, मधेपुरा, महाराजगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, पटना साहिब, काराकाट, औरंगाबाद, गया एवं जमुई लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं. लेकिन जो नए राजनीतिक हालात बने हैं उनसे लगता है कि कांग्रेस बिहार में गठबंधन की राजनीति ही करेगी. इधर भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है. प्रत्याशियों को लेकर कुछ दिक्कत बनी हुई है लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि दही चूड़ा के बाद गठबंधन का ऐलान हो जाएगा. जहां तक जदयू का सवाल है तो वह तो लोजपा से तालमेल को लेकर आगे बढ़ गई है. अगर किसी वजह से बात नहीं बनी तो फिर वाम दलों को साथ लाया जाएगा और दूसरे दलों के कुछ बड़े नेताओं को शामिल कराया जाएगा. लेकिन पूरी तैयारी है कि कांग्रेस और लोजपा के साथ एक मजबूत गठबंधन बने. चूंकि सूबे की चालीस सीटें दांव पर हैं इसलिए हर दल अपने को मजबूत कर लेना चाहता है और एक ऐसे गठबंधन की चाहत रख रहा है जो सामाजिक व राजनीतिक तौर पर उसे फायदा पहुंचा सके. अब इतने दिनों की कवायद का क्या असर होता है और कौन सी तस्वीर बनती है इसके लिए तो मकर संक्रांति तक इंतजार करना ही पड़ेगा.

राजद महागठबंधन: राजद प्रमुख लालू प्रसाद के प्रस्तावित महागठबंधन का अभी स्वरूप तय भी नहीं हुआ है और उसे चुनौती मिलनी शुरू हो गई है. चुनौती बाहर से नहीं, बल्कि अपनों से ही है. राजद के ही कई नेता लोकसभा सीट के लिए दावेदार हैं. सार्वजनिक तौर पर नहीं, पर वे मन बना चुके हैं कि पार्टी ने उनका टिकट काटा तो वह निर्दलीय रूप से भी चुनाव मैदान में उतरेंगे. उन्हें यह आशंका है कि राजद –कांग्रेस–लोजपा गंठबंधन में उनके निर्वाचन क्षेत्र का टिकट दूसरे दल के हिस्से में चला जाएगा. सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति राजद प्रमुख के खुद की सीट छपरा, पाटलिपुत्र और मधेपुरा को लेकर है. मधुबनी, किशनगंज, जमुई, खगड़िया और मोतिहारी में गंठबंधन को लेकर पार्टी नेतृत्व परेशान हैं.

अखिलेश व अशोक बने अहम: मोतिहारी में पिछले चुनाव में राजद के उम्मीदवार डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह थे, इस बार वह कांग्रेस में शामिल हैं. उनकी लॉबिंग मजबूत बताई जा रही है. राजद की ओर से भी सीट पर मजबूत दावेदारी है. वहां राजद के नेता प्रो. गुलाम गौस समेत कई नेता अपनी दावेदारी नेतृत्व के समक्ष जता चुके हैं. जमुई से पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी पार्टी के उम्मीदवार थे. उन्हें अच्छा खासा वोट मिला था. अगर कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी करती है, तो राजद–लोजपा के उम्मीदवारों को मनाना होगा. पाटलिपुत्र और पटना साहिब से राजद के उम्मीदवार कौन होंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है. पाटलिपुत्र से राज्यसभा सांसद रामकृपाल यादव और पटना साहिब से फतुहा के विधायक डॉ. रामानंद यादव व बख्तियारपुर के विधायक अनिरुद्ध यादव भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है. अब गठबंधन में यह सीट किस दल के हिस्से जाएगी, यह भी समीकरण पर ही निर्भर करेगा. दोनों ही सीटों पर लोजपा और कांग्रेस की भी दावेदारी है. कांग्रेस की रंजीता रंजन पिछले चुनाव में सुपौल लोकसभा सीट से उम्मीदवार थी. फिलहाल लालू प्रसाद गठबंधन का ताना–बाना बुनने के लिए दिल्ली प्रवास पर हैं. पार्टी में टिकट के कई दावेदार दिल्ली में कैंप कर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. क्या झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी राजद कांग्रेस के सामने झुक जाएगी? ये सारे सवाल अनुत्तरित हैं.■

सम्राट या कैसर

खगड़िया से राजद के मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी ताल ठोंक रहे हैं. नेतृत्व ने उन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा था. अभी वहां से जदयू के दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं. पिछले चुनाव में राजद ने डॉ. आरके राणा को उम्मीदवार बनाया था और वह दूसरे स्थान पर थे. कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर उम्मीदवार थे और अल्पसंख्यक मतों के कारण अभी उनकी दावेदारी मजबूत है. इसी तरह से आरा संसदीय सीट से राघवेंद्र प्रताप सिंह राजद से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं. आरा सीट पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा के खाते में थी और यहां से राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह उम्मीदवार थे.

सिद्दीकी या शकील

पार्टी सूत्रों के अनुसार मधुबनी संसदीय सीट से पिछले चुनाव में भाजपा के हुकुमदेव नारायण यादव से राजद के प्रत्याशी रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी मात्र 5200 वोट से हारे थे. तीसरे स्थान पर कांग्रेस के शकील अहमद थे. इस सीट पर दावेदारी दोनों ही जता रहे हैं. यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या करेंगे? यह भी राजद के लिए परेशानी है. किशनगंज सीट से अभी कांग्रेस के असरारुल हक सांसद हैं, लेकिन वहां से राजद के अख्तारुल इमान अपनी दावेदारी जता रहे हैं. मो इमान कोचाधामन के राजद विधायक हैं और उन्हें पार्टी नेतृत्व ने चुनाव की तैयारी करने का निर्देश भी दे रखा है

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

पोशाक राशि का वितरण

[illegible]

खगड़िया को केंद्र का तोहफा

[illegible]

उन्होंने कहा कि माधुरी सेवा न्यास अपने तकनीकी शिक्षण संस्थान के जरिए हम क्षेत्र से बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं.

– नन्द किशोर शर्मा

प्रत्याशी का रोड शो

पिछले दिनों चतरा लोकसभा क्षेत्र में ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी के उम्मीदवारों ने रोड शो किया. रोड शो के बाद से कई पार्टियों में बेचैनी देखी जा रही है. खासकर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी ज्यादा ही परेशान हैं. इसकी वजह यह है कि रोड शो तिलेश्वर साहू ने किया और भाजपा व कांग्रेस को वैश्य समाज से काफी उम्मीद है जो तिलेश्वर साहू के आने के बाद से डगमगाता नजर आ रहा है. कहा जाता है कि साहू का वैश्य समाज पर अच्छी पकड़ है. बताते चलें कि अर्जुन मुंडा के कार्यकाल के समय तिलेश्वर प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं. यह भी जान लें कि इस लोकसभा में वैश्य समाज का वोट अस्सी हजार के आसपास है. यही वजह है कि आजसू पार्टी ने तिलेश्वर को अपना उम्मीदवार बनाया है.

– अमरेंद्र प्रताप सिंह

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू
Contact : 9386595926, 9334115955

घुटना शरीर का सबसे सहायक अंग
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
नववर्ष की शुभकामनाएं
डॉ. प्रवीण कुमार आर्थो, (पटना)

घुटना शरीर में सबसे बड़ा संयुक्त है कुल घुटने बदलने की सर्जरी से रोगी सामान्य जीवन में लौटने में सक्षम हो जाते है. पटना के जानेमाने आर्थोपेडिक सर्जन डॉ.प्रवीण कुमार ने एक विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। घुटने बदलने से रोगी को दर्द से राहत और विकृत पैर सही करने में मदद करता है और रोगी सामान्य गतिविधियां शुरु कर सकते हैं। घुटने गंभीर रुप से गठिया या चोट से क्षतिग्रस्त हो या इसका अचानक शुरुआत भी संभव है, हालांकि आम तौर पर गठिया के साथ दर्द धीरे–धीरे विकसित हो जाता है, घुटने मोड़ने में मुशिकल या कठोर और सूजन, बैठने या नीचे झूकने में तकलीफ ,दवायों का बेअसर हो जाने पर घुटने बदलवाने पड़ते हैं। आर्थोपेडिक सर्जन 2–3 दिन ऑपरेशन से पहले रोगी के साथ एक पूर्ण शरीरिक परीक्षा शेडयूल करते है, व्यायाम विशेष रुप से सर्जरी के बाद और पहले कुछ हफ्तों के दौरान घर की देखभाल में करवाये जाते हैं। पहले 6 हफ्तों के भीतर शरीरिक थेरेपी भी बहुत महत्वपूर्ण है शारीरिक चिकित्सा घुटने की गति में सुधार लाता है और सर्जरी के 3 से 6 सप्ताह के भीतर रोगी दैनिक जीवन शुरु करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रस्तुति: अमृता कुमारी

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

सरकार करवा रही लोक शिक्षकों की फजीहत

इनजेमाम हक/मुकुल पाण्डेय

[illegible]

feedback@chauthiduniya.com

गया जदयू में घमासान की आहट

सुनील सौरभ

[illegible]

... के दिनों की याद कराया और कहा कि किसी एक वर्ग, जाति नहीं बल्कि सभी लोगों ने अपना मत देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया. इस बैठक में अतिपिछड़ा वर्ग से आने वाले और लगातार तीन बार विधानसभा का चुनाव लड़कर बुरी तरह पराजित हो चुके जदयू नेता के यह कहे जाने पर कि सिर्फ अतिपिछड़ा, महादलितों [illegible] लगातार मुखिया रहे हैं. इस बैठक में जदयू के पुराने कार्यकर्ता अपने मान-सम्मान के लिए गया में आगामी 19 जनवरी को आयोजित होने वाली संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष भी अपनी बात कहेंगे, यह भी एहसास कराया. ■

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा। रिचा स्वामी, राजस्थान
उत्तर : आप CINERARIA MARITIMA REPL दिन में 2 बार दोनों आँखों में 2-2 बूंद डालें। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चालू रखें। आपको स्थायी निदान मिलेगा। क्योंकि यह बाजार में अन्य आईड्रॉप से अधिक प्रभावशाली व परिष्कृत है।
प्रश्न : डॉ साहब मेरी उम्र 23 वर्ष है, गलत आदतों के कारण अत्यधिक कमजोरी है, इच्छा मात्र से ही असंयमित हो जाता हूँ। मधुरेन्द्र, देहरादून
उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें निश्चित फायदा होगा।
प्रश्न : मेरी आयु 33 वर्ष है एवं मैं विवाहित हूँ पेशाब में धातक्षीणता की शिकायत है। जिससे मैं कफी चिंतित रहता हूँ। कोई अच्छा और हानिरहित उपाए बतायें। आविद, फिरोजाबाद।
उत्तर : आप निराशा मन से निकाल दें और विगोरा 5000 की 6 शीशी का कोर्स करें एवं विगोरा ऑयल से मालिश करें। यह होमियोपैथिक लिक्यूड दवा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
प्रश्न : मेरी उम्र 54 साल है, मैं बाबासीर का मरीज हूँ, पिछले कुछ दिनों से इच्छा होते हुए भी समर्थ नहीं हो पाता हूँ। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर
उत्तर : सुधीर जी! बाबासीर की रोकथाम के लिये आप पाइलेलैक्स लिफलेट के निर्देशानुसार इस्तेमाल करें और विगोरा 5x का 6 शीशी का कोर्स करें और सुबह-शाम हाई पावर मुसली आयल से दो महीने तक लगातार मालिश करें। आपको लाभ होगा।
प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 68 वर्ष है। शरीर से बिल्कूल स्वस्थ्य हूँ, लेकिन इच्छाशक्ति के रहते हुये भी शरीर साथ नहीं देता। कोई आयुर्वेदिक तात्कालिक समाधान बतायें। जगदीश प्रसाद, झरिया।
उत्तर : आप सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आयुर्वेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
प्रश्न : पिछले 7-8 वर्षों से मेरे घुटनों और कमर में बहुत दर्द रहता है। दर्द की वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो गया है कोई आयुर्वेदिक उपचार बतायें। देवंती सिंह, दिल्ली
उत्तर : आप ऑर्थोविट कैप्सूल सुबह-शाम एक कैप्सूल लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालिश करें काफी लाभ होगा।
प्रश्न : मेरी उम्र 24 वर्ष है। अविकसित सीना के कारण हीन-भाव से ग्रसित हूँ। आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।
उत्तर : सीना का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।
प्रश्न : बालों के निरन्तर झड़ते रहने के कारण सिर पर गंजापन हो गया है, मैं इस समस्या से बहुत चिन्तित हूँ, उपाय बतायें । उपेन्द्र सिंह, कानपुर
उत्तर : बालों के झड़ने, टुटने से बचने के लिए आप केशवर्धक तेल का नियमित इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बाल झड़ना एवं टूटना तत्काल समाप्त हो जायेगा।
प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून
उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें
9304291051

किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

ऐतिहासिक धरोहरों पर भूमाफियाओं की नजर

नीरज/कुलभूषण

बिहार के सीमांचल का इलाका कई वजहों और विवादों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है. लेकिन हाल के दिनों में इन इलाकों में भूमि विवाद एक नई समस्या बन कर उभरी है. साथ ही वहां का प्रशासन, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वाली कहावत को चरितार्थ करता है. जिले की प्रशासनिक उदासीनता की वजह से यहां के भूमि विवाद की जड़ें गहरी होती जा रही हैं. यही वजह है कि इन विवादों में आए दिन खून–खराबे की खबरें आती रहती हैं.

बताते चलें कि भूमाफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब वे ऐतिहासिक व पुरातात्विक धरोहरों और सरकारी जमीनों को भी खरीदने–बेचने लगे हैं. जहां पूर्णियां के धमदाहा में भूमि विवाद को लेकर खूनी खेल जारी है वहीं दूसरी ओर किशनगंज के पोठिया, ठाकुरगंज जैसे प्रखंडों के चाय बगानों में भूदान, बिहार सरकार बंदोबस्ती व लाल कार्ड के जमीन को लेकर आदिवासियों समेत आमलोगों का संघर्ष जारी है. मालूम हो कि सीमांचल अर्थात पुराना पूर्णियां जिला नदियों एवं वनों से आच्छादित था. यहां की लगभग 5800 एकड़ भूमि बिहार सरकार के अन्तर्गत मानी जाती थी लेकिन बदलते परिवेश में इसमें से अधिकतर भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया. यह भी सच है कि सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से ही ऐसा संभव हो सका है. पूर्णियां का कुंडी पुल, सौरा नदी, किशनगंज का रमजान नदी, कटिहार और अररिया शहर से बहनेवाली नदियां अतिक्रमण की शिकार हो गई हैं और आज वहां आलिशान व नए–नए भवन उग आए हैं. नाले का भी अतिक्रमण हुआ, जिसमें बिहार की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग कृषि उत्पादन बाजार समिति पर अतिक्रमण कर मार्केट का निर्माण कर दिया गया. दूसरी तरफ किशनगंज के प्रसिद्ध मारवाड़ी कालेज की कुल 75 एकड़ भूमि में से 25 एकड़ भूमि को भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल संजय सिंह का कहना है कि कॉलेज की 25 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जाधारियों द्वारा पक्का भवन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन, प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर राज्य सरकार तक को लिखा गया लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई समुचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है. पूर्णियां के परोरा स्थित मिल्लिया शिक्षा संस्थान के लगभग 100 एकड़ जमीन को मुख्यमंत्री के 15 दिसम्बर को होने वाली संकल्प यात्रा से दो दिन पहले प्रशासन द्वारा खाली कराया गया. यहां पिछले 16 महीनों से आदिवासियों द्वारा लाल कार्ड व बिहार सरकार की 20 एकड़ जमीन शामिल होने की बात बताकर आदिवासियों द्वारा कब्जा जमाया गया था. किशनगंज के मारवाड़ी कालेज की जमीन का अतिक्रमण मुक्त नहीं होना. वहीं मिल्लिया शिक्षा संस्थान [illegible]

पूर्णियां का कुंडी पुल, सौरा नदी, किशनगंज का रमजान नदी, कटिहार और अररिया शहर से बहनेवाली नदियां अतिक्रमण की शिकार हो गई हैं और आज वहां आलिशान व नए-नए भवन उग आये हैं. नाले का भी अतिक्रमण हुआ, जिसमें बिहार की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग कृषि उत्पादन बाजार समिति पर अतिक्रमण कर मार्केट का निर्माण कर दिया गया . दूसरी तरफ किशनगंज के प्रसिद्ध मारवाड़ी कालेज के कुल 75 एकड़ में से 25 एकड़ भूमि को भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है.

[illegible] जा रहा है. अब तो यहां ऐतिहासिक, पुरातात्विक धार्मिक महत्व के मंदिर, ट्रस्ट की जमीन की खरीद–बिक्री भी चालू हो गई है. एम्बीशन कोचिंग शिक्षण संस्थान के निदेशक अमित सिन्हा पर पूर्णियां सिटी में स्थित विश्व प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर ट्रस्ट की भूमि कि खरीद बिक्री का आरोप लगा है. इस संबंध में पूर्णियां सिटी स्थित सीताराम लक्ष्मण एवं उदासी संगत बाड़ी ट्रस्ट के अस्थाई न्यासधारी संत मदन दास ने जो दस्तावेज सौंपे और जो जानकारी दी उसके अनुसार पूर्णियां सिटी के बसंतबाग में स्व. राजा पृथ्वी चंद लाल के द्वारा सीताराम लक्ष्मण एवं इदासी संगत बाड़ी ट्रस्ट में लगभग 90 बीघा जमीन व पूर्णियां जक्शन [illegible] लाल की बुरी नजर ट्रस्ट और मंदिर की जमीन पर पड़ी. जिस कारण प्रदीप चंद लाल द्वारा ट्रस्ट की जमीन को बेचने के ख्याल से कागजी हेर–फेर किया जाने लगा और धीरे–धीरे जमीन को बेचा जाने लगा. वहीं परिसर स्थित आम, कटहल के फलदार वृक्षों को उनके द्वारा कटवाकर अवैध रूप से बेच डाला गया. सूत्रों ने बताया कि एक साजिश के तहत त्रिपुर सुंदरी मंदिर से पहले बहुमूल्य अष्टधातुओं की मूर्तियों को इनलोगों के द्वारा चोरी करवा दिया गया. मदन दास का कहना है कि विरोध करने पर मेरे ऊपर कई बार हमला करवाया गया और धमकाया गया और अब तो प्रदीप की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी द्वारा [illegible] कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अब बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद पटना के अध्यक्ष किशोर कुणाल को आवेदन देकर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है. मालूम हो कि पूर्णियां सिटी स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर विश्व प्रसिद्ध था जहां पड़ोसी देश नेपाल व भूटान से भी लोग पूजा करने आया करते थे. विश्व

में तीन ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर था जिसमें से एक नेपाल के काठमांडू में स्थित है दूसरा त्रिपुरा के अगरतला में जबकि तीसरा पूर्णियां सिटी में स्थित है. दस्तावेज के हिसाब से सीताराम लक्ष्मण एवं उदासी संगत बाडी ट्रस्ट बसंतबाग पूर्णियां सिटी एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्याय अधिनियम 1950–1951 की धारा 34 के तहत परिषद में निबंधित है और उसकी निबंधन संख्या 2164 है. वर्तमान में महंथ मदन दास इसके अस्थाई न्यायधारी हैं. राज्य धार्मिक न्याय परिषद पटना में इस ट्रस्ट के द्वारा वित्तीय वर्ष 1951–52 से लेकर 1977–78 के बीच का कुल राजस्व शुल्क 288 रूपया 59 पैसा, दिनांक 22.03.1995 को जमा कराया गया था. बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के पूर्व के कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा पत्रांक 3886, दिनांक 29.10.02 को पुर्णियां पूर्व के प्रखंड के अंचलाधिकारी को भेजे गए पत्र में मदन दास को ट्रस्ट की संपत्ति सौंपने की बात कही है. इसकी प्रतिलिपि परिषद ज्ञापांक 530 दिनांक 20.06.94 को पूर्णियां के जिलाधिकारी को सूचनार्थ हेतु भेजा गया. इस संबंध में पूर्णियां के पूर्व भाजपा विधायक स्वर्गीय राज किशोर केशरी द्वारा दिनांक 13.12.09 को अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद पटना को पत्र लिखा गया था जिसमें अवैध ढंग से हो रही ट्रस्ट की जमीन बिक्री पर रोक लगाने और मदन दास को स्थाई न्यायधारी नियुक्त करने की बात कही गई थी. इन तमाम मामलों पर जब एम्बीशन के निदेशक अमित सिन्हा से बात करने कि कोशिश की गई तो वे पूर्णियां से बाहर रहने का बहाना बनाकर टालते रहे. वहीं ट्रस्ट की जमीन की खरीद में सह भागीदार और त्रिपुर सुन्दरी मंदिर के पास निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे भगत कंप्युटर के मालिक एंव डीएपीएस स्कूल के निदेशक आरके भगत से ट्रस्ट की जमीन को लेकर बात की गई तो इनका कहना था कि यह जमीन प्रदीप चंद लाल की खतियानी जमीन है जिसका नामान्तरण भी हो गया है. जब नामान्तरण करने वाले पूर्णियां पूर्व प्रखंड के पूर्व अंचलधिकारी [illegible] कारोबार नलनी लाल के साथ पूर्णियां से लेकर किशनगंज तक कर रहे हैं. पूर्णियां के स्थानीय लोगों द्वारा सुशासन में ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर ट्रस्ट के जमीन कि बिक्री पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एसएसबी के लिए चुनौती बने तस्कर

वाल्मीकि कुमार

भारत–नेपाल की खुली सीमा व दोनों देशों के बीच के मैत्री संबंधों की आड़ में असामाजिक तत्वों ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं. पिछले तकरीबन एक दशक से भारत–नेपाल खुली सीमा पर चौकसी को लेकर एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है. दोनों देश के बीच के परंपरागत धार्मिक व सामाजिक संबंधों का नतीजा है कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का नेपाल से रोटी–बेटी का संबंध रहा है. एक दूसरे के बीच संबंधों को लेकर आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है. खास कर भारतीय क्षेत्र में मैत्री संबंध विशेष तौर पर कायम रखा जा रहा है. कुछ मामलों में पूर्व की संधि को भी नजर अंदाज किए जाने की चर्चा है. इसी कारण नेपाली क्षेत्र के लोगों को भारतीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. परंतु भारतीय क्षेत्र के लोगों को नेपाली सीमा में प्रवेश के साथ ही कई नियम व कानूनों से समझौता करना मजबूरी मानी जाती है. सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया, सोनबरसा, सुरसंड व भिटठा मोड़ ऐसे स्थान हैं जहां से दोनों देशों में प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है. इसके अलावा खुली सीमा होने के कारण दर्जनों ग्रामीण इलाके भी ऐसे हैं, जहां से दोनों देशों के बीच आवागमन सुगम है. एक ओर बैरगनिया, सोनबरसा व भिटठा मोड़ में जहां चेक पोस्ट स्थापित कर नियमित आवागमन करने वाले लोगों पर स्थानीय थाना पुलिस के अलावा सीमा शुल्क कार्यालय, कस्टम कर्मी व एसएसबी के जवान पैनी नजर रख रहे है.

वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र की पगडंडी से आवागमन करने वालों पर कोई विशेष नजर चाह कर भी रखना आसान नहीं रह गया है. नतीजा है कि इन्ही रास्तों ने सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों ही देशों के बीच तस्करी के व्यापार को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है. एसएसबी की तैनाती के बाद कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्र के इन रास्तों पर भी अब तस्करों के लिए अवैध वस्तुएं पार करना आसान नहीं रह गया है. बावजूद इसके तस्करी का दौर जारी है. खुली सीमा का ही नतीजा है कि भारतीय क्षेत्र से खाद, बीज, डीजल, किरासन एवं खाद्यान्न समेत अन्य वस्तुओं की खेप नेपाली क्षेत्र तक पहुंचती रही है. इसको लेकर कई बार सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों को बैरगनिया, मेजरगंज, परिहार, सोनबरसा व सुरसंड समेत अन्य स्थानों पर तस्करी में संलिप्त तत्वों के संगठित गिरोह की साजिश का भी सामना करना पड़ा है. दूसरी ओर कुछ स्थानों पर जवानों की मनमानी को लेकर भी आंदोलन होते रहे हैं. इन तमाम बातों के बाद भी फिलहाल एसएसबी की चौकसी तस्करों के लिए एक मुसीबत से कम नहीं है. एसएसबी के 20 वीं बटालियन के कमांडेंट बी विक्रमण एवं सहायक कमांडेंट राजन राय के कुशल नेतृत्व में जवानों ने बेशुमार उपलब्धियों को बटोरने में कामयाबी पाई है. वर्ष 2013 में 1 मार्च को सुरसंड प्रखंड के बुढ़्रा पोखर के समीप एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी. गुप्त सूचना के आधार पर नेपाल से भारतीय क्षेत्र में लाए जा रहे करीब 1 करोड़ 11 लाख 60 हजार रुपये मूल्य के 9.3 किलोग्राम चरस को भिटठा मोड़ से पटना जा रही एक यात्री बस बीआर – 016– 3278 से बरामद कर थाना पुलिस को सौंपा था. दूसरी

सफलता मुजफ्फरपुर–दरभंगा एनएच पर 9 अप्रैल 13 को मिली थी. इसमें मुजफ्फरपुर के बैरिया निवासी जवाहर साह का पुत्र प्रमोद साह को 5 सौ के 2 हजार पीस यानि कुल 10 लाख नकली भारतीय रुपये के साथ पकड़कर अहियापुर थाना पुलिस के हवाले किया था. गत महीने की 17 तारीख को सीतामढ़ी–सोनबरसा एनएच – 77 के कमलदह गांव के बहुरहिया देवी मंदिर के समीप से नेपाल ले जाए जा रहे यूएसए निर्मित 2 पिस्टल, देशी 3 पिस्टल, नारंगी और सफेद रंग का 5 किलो विस्फोटक, 3 पिस्टल मैगजीन, 8 एमएम का 19 एवं 7.65 एमएम का 10 कारतूस के अलावा दो मोबाईल के साथ मेहसौल चौक निवासी तुफैल अहमद व मंगरा को एसएसबी के स्पेशल कमांडों ने पकड कर बथनाहा थाना पुलिस को सौंपा था. मई महीने की 18 तारीख को जनकपुर के नेपाल राष्ट्रीय बैंक लूट की योजना को अमलीजामा पहनाने जाने के क्रम में एनएच–104 के बथनाहा थाना अन्तर्गत रामपुर इनरवा के समीप 315 बोर के 3 देशी पिस्टल, 8 एमएम के 8 कारतूस एवं एक हीरो होंडा बाइक के साथ बथनाहा थाना के झटौलिया निवासी वीरेंद्र राइत, झिटकहिया निवासी गणेश प्रसाद यादव एवं सोनबरसा थाना के बेला निवासी चंदन कुमार को पकड़कर बथनाहा थाना पुलिस के हवाले किया था. सफलताओं की कड़ी

में जून माह का 28 तारीख एसएसबी के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन साबित हुआ. एसएसबी जवानों ने परिहार थाना के सासाराम गांव के पीलर संख्या– 306 व 307 के बीच भारतीय क्षेत्र से नेपाल ले जाए जाने के दौरान करीब 2 करोड़ रुपये मूल्य के 10 किलोग्राम चरस, एक देशी पिस्टल एवं 8 एमएम के 5 कारतूस के साथ परिहार थाना के बारा निवासी मुकेश साह को पकड़कर परिहार थाना पुलिस के हवाले किया था. 30 अक्टूबर को मेजरगंज क्षेत्र में तैनात जवानों ने पीलर संख्या – 335 –13 के समीप से 9 देशी पिस्टल, 2 देशी रायफल एवं होंडा शाइन बाइक के अलावा कई कारतूस भी बरामद किया गया था. परंतु कोहरे के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी थी. इन उपलब्धियों ने अब तक यह तो साबित कर ही दिया है कि भारत–नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी के बाद भी तस्कर व असामाजिक तत्वों की आवाजाही बदस्तूर जारी है. एसएसबी की सफलता में श्वान दस्ता का भी सराहनीय सहयोग रहा है. वर्ष 2010 से लेकर अब तक दर्जनों चोरी, हत्या, डकैती व तस्करी समेत अन्य मामलों में श्वान दस्ता ने सफलता दिलाने में कामयाबी पायी है. भारत– नेपाल सीमा के सीतामढ़ी जिले में भांगा, कोल्हुआ चैनपुर, बैरगनिया, मेजरगंज, हरपुर कला व बसबीट्टा समेत अन्य जगहों पर निगरानी के लिए तकरीबन डेढ़ हजार एसएसबी के जवानों को लगाया गया है. करीब 1 सौ किलोमीटर सरहद की निगरानी के लिए तैनात जवान चाहे कितने भी चौकस क्यों न हो, परंतु लंबे अर्से से चल रही तस्करी के धंधे पर पूर्णत: रोक लगाना आसान नहीं दिख रहा है. एसएसबी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आम लोगों से बेहतर संबंध कायम रखने को लेकर समय–समय पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता रहा है. जवानों की प्रेरणा से कुछ हद तक लोगों का सहयोग भी मिल रहा है. जबकि बढ़ती आपराधिक गतिविधियों एवं तस्करी पर अंकुश के लिए अभी कड़ी मशक्कत की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सासाराम से लड़ेंगे कामेश्वर बैठा!

ममता चौहान

कैमूराचंल की घाटी में दो दशकों तक बंदूक और बारूद की खेती कर चुके और कभी पीपुल्सवार ग्रुप के जोनल कमांडर रह चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद कामेश्वर बैठा की रोहतास जिले में कुछ ज्यादा ही गतिविधियां बढ़ी है. यह गतिविधी बंदूक और बारूद की नहीं बल्कि राजनीतिक है. वह भी सासाराम सुरक्षित लोकसभा सीट के लिए. जहां पहले से ही मैडम स्पीकर मीरा कुमार का कब्जा है. पहले तो कामेश्वर बैठा क्षेत्र में आते–जाते और लोगों से मिलते जुलते ही देखे गए लेकिन 22 दिसंबर को पप्पू यादव की आशीर्वाद यात्रा वाली जन सभा में जब मंच पर पहुंचे तो लगा कि बात में कुछ दम है. रही सही कसर तब पूरी हुई जब इस मंच पर कामेश्वर बैठा ने यह कहकर पूर्व विधायक रामचंद्र यादव को गले लगाया की कल तक हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे अब दोस्त होने वाले हैं. यहां बताते चलें कि 1990 से लेकर 2009 तक कैमूरांचल में जब प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्सवार ग्रुप के जोनल कमांडल कामेश्वर बैठा हुआ करते थे

पहले तो कामेश्वर बैठा क्षेत्र में आते-जाते और लोगों से मिलते जुलते ही देखे गए लेकिन 22 दिसंबर को पप्पू यादव की आशीर्वाद यात्रा वाली जन सभा में जब मंच पर पहुंचे तो लगा कि बात में कुछ दम है. रही सही कसर तब पूरी हुई जब इस मंच पर कामेश्वर बैठा ने यह कहकर पूर्व विधायक रामचंद्र यादव को गले लगाया की कल तक हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे अब दोस्त होने वाले हैं.

तब कैमूर की दूसरी शक्ति रामबचन यादव और रामचंद्र यादव के सामने उनकी बंदूक खूब गरजती थी. तब यह लड़ाई कैमूर पहाड़ी पर वर्चस्व को लेकर थी. समय ने करवट ली और कामेश्वर बैठा झारखंड से सांसद बने और रामचंद्र यादव भभुआ से विधायक. यहां से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा में कभी भी दोनों आमने सामने नहीं हुए. परंतु सासाराम में जब पप्पू यादव की आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई तो दोनों एक साथ मंच पर आ पहुंचे. मंच पर पहुंचने के बाद कामेश्वर बैठा ने जो बात कही वह कहीं ना कहीं सासाराम लोकसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ी थी. हालांकि राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की भी है की कामेश्वर बैठा कांग्रेस छोड़कर अन्य सभी दरवाजों पर अपनी उम्मीदवारी की दस्तक दे चुके हैं. भले हीं अधिकृत रूप में कोई बयान सामने नहीं आया. अगर कामेश्वर बैठा लोक सभा चुनाव में सासाराम से उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम चाहे जो भी हो लड़ाई मजेदार होगी क्योंकि इस लड़ाई में प्रशासन को भी निष्पक्ष चुनाव करा लेने में एड़ी चोटी एक कर देना होगा. फिलहाल कामेश्वर बैठा ने इतना ही कहा है कि पहले जन संघर्ष में इन हाथो ने बंदूक थामी थी, अब जन सेवा की बारी है. जिसकी शुरुआत मैंने झारखंड से की है. आगे आम लोगो की मर्जी. ■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

बाहरी का बहिष्कार

चतरा लोकसभा क्षेत्र को लेकर दो बातें प्रचलित हैं. पहला यह कि ये राजद का गढ़ है और दूसरा ये कि यह सीट हमेशा से बाहरी नेताओं के प्रतिनिधित्व में रहा है लेकिन इसबार बाहरी नेताओं की राह यहां से आसान नहीं होगी. चतरा के लोगों ने ऐलान किया है कि बाहरी और बिहारी नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा. राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रदेव गोप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुर्गाशंकर सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष विनय सिंह सहित अन्य लोगों को भी इस मुहिम का समर्थन है. इसी क्रम में राजद के प्रदेश प्रवक्ता मो इस्लाम ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलकर क्षेत्र से अगामी लोकसभा में राजद के प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाने का दबाव बनाया है. सूत्र बताते हैं कि अगर गिरिनाथ सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो प्रदेश राजद में बगावत के सुर भी उभर सकते हैं.

–अमरेंद्र प्रताप सिंह

स्थापना दिवस मना

पिछले दिनों पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस के ललित आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला की अगुआई में कार्यकर्ताओं ने सेवादल के साथ पार्टी ध्वज फहरा कर संगठन की मजबूती के साथ ही पार्टी हित में सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया. कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सीताराम झा, डॉ. भुवनेश्वरी मिश्र, सत्येंद्र तिवारी, प्रो. बच्चा मिश्र, संजय विरख, राजीव कुमार काजू, अफाक खां, शिव शंकर शर्मा, अंजारुल हक तौहिद, वीरेंद्र कुशवाहा, आलोक कुमार, संजय कुमार, अमित कुमार, विजय सिंह, डॉ मोबिनुल हक, त्रिलोकी यादव, प्रमोद नील व ज्वाला प्रसाद समेत अन्य थे.

– ब्रजेश कुमार

प्रशिक्षण का आयोजन

नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में ब्यूटी पार्लर व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन केंद्र के सभागार में किया गया. उद्घाटन गांव विकास मंच के संस्थापक नागेंद्र प्रसाद सिंह, मो. अफाक खां, रकटू प्रसाद व लेखापाल हर्षनाथ झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन सोफिया जकीर व धन्यवाद ज्ञापन दिग्विजय सिंह ने किया. मौके पर बेबी सिंह, सविता गुप्ता, अनिता गुप्ता, डेजी, कंचन, पिंकी, कुमारी प्रियंका, अभिलाषा, रिजवाना, आशा, उर्मिला व नेहा समेत अन्य थे.

मनेगी कर्पूरी जयंती

सीतामढ़ी शहर के सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक उपाध्यक्ष सीताराम राय की अध्यक्षता में हुई. बैठक का संचालन श्यामचंद्र सिंह अमिताभ ने किया. मौके पर प्रदेश महामंत्री व विधायक विनय कुमार सिंह ने कहा कि 14 से 16 जनवरी तक लौह संग्रह के लिए प्रखंडो में बैठक बुलाई जाएगी. 21 जनवरी तक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाएगी. बैठक में विधायक दिनकर राम, मोतीलाल प्रसाद, राम नरेश प्रसाद यादव, विधान पार्षद वैद्यनाथ प्रसाद, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश सिंह, जिला महामंत्री सुरेंद्र झा, मंत्री चंद्रशेखर पाठक, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कार्तिकेश झा, डॉ कुमकुम सिन्हा, रामचंद्र सिंह, संजीव चौधरी, अर्पणा शर्मा, उपेंद्र शुक्ल, रामा शंकर प्रसाद व विजय प्रसाद स्वर्णकार समेत अन्य थे.

– वाल्मीकि

साधु समाज का आन्दोलन

भारत साधु समाज के संस्थापक महामंत्री स्वामी हरिनारायणानंद जी महाराज ने कहा कि सार्वजनिक जीवन व प्रशासन तंत्र में व्याप्त मूल्यहीनता को नियंत्रित करने के लिए बिहार में आध्यात्मिक एवं सामाजिक जागरण अभियान का उद्घाटन आगामी 2 फरवरी को सीतामढ़ी में किया जाएगा. भवदेपुर के ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में संत जी ने कहा कि पिछले 10 सालों में राज्य सरकार की हिंदू धर्म स्थानों के प्रति उपेक्षा के कारण पांच दर्जन से अधिक मठों को ध्वस्त कर दिया गया है. नतीजतन हजारों गरीबों के लिए जीवन यापन एक चुनौती बन गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मठों को जीवंत बनाने के लिए 10 करोड रुपये देने का भरोसा दिलाया था. नए वित्तीय वर्ष में उक्त राशि का आवंटन नहीं किए जाने पर आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दो दिवसीय अधिवेशन में पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, महंत जनमेजय शरण, महंत माधव दास, स्वामी असंगानंद सरस्वती, रामानुजाचार्य स्वामी रंगरमाचार्य जी प्रभृति समेत 5 सौ से अधिक साधु महात्मा भाग लेंगे. मौके पर साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष महंत ब्रज नारायण दास, उपाध्यक्ष महंत परमेश्वर दास, राम उदार दास, नारायण स्वरूप, दिनेशचंद्र द्विवेदी, प्रो शशि भूषण कुमार सिंह, विनय कुमार चौधरी व हरि किशोर मिश्र समेत अन्य थे.

मोदी को पीएम बनाने की अपील

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर में विधानसभा स्तरीय भाजपा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया. रामदौन हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुधीर रंजन वर्मा एवं संचालन विनोद कुमार ने किया. मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा ने आम– आवाम से महंगाई, भ्रष्टाचार समेत अन्य समस्याओं से निजात के लिए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील की. कार्यक्रम में विधायक राम सूरत राय, सुनील कुमार पिंटू, पूर्व विधान पार्षद व तिरहुत स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी राम कुमार सिंह, डुमरा प्रमुख देवेंद्र साह, रीता वर्मा, पवन कुमार उपमन्यु, चुनचुन सिंह, सुफल झा, प्रो वीरेंद्र कुमार सिंह, मनोज तिवारी, विकाश शर्मा, उदय शंकर सिंह, अशोक चौधरी, रंजन कुमार व राम नरेश पांडेय समेत अन्य थे.

– विभा सिन्हा

अतिपिछड़ा में शामिल हों तैलिक

कृष्णा प्रसाद बिहार तैलिक वैश्य सभा के अध्यक्ष चुने गए. पिछले दिनों बिहारी साव लेन स्थित साहू समाज भवन में आयोजित चुनाव में रणविजय साहू को महामंत्री, ओमप्रकाश को कोषाध्यक्ष चुना गया. डा. प्रेम कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार, डा. सुनील कुमार को उपाध्यक्ष, चंदेश्वर साह को संयुक्त मंत्री व विजय साह को संगठन मंत्री चुना गया. नए अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने कहा कि तैलिक जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कराना उनका लक्ष्य होगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसी एजेंडे पर किसी भी दल को लोकसभा और विधानसभा में समर्थन दिया जायेगा. प्रसाद ने कहा कि साहू समाज ने इनपर जो भरोसा किया है उसपर वो खरे उतरेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि साहू समाज की जितनी भी मांगे लंबित हैं उसे पूरा करने की दिशा में प्रयत्न करेंगे.

– चौथी दुनिया ब्यूरो

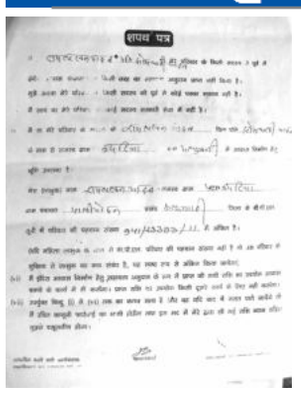

> ऐसा नहीं है कि यह जिले का पहला मामला है. पाली मोहन पंचायत के ही मो. शाबिर ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि बीडीओ विजय कुमार ने इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 353 आईडी 76286 और अंक 9 रहने के बावजूद उसे इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया. पूछे जाने पर बीडीओ ने पीड़ित को झिड़कते हुए कहा कि जिससे भी शिकायत करनी हो कर ले, जांच का जिम्मा तो मुझे ही दिया जाएगा.

भ्रष्ट अधिकारी को बचाने में जुटा महकमा

कपिल झा

रामलखन यादव मधुबनी के पाली मोहन पंचायत के निवासी हैं. न्याय के साथ विकास की बातें उनके लिए बेमानी साबित हो रही हैं. राजधानी से लेकर प्रखंड स्तर तक कैसा भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसकी बानगी है रामलखन के साथ हुई घटना. कलुआही प्रखंड के बीडीओ ने न केवल रामलखन को इंदिरा आवास के लाभ से वंचित रखा है बल्कि उसी की आईडी पर किसी और को इंदिरा आवास आवंटित कर दिया. बताते चलें कि जिस आदमी को रामलखन के बदले में अवास का आवंटन किया गया है उसका नाम भी प्रतीक्षा सूची में दर्ज नहीं है. इसका खुलासा आरटीआई से हुआ.

रामलखन ने इसकी शिकायत मधुबनी के जिलाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव व राज्य के मुख्य सचिव तक से की लेकिन हैरत की बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस बीडीओ पर आरोप लगाया गया है विभाग ने उसे ही जांच का जिम्मा सौंप दिया है. सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भी आरोपी बीडीओ पर पीडीएस के चावल की कालाबाजारी, पशु प्रगणक के जाली हस्ताक्षर से राशि गबन का आरोप और आरटीआई करने पर झूठे मुकदमें में फंसाने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं. अब इलाके के लोगों को यह बात गले नहीं उतर रही है कि जो खुद आरोपी हो उससे न्याय की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? बताते चलें कि रामलखन का प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 941, आईडी 23393 और अंक 11 है लेकिन रामलखन को लाभ न देकर अन्य क्रमांक वाले जैसे 942, 943, 944 व 953 वाले लोगों को लाभ दिया गया. बीस सूत्री कार्यक्रम के सदस्य वरुण कुमार सिंह के आरटीआई के आलोक में लोकसूचना पदाधिकारी व बीडीओ ने जानकारी दी कि वर्ष 2012–2013 में ग्रामीण बैंक कलुआही से खाता संख्या 10039430007314 के द्वारा रामलखन यादव पिता सोमधारी यादव को लाभ दिया गया. आश्चर्य की बात यह है कि लाभार्थी का नाम तक प्रतिक्षा सूची में दर्ज नहीं है. रामलखन की शिकायत पर ग्रामीण विकास विभाग के उपसचिव महेंद्र भगत ने 9–10–13 को जिलाधिकारी को जानकारी दी कि कलुआही के बीडीओ के विरूद्ध परिवाद में वर्णित विंदुओं की जांचकर आवश्यक कार्रवाई की जाए. अब विडंबना यह है कि डीएम ने जनतादरबार निबंधन संख्या 4979 के द्वारा पूरे मामले की जांच का जिम्मा कलुआही बीडीओ को ही सौंप दिया. अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे में पीड़ित को न्याय मिल पाएगा?

ऐसा नहीं है कि यह जिले का पहला मामला है. पाली मोहन पंचायत के ही मो. शाबिर ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि बीडीओ विजय कुमार ने इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 353 आईडी 76286 और अंक 9 रहने के बावजूद उसे इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया. पूछे जाने पर बीडीओ ने पीड़ित को झिड़कते हुए कहा कि जिससे भी शिकायत करना हो कर ले, जांच का जिम्मा तो मुझे ही दिया जाएगा.

और बाद में ऐसा ही डीएम ने जांच का जिम्मा आरोपी बीडीओ को ही सौंप दिया. काफी हो–हल्ले के बाद डीएम ने माना कि उनसे गलती हो गई और कहा कि यह भूलवश लिया गया निर्णय था और आगे से इसका ख्याल रखा जाएगा. अब रामलखन के मामले में भी डीएम ने भूलवश ऐसा ही निर्णय ले लिया. इससे इस बात का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि डीएम के जनता दरबार में आए मामले को कितनी गंभीरता से निपटाया जाता है. इसी बीडीओ के खिलाफ नाजिर व प्रधान लेखपाल कुमार शिव संतोष ने सदर एसडीओ से शिकायत की थी कि बीडीओ ने फर्जी हस्ताक्षर कर प्रखंड कन्या विवाह मद के खाते से 2012 के दिसम्बर में 20 लाख 39 हजार रुपये की अवैध निकासी की है. बाद में डीएम के आदेश से मामले की जांच उपसमाहर्ता रंगनाथ चौधरी व मिथिलेश के द्वारा की गई और मामले को सही पाया गया.

हैरत की बात यह है कि दोषी पाए जाने के बाद भी बीडीओ पर कोई कर्रवाई नहीं की गई और उल्टे नाजिर का स्थानांतरण कर दिया गया. इसी तरह पीडीएस चावल के कालाबाजारी में बीडीओ की संलिप्तता स्वीकार करने वाला कलुआही थानाध्यक्ष का भी स्थानांतरण कर दिया गया. उनपर इंदिरा आवास देने के नाम पर एक–एक हजार रुपये की वसूली का भी आरोप लगा चुका है. साथ ही कई आरटीआई कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि अगर आरटीआई उक्त बीडीओ के दफ्तर में गया तो समझो किसी न किसी प्रकार से वह खारिज ही हो जाएगा या फिर आरटीआई कर्ता प्रताड़ित होगा. पूरे मामले पर मधुबनी के जिलाधिकारी का कहना है कि आरोपी पदाधिकारी को जांच पदाधिकारी बनाया जाना संभव नहीं है. उस दिन मैं जनतादरबार में मौजूद नहीं था, पूरे मामले की सक्षम व वरीय पदाधिकारी से जांच कराकर यथोचित कार्रवाई की जाएगी.■

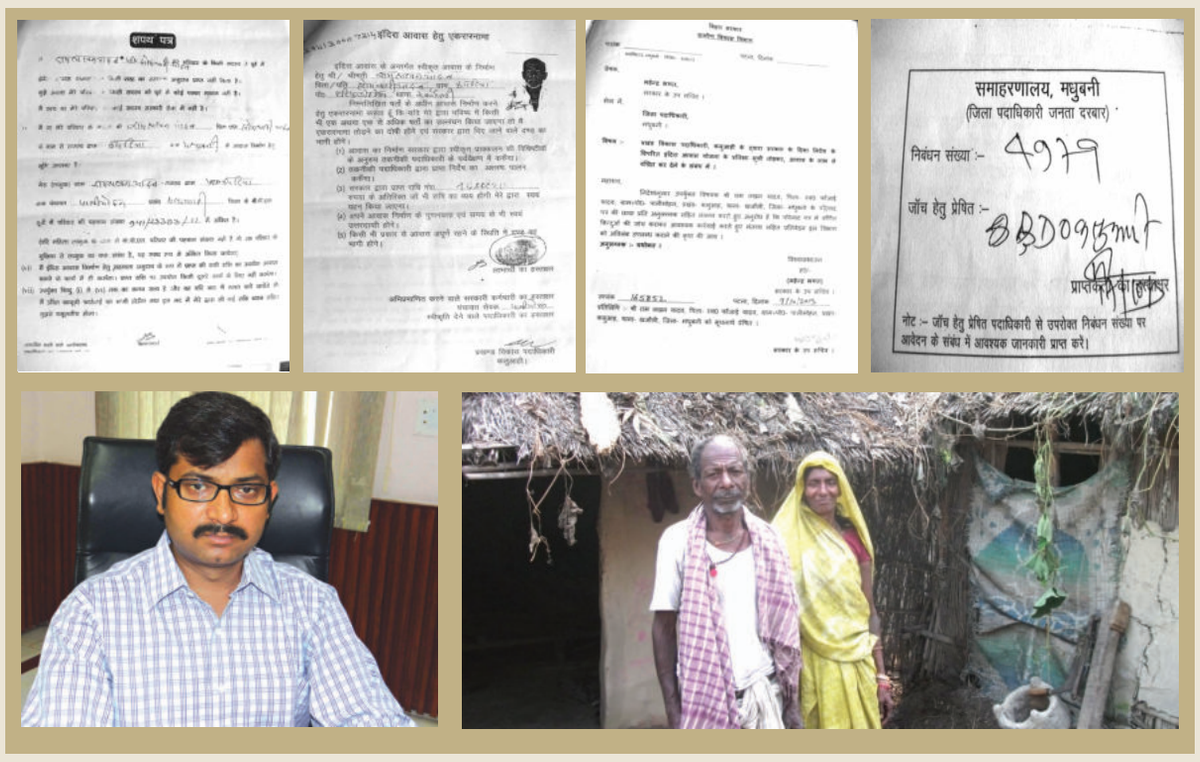

feedback@chauthiduniya.com

नववर्ष 2014 एवं गणतंत्र दिवस की समस्त
सीतामढ़ी, अररिया जिलेवासियों को
हार्दिक बधाई
प्रस्तुति
बाल्मीकि एवं अजातशत्रु

नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर जिलेवासियों समेत सम्पूर्ण राज्यवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
अमिचन्द राम
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
नरपतगंज

नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर जिलेवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
डॉ. जयनारायण प्रसाद
रेफरल प्रभारी
फारबिसगंज

गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर अररिया जिलेवासियों समेत सम्पूर्ण राज्यवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
मनचन केसरी
प्रदेश मंत्री
विश्व हिन्दु परिषद

नववर्ष 2014 एवं गणतंत्र दिवस की विधानसभा सहित
क्षेत्र की समस्त जनता को
हार्दिक शुभकामनाएं
लक्ष्मीनारायण मेहता
पूर्व भाजपा विधायक,
फारबिसगंज विधानसभा

नववर्ष 2014 एवं गणतंत्र दिवस की
फारबिसगंज नगर क्षेत्र की समस्त जनता को
हार्दिक शुभकामनाएं
वीणा देवी
मुख्य पार्षद
नगर परिषद्, फारबिसगंज

निर्मला उत्सव पैलेस
मेन रोड, राजेंद्र भवन के पीछे, सीतामढ़ी
निर्मला उत्सव पैलेस
मेन रोड, राजेंद्र भवन के पीछे,
सीतामढ़ी, बिहार
सभी प्रकार के पार्टी एवं
उत्सव के लिए उपयुक्त
नव वर्ष 2014 की हार्दिक शुभकामनाएं...

नववर्ष 2014 एवं गणतंत्र दिवस की
जिले की की समस्त जनता को
हार्दिक शुभकामनाएं
अरविंद गोयल
जिलाध्यक्ष
निवेदक
राष्ट्रीय जनता दल, व्यवसायिक प्रकोष्ट, अररिया

बाबा तपस्वी नारायण दास टीचर ट्रेनिंग 'बीएड' कॉलेज
तपस्वी नगर, दोस्तपुर, सीतामढ़ी, बिहार
नव वर्ष
की
हार्दिक शुभकामनाएं.....

नववर्ष 2014 एवं गणतंत्र दिवस की नरपतगंज विधानसभा
सहित क्षेत्र की समस्त जनता को
हार्दिक शुभकामनाएं
जनार्दन यादव
पूर्व भाजपा विधायक,
नरपतगंज विधानसभा

2014
जननायक
कर्पूरी ठाकुर
विचार केंद्र
नया साल सूबे बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त कर
विश्व पटल पर पहचान कायम रखने में सफल हो...
सीतामढ़ी व शिवहर समेत समस्त
बिहारवासियों को नव वर्ष 2014 की
हार्दिक शुभकामनाएं....
नवल किशोर राय
केन्द्रीय अध्यक्ष,
जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र सह पूर्व सांसद, सीतामढ़ी , बिहार

तिरहुत स्नातक क्षेत्र समेत
समस्त बिहारवासियों
को नव वर्ष
2014
की
हार्दिक
शुभकामनाएं...
राम कुमार सिंह
पूर्व विधान पार्षद सह प्रत्याशी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, बिहार

नववर्ष 2014 एवं गणतंत्र दिवस की जिले की
की समस्त जनता को
हार्दिक शुभकामनाएं
चन्द्रशेखर सिंह बब्बन
भाजपा जिलाध्यक्ष, अररिया

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

13 जनवरी –19 जनवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

हाथी के पांव डगमगा रहे हैं

बसपा नेत्री मायावती ने किसी दूसरे दलित नेता को उभरने का कभी कोई मौका नहीं दिया. बुद्धिजीवियों का कहना है कि दलितों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो किया गया, मगर सत्ता में उन्हें कभी सम्मानजनक भागीदारी हासिल नहीं हुई. मायावती आज जिस राजनीतिक रास्ते पर चल रही हैं, उसमें उन्होंने उन विचारों से ही पल्ला झाड़ लिया है, जिनके तहत डॉ. भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जैसे नेताओं ने दलितों के राजनीतिक भविष्य का सपना देखा था. ऐसे में हाथी कमजोर पड़ गया है और उसके पांव डगमगाने लगे हैं.

दर्शन शर्मा

दलितों के उत्थान का सपना देखने वाले कांशीराम ने जिस पौधे को लगाया था, उसे फलदार बनाने का काम मायावती ने अच्छे ढंग से किया. बसपा की बागडोर हाथ में लेकर दलित बेटी ने खूब नाम कमाया. शोहरत लूटी. दलित समाज को मुट्ठी में रखा. अच्छी पकड़ जमाई, जिससे वह एक बार नहीं, बल्कि चार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुईं. मायावती की पूजा देवी की तरह दलित वर्ग करने लगा. तीन बार के अल्प काल की मुख्यमंत्री रहने वाली बसपा नेत्री ने चौथी बार नील गगन के नीचे अपना नीला झंडा तब फहराया, जब सपा जैसी मजबूत पाये वाली पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग का नायाब फॉर्मूला अपनाकर प्रदेश की सत्ता बहुमत के साथ हथिया ली थी, यानी बसपा ने एक बड़ी लाइन के आगे इससे बड़ी लकीर खींच कर विरोधी पार्टी सपा का कद छोटा कर दिया था. पहले डीएसफोर फिर बहुजन समाज पार्टी बनी दलितों की इस पार्टी को माया ने सींच कर पुष्पित-पल्लवित किया. देखते-देखते बसपा ने एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया. इसकी गूंज देश के दूसरे राज्यों तक सुनाई दी थी. पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक आदि राज्यों में इसके कार्यकर्ता पनपने लगे. बड़े-बड़े राजनीतिक दिग्गज माया के आगे नतमस्तक होने लगे. नौकरशाही पर इतनी मजबूत पकड़ कि वह जिस ओर मोड़ती थी, मुड़ने को मजबूर थे. नौकरशाहों की लॉबियां खत्म हो गईं. इनका संगठन मुख्यमंत्री की एक बैठक के लिए तरस गया. किसी में हिम्मत नहीं थी, कुछ अलग करने की. रूतबा इतना कि नौकरशाह उनकी चप्पलें उठाने में भी तौहीनी नहीं समझते थे. मिजाज इतने निराले रहे कि एक अदद सैंडिल के लिए जहाज उड़ते थे. इसी चकाचौंध में खोई माया की राजनीतिक संपदा तब नेस्तनाबूद होने लगी, जब उनके चौथी बार के शासन में भीषण भ्रष्टाचार ने जन्म ले लिया. चाटुकार मंत्रियों-संत्रियों से घिरीं माया यह समझ न सकीं कि एसी में बैठे-बैठे जारी किए जा रहे उनके फरमान कितने कारगर हो रहे हैं. ऊपर से देखने में सब कुछ ठीक-ठाक लगता था, लेकिन अंदर कुछ और ही था. हां में हां मिलाने वाली नौकरशाही और कुछ मंत्री मिलकर खजाने में सेंध लगा रहे थे. मीडिया को इसकी कानों-कान खबर नहीं रहती थी. कई नौकरशाह और मंत्री बात लीक होने के डर से मीडिया से दूर भागते थे. मीडिया को अंदर पैठ बनाने में मशक्कत करनी पड़ती थी. कुछ गिने-चुने पत्रकारों को ही बहिन जी से मिलने की इजाजत होती थी. कई बार पार्टी के विधायक ही मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते थे, जिसके चलते आम आदमी पार्टी से लगातार कटता जा रहा था. किसी के दुख-दर्द से किसी को कोई वास्ता ही नहीं रह गया था. मुट्ठी भर लोग ही फायदा पा रहे थे. सबसे बड़ी बात बसपा की यह रही कि जिस पार्टी में एक समय मात्र दलित नेताओं का ही दखल रहता था, उसमें

बसपा की निगाहें मुसलमानों पर टिकी हैं. मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर बसपा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कई बार कठघरे में खड़ा किया है. बसपा संगठन की कोशिशें जारी हैं. बूथ दर बूथ कील-कांटे ठोंके जा रहे हैं. समीक्षा हो रही है. बैठकों के जरिये हर खतरे को दूर किया जा रहा है. ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, मुस्लिम, कुर्मी, मौर्य, चौहान, राजभर व प्रजापति जैसी जातियों को जोड़ने के लिए बड़े नेता पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं.

सोशल इंजीनियरिंग के जरिये प्रचंड बहुमत से जीती बसपा सरकार का मिजाज बदल सा गया था. दलितों की जगह दूसरे वर्गों का दबदबा पार्टी में ज्यादा बढ़ गया था.

गौर करने की बात यह थी कि कांशीराम का जन्मदिन हो या पुण्यतिथि, अंबेडकर जयंती हो अथवा मायावती का जन्मदिन, इन दिवसों पर बसपा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखते ही बनता था. मधुमक्खी के छत्ते की तरह मायावती द्वारा बनाए पार्कों, प्रदेश की दूसरी पार्टियों को भयाक्रांत करने लगा था. उन्हें शायद यह अहसास होने लगा था कि बसपा के इतने विशाल किले को वह ढहा नहीं पाएंगे. वे बसपा को प्रदेश से कभी हटा नहीं पाएंगे. पार्टी के नेताओं के बीच साम्राज्ञी जैसा ठाठ-बाट रखने वाली मायावती भी जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चौथी बार पूरे बहुमत के साथ विराजमान हुईं, वहीं उनके जन्मदिन पर सोने-जवाहरात के बने आभूषण पेश किए जाते थे, जो बदस्तूर जारी रहा. उन्हें इसके लिए आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई के फंदे से भी गुजरना पड़ा. माया के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर एक बात खास यह देखी गई कि पहले दो वर्ष यानी 2007 से 2009 तक मायावती शासन में मंत्री से संत्री तक मीडिया से बहुत दूरी बनाए रखे. इसके पीछे का कारण तब समझ में आया, जब अंदरखाने सुर्खियों में या राजनीतिक चर्चाओं में उभरकर आया कि महापुरुषों के नाम पर बन रहे पार्कों में सरकारी धन, जिसे विकास के कामों में लगाया जाना चाहिए था, वह पत्थरों के बने हाथियों पर लगाया जा रहा है. विदेशी पौधों को लगाने पर खर्च किया जा रहा था. कई निगमों, विभागों का सरकारी अमला भी इसमें पूरी सिद्दत से काम कर रहा था. कई ऐसे मद थे, जिसमें से बसपा सरकार पैसा निकालकर दूसरे मद में खर्च कर रही थी, लेकिन सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है. बसपाई मंत्रियों द्वारा की जा रही लूट-खसोट को अखबारों ने सुर्खियों में रखा. मीडिया ने भी समझ लिया कि बसपा के अंदर सब ठीक नहीं है. उसने एक के बाद एक कारनामे उजागर करने में देर नहीं लगाई. कई मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में भ्रष्टाचार कर सरकारी खजाना अपनी जेबों में भर लिया. अनाप-शनाप ठेके उठाए गए. अपनों को रेवड़ी की तरह पैसे वाले काम दिए जाने लगे. अफसरों ने भी मंत्रियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धोए थे. यह सब कुछ बसपा नेत्री की नजरों के आगे हो रहा था, जिसे वह अनदेखा कर रही थी. कई शिकायतें लोकायुक्त के पास आईं. कई मंत्री जवाब-तलब के लिए बुलाए गए. जांच शुरू हुई. वे फंसे भी. कोर्ट ने भी दखल दिया. 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त मायावती की तंद्रा तब टूटी, तब तक प्रदेश लुट चुका था. मायावती ने ऑपरेशन क्लीन के तहत चुनाव के ऐन वक्त अपने करीब सौ विधायकों के टिकट काट दिए, लेकिन प्रदेश की जनता में बसपा के विपरीत चली भ्रष्टाचार की हवा ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बसपा के हाथ से सत्ता तो आखिर चली ही गई. बसपा के शासनकाल में मंत्री रहे कई विधायक आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं.

लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा नेत्री के 58वें जन्मदिन की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. पार्टी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर राष्ट्रीय सावधान विशाल महारैली बुलाई है. हर विधानसभा क्षेत्र से पांच हजार लोगों को लाने का निश्चय किया गया है. प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर पर दिल्ली राज्य का प्रभार तो है ही, साथ ही उन्हें आगरा, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, कानपुर, चित्रकूट, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली मंडल में बैठकों के जरिये भीड़ जुटाने का भार सौंपा गया है. लोकसभा चुनाव के कारण बसपा तैयारी के लिए दम-खम दिखा रही है. वह अपनी भूल का स्वाद चख चुकी है. 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें जुटाने वाली बसपा को 2012 के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली और चार राज्यों के चुनाव में इसके विधायकों की संख्या घटकर आधी रह गई है. इससे बसपा के माथे पर बल पड़ना लाजिमी है. दिल्ली में इस पार्टी के पूरी तरह से साफ हो जाने से जाहिर हो रहा है कि दलित वोटर बसपा का साथ छोड़ रहा है. अगड़ी जातियों का इससे मोहभंग इसलिए हो रहा है, क्योंकि पिछले

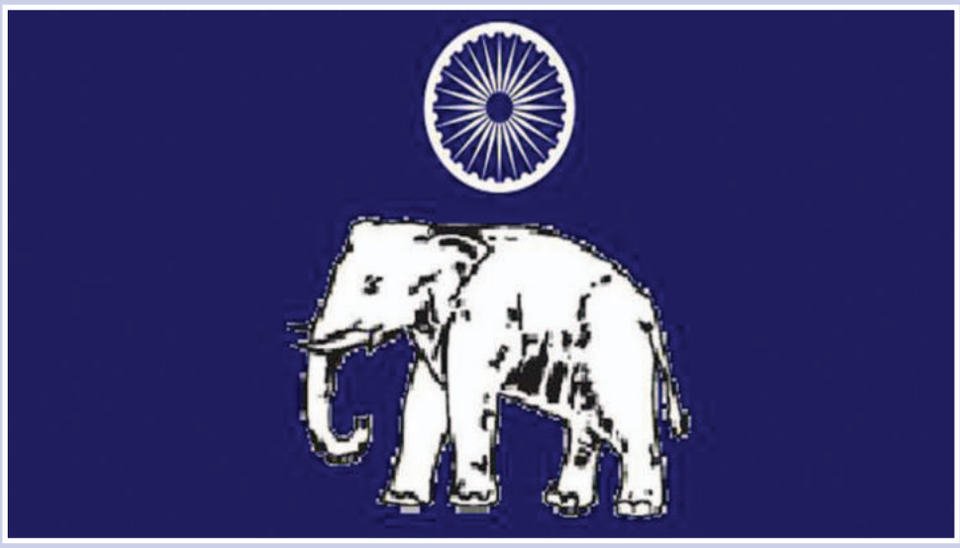

कुछ महीनों से नरेंद्र मोदी का जादू प्रदेश के युवा मतदाताओं पर चढ़ा है. रैली में भीड़ को देखते हुए अंदाजा लगाया जाने लगा है कि निश्चित ही यह भीड़ आने वाले चुनावों में हर किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि मोदी के प्रति नौजवान चाहे वे दलित हों या गैरदलित अथवा अल्पसंख्यक, सभी में इस बात को लेकर उत्सुकता जगी है कि आने वाले समय में भाजपा ही उनके लिए कुछ कर सकती है. अब जातीय राजनीति के दिन लदने वाले हैं. अब जो विकास की राजनीति करेगा, मतदाता उसी के साथ जाएगा.

अब बसपा की निगाहें ज्यादातर मुसलमानों पर टिकी हैं. मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर बसपा ने कांग्रेस और सपा को कई बार कठघरे में खड़ा किया है. बसपा संगठन की कोशिशें जारी हैं. बूथ दर बूथ कील-कांटे कसे जा रहे हैं. समीक्षा हो रही है. बैठकों के जरिये हर खतरे को दूर किया जा रहा है. ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, मुस्लिम, कुर्मी, मौर्य, चौहान, राजभर व प्रजापति जैसी जातियों को जोड़ने के लिए बड़े नेता पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं. कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा सरकार से जनता की नाराजगी को भुनाने के लिए पार्टी आए दिन राज्यपाल से राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग करती रही है. भाजपा नरेंद्र मोदी पर भी तीर चलाती रहती है. मायावती मिशन 2014 के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की खोज कर रही है. हार की जरा भी शंका होने पर मौजूदा सांसदों तक के टिकट काटने में बसपा परहेज नहीं कर रही है. राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है. मायावती अपने जन्मदिन पर ऐतिहासिक महारैली में यूपीए सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान भी कर सकती हैं. माया से दलितों का वोट बैंक छीनने के लिए कांग्रेस भी उपाय ढूंढती रहती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों दलित आंदोलन की बात उठाई थी. उनका कहना था कि दलितों के उत्थान के लिए एक या दो दलित नेता पर्याप्त नहीं होते. इस वर्ग से अधिकाधिक नेतृत्व को उभारने और उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने मायावती की तरफ इशारा किया था. राजनीति के जानकारों का भी यही कहना है. मायावती अपने व्यवहार से पूरी तरह एक वर्चस्ववादी नेता हैं, लेकिन व्यापक दलित नेतृत्व की उन्होंने कभी कोई परवाह नहीं की. उन्होंने किसी दूसरे दलित नेता को उभरने का मौका ही नहीं दिया. दूसरी ओर बुद्धिजीवियों का तर्क है कि दलितों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो किया गया, मगर सत्ता में कभी सम्मानजनक भागीदारी हासिल नहीं हुई. उनका मानना है कि तमाम क्षमताओं से भरपूर होने के बावजूद दलित नेताओं को उनके हक से दूर रहना पड़ा. वे कहीं न कहीं आर्थिक मजबूरियों और राजनीतिक दलों के सामंती चरित्र का शिकार होकर पीछे ही रह जाते है. बड़े दलित नेता अपने विकास में ही लग जाते हैं. मायावती आज जिस राजनीतिक रास्ते पर चल रही हैं, इसमें उन्होंने उन विचारों से ही पल्ला झाड़ लिया है, जिनके तहत डॉ. भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जैसे नेताओं ने दलितों के राजनीतिक भविष्य का सपना देखा था. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

आज भी चुनावों में राजघरानों का दबदबा है

शिवनाथ चतुर्वेदी

चुनाव कोई भी हो या पार्टी कोई भी हो, उत्तर प्रदेश राजघरानों का दबदबा अब भी कायम है. राजशाही भले अब नहीं रही, लेकिन पूर्व राजपरिवार के लोगों ने लोकतंत्र के पर्व को बखूबी सत्ता में भागीदारी का जरिया बनाया है. इन्हें दलीय निष्ठा से कोई लेना-देना नहीं. जीतना इनकी शर्त और राज करना इनका शगल. आगामी आम चुनाव के लिए वॉर्म-अप माने जा रहे राजे-रजवाड़ों की सक्रियता चारों तरफ देखी जा रही है. लोकशाही की आंगन में भला राजे-रजवाड़ों का क्या काम है, यह सवाल भले ही लोकतंत्र में आस्था रखने वालों को कुरेदता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की पाठशाला में मास्टरों की कुर्सी पर सामन्तों का ही बोलबाला है. राजपरिवारों ने विरासत में मिले राज करने के गुणों की गोटियों का जाल लोकतंत्र की चौकस पर इस कदर बिछाया है कि उनके सामने सब बौने हैं. माना जाता है कि ये भले ही किसी दल में रहे हों, लेकिन लोकशाही में सामंती रसूख किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. प्रदेश की राजनीति पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में करीब दो दर्जन ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जिनका किसी न किसी राज परिवार से सीधा सम्बन्ध रहा. इलाहाबाद के करछना क्षेत्र के बराव राजघराने के वारिस उज्ज्वल रमण सिंह सपा में हैं. यह सीट उज्ज्वल को अपने पिता व सपा सांसद कुंवर रेवतीरमण सिंह से राजनीतिक विरासत में मिली थी. सियासत से अपने रिश्तों के लिए मशहूर प्रतापगढ़ के राजघराने में शुमार भदरी घराने के रघुराजप्रताप सिंह जिले की कुंडा सीट से जीतते आ रहे हैं. महाराजगंज की सिसवा रियासत के शिवेन्द्र सिंह ने सियासी सफलता के लिए समय-समय पर नये दोस्त चुने. केन्द्र में मंत्री आरपीएन सिंह गोरखपुर के पास तुमकुही राज रियासत के वारिस हैं. करनैलगंज क्षेत्र के बरगदीकोर्ट राज घराने के कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया ने 1989 में करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय की हैसियत से चुनाव जीता. 1991, 1993 और 1996 में वे भाजपा के विधायक बने. 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नाव पर बैठे और बाद में इस्तीफा देकर बसपा से नाता जोड़ लिया. रायबरेली के तिलोई राज घराने के उत्तराधिकारी मंयक केश्वर शरण सिंह 1993 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में तिलोई विधानसभा से निर्वाचित हुए थे. वे 2002 में भाजपा और 2007 में सपा से जीते थे. गोंडा के मनकापुर राजघराने का सियासत से शुरू से ही चोली-दामन का साथ रहा. राजघराने के कुंवर राघवेन्द्र प्रताप सिंह 1951 में कांग्रेस के टिकट पर मनकापुर से विधायक निर्वाचित हुए उनके पुत्र आनन्द सिंह कांग्रेस के सांसद और विधायक रहे. 1998 और 2004 में उनके पुत्र कीर्तिवर्धन सिंह सपा से जीते. वख्शी का तालाब (लखनऊ) सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता सिंह भी रजवाड़े से ताल्लुक रखती हैं. सुनीता पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की भतीजी हैं. लखीमपुर की धाहरौरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चिन्पू भैया का भी राज परिवार से नाता रहा है. इनके पिता सरस्वती प्रताप इलाके से कई बार विधायक और राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे हैं.

आवाम पर हुकूमत के आदि और रियासतों को संसदीय लोकतंत्र में जन बल का एहसास हुआ तो दूसरी ओर दागी और बाहुबली नेताओ ने लोकतंत्र के पर्व को बखूबी सत्ता में भागीदारी का जरिया बनाया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य में बाहुबली और दागी नेताओं को रोकना आसान नहीं लगता. वे न सिर्फ देश की संसद में प्रवेश की तैयारी में जुटे हुए हैं, बल्कि राजनीतिक दल भी इनके स्वागत में पलक-पावड़े बिछाए हुए हैं.

मौजूदा समय में राजनीतिक दल पहले की तरह ही बाहुबली हिस्ट्रीशीटरों को देश की संसद में भेजने पर आमादा हैं. ऐसे में राजनीति को साफ-सुथरा रखने की मंशा का पूरा होना सम्भव नहीं दिखता. सपा में पवन पांडेय, कपिलमुनि करवरिया, जितेन्द्र सिंह, बब्लू और कादीर राजा का अतित दागदार रहा है. इसके बावजूद बसपा ने पवन पांडेय को सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है. पवन पांडेय पर आधा दर्जन आरोप हत्या के हैं. अन्य की सक्रियता खासी चर्चा में है.

सपा का भी यही हाल है. इनके उम्मीदवारों की सूची में कई दागदार चेहरे हैं, जिसमें मित्रसेन यादव, बालेश्वर, अरुणशंकर शुक्ल उर्फ अन्ना महराज, अतीक अहमद, अखिलेश प्रताप सिंह और बालकुमार पटेल के नाम प्रमुख हैं. समाजवादी पार्टी ने अन्ना महाराज को उन्नाव से अपना उम्मीदवार बनाया है तो मित्रसेन यादव को फैजाबाद से. वहीं अखिलेश प्रताप सिंह को महराजगंज की कमान सौंपी गई है. अतीक अहमद को सुल्तानपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है. कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इनके कुनबे में भी दागियों की कमी नहीं है. हार्डकोर क्रिमिनलों में गिने जाने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, बृजेश सिंह आदि चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. ■

गोंडा के मनकापुर राजघराने का सियासत से चोली-दामन का साथ रहा. राजघराने के कुंवर राघवेन्द्र प्रताप सिंह 1951 में कांग्रेस के टिकट पर मनकापुर से विधायक निर्वाचित हुए उनके पुत्र आनन्द सिंह कांग्रेस के सांसद और विधायक रहे. 1998 और 2004 में उनके पुत्र कीर्तिवर्धन सिंह सपा से जीते. वख्शी का तालाब (लखनऊ) सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता सिंह भी रजवाड़े से ताल्लुक रखती हैं. सुनीता पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की भतीजी हैं.

मुलायम के पैंतरे से विरोधी चित

संजय सक्सेना

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं. राजनीति की नब्ज पहचानने में उन्हें महारथ हासिल है. राजनीति किस करवट बैठेगी या फिर बैठने वाली है, इसके बारे में उनसे बेहतर कम ही राजनीतिज्ञ समझ पाते हैं. वह राजनीतिक नब्ज टटोल लेते हैं तो अवाम का मिजाज भी जानते हैं. भले ही उनकी राजनीति को समय रहते कोई न समझ पाए, लेकिन उनकी दूरदर्शिता को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता है. अगर ऐसा न होता तो वह मुजफ्फरगनर और शामली आदि जगहों में राहत कैम्पों में रह रहे लोगों के लिए इतनी सख्त टिप्पणी नहीं करते, जो उनके मजबूत वोट बैंक भी हैं. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मुलायम को आहट मिल गई थी कि राहत कैम्प उनकी भविष्य की राजनीति में रोड़ा बन सकते हैं. राहत कैम्पों में जितने दंगा पीड़ित रह रहे हैं, उसका दस गुना लोग ऐसे हैं, जिनकी सोच दंगा पीड़ितों के नाम पर आ रही मदद में लूट-खसोट करना है. कई अन्य राज्यों से भी मदद की आस में लोग आकर यहां बस गए हैं. यह वे लोग हैं, जो कभी यहां के वाशिंदे हुआ करते थे, लेकिन अब उनका यहां से दूर-दूर का वास्ता नहीं है. कुछ भू-माफिया टाइप लोगों की नजर इस जमीन पर भी है, जहां राहत कैम्प लगे हुए हैं. यह बेशकीमती जमीन है. ऐसे लोगों को सपा विरोधियों और धर्म के कुछ ठेकेदारों की शह मिली हुई है. यहां शाम होते ही कुछ लोग राहत कैम्प में रहने वालों को नोट बांटने पहुंच जाते हैं. वह भी दस-बीस नहीं, पांच-पांच सौ रुपये. राहत के नाम पर अरब के मुल्कों तक से पैसा आने लगा था. इस बात को स्थानीय प्रशासन भी स्वीकार करता दिखा. हद तो तब हो गई, जब चारा घोटाले में जेल की हवा खा चुके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी राहत शिविरों में विस्थापितों को पैसा बांटने पहुंच गए. कांग्रेस, भाजपा और रालोद तो पहले ही राहत कैम्पों के नाम पर राजनीति कर रहा था. मुजफ्फनगर के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा तो साफ-साफ शिविर खत्म नहीं होने के पीछे राजनीतिक मकसद बताते हैं. उनका कहना है कि इंसाफ दिलाने का वास्ता देकर दंगा पीड़ितों को यहीं जमे रहने को कहा जाता है. उधर, सपा भी यह बात समझ रही थी कि राहत कैम्प इसके लिए अब नुकसान का सौदा बनते जा रहे हैं.

बहरहाल, बात मुलायम के इस बयान कि की जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहत कैम्पों में दंगा पीड़ित नहीं, कांग्रेस और भाजपा के लोग रह रहे हैं तो यह साफ हो जाता है कि मुलायम ने दूर की कौड़ी चली थी. हालांकि मुलायम के बयान का जबर्दस्त विरोध हुआ. कांग्रेस-बसपा और भाजपा ही नहीं, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं तक ने मुलायम से माफी मांगने की बात कही, लेकिन मुलायम टस से मस नहीं हुए. पार्टी के बाहर ही नहीं, भीतर भी समाजवादी सरकार और संगठन दोनों को ही पहले पहल जरूर लगा था कि नेताजी से कुछ चूक हो गई, लेकिन यह दौर लम्बा नहीं चला. इसी के बाद समाजवादी सरकार का रवैया राहत कैम्पों में रहने वालों के प्रति सख्त हो गया. कैम्पों से लोगों को खदेड़ने के लिए अखिलेश सरकार ने तंबू हटाओ अभियान चला दिया. काफी हाय तौबा हुई, लेकिन यह सिलसिला थमा नहीं. सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों से यह भी साफ हो गया कि अब राहत कैम्पों के नाम पर आगे सपा सरकार को घेरने का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा.

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बयान और राहत कैम्पों से लोगों का तंबू उखाड़े जाने के दौरान अखिलेश सरकार के कारागार मंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी पार्टी और सरकार का रुख रखने के लिए सामने आए. उन्होंने दो टूक घोषणा कर दी कि मुजफ्फरनगर और शामली में बने राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों को सरकार ने हरसंभव मदद की. अब सरकार चाहती है कि ठंड के इस मौसम में पीड़ितों के लिए पक्के मकानों में वैकल्पिक व्यवस्था हो. जो लोग घर वापस जाना चाहते हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा दिए जाने का भी भरोसा दिया गया है. इन पीड़ितों को आर्थिक तथा अन्य मदद भी दी गई है. राज्य सरकार ने पीड़ितों को सुविधा और सम्मान दोनों मिले, इसका पूरा ख्याल रखा है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी मानव त्रासदी में भी अपनी राजनीति की रोटी सेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं. यही लोग पीड़ितों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं. चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि इसी से दु:खी होकर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पीड़ितों के प्रति संवेदना जताने के बजाय भाजपा-कांग्रेस शिविरों में राजनीति करने की साजिश में जुटे हुए हैं. उनके बयान को संदर्भ से अलग तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. कुछ लोग अब भी भ्रम फैलाने पर लगे हैं और मुलायम सिंह यादव के बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा अपनी जमीन खो चुके हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रति जनता का बढ़ता विश्वास और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लोकप्रियता से उन्हें डर है. वहीं सपा प्रमुख मुलायम के राहत शिविर खाली कराने के पैंतरे से सपा विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं, जबकि सपा का मानना है कि इससे थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन समय-समय पर मुसलमानों को मरहम लगा कर इसे पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों में भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो यह मान कर चल रहे थे कि राहत कैम्पों की हकीकत वैसी नहीं है, जैसी तस्वीर सपा विरोधी पेश कर रहे हैं. सपा सरकार ने राहत कैम्पों में रहने वालों की ठीक-ठाक मदद की है. ■

मुलायम को मोदी बताकर मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की सत्ता गवांने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2013 में कोई खास धमाका नहीं किया. उनकी तरफ से विरोधियों पर हल्के-फुल्के हमले जरूर किए गए, लेकिन यह औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं था. माया चुप थीं तो उनके सिपहसलारों ने भी अपवाद को छोड़कर अधिकांश मौकों पर मुंह बंद ही रखा. यह सिलसिला नवंबर में हुए चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय भी जारी रहा, जिसका पार्टी को नुकसान भी हुआ. माया की चुप्पी का राजनीतिक पंडितों ने समय-समय पर खूब पोस्टमॉर्टम किया. किसी ने कहा बहन जी यूपी की गद्दी जाने के सदमे से उबर नहीं पा रही हैं तो कोई बोला नरेन्द्र मोदी के उभार से बसपा का दलित छोड़कर अन्य वोट बैंक भाजपा की तरफ खिसक गया है. ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जिनको लग रहा था कि माया के राजनीतिक करियर में विराम लग गया है. यूपी तो उनसे छिन ही गया था, दिल्ली में भी बसपा के मुकाबले समाजवादी नेता पूरे साल ज्यादा चमक फैलाते रहे. इस दौरान बसपा ने अगर कुछ खास किया तो बस इतना कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों (लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना कर) के नामों की घोषणा कर दी. यह और बात है कि बदले राजनीतिक माहौल के बीच उन्हें अपने कई प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं.

बहरहाल, 2013 में बसपा ने भले ही कोई बड़ा राजनीतिक धमाका नहीं किया हो, लेकिन 2104 का आगाज मायावती धमाकेदार तरीके से करने जा रही है. इसके लिए उन्होंने 15 जनवरी का दिन तय किया है. 15 जनवरी यानी माया का जन्मदिन. इस दिन मायावती लखनऊ में 'सावधान विशाल महारैली' करने जा रही हैं. इसमें पूरे देश से बसपाई आएंगे. रैली मैदान पुराना वाला (रमाबाई अम्बेडकर मैदान) ही रहेगा, जहां रैली करने का साहस माया के अलावा कोई नहीं कर पता है. रैली को सफल बनाने के लिए मायावती पिछले कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं. रैली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच हजार और लोकसभा क्षेत्र से 25 हजार की भीड़ लाने को बसपा नेत-ाओं से कहा गया है. भीड़ को ढोने के लिए बसों और छोटे-छोटे वाहनों के अलावा करीब डेढ़ दर्जन रेलगाड़ियां भी बुक कराई गई हैं. बसपा से टिकट की चाह रखने वालों और जिन्हें टिकट मिल गया है, उन्हें अपना टिकट बचाए रखने के लिए हर हालत में भीड़ जुटा कर मायावती को प्रभावित करना होगा. वामसेफ के कार्यकर्ता इस बात पर नजर रखेंगे कि कौन नेता कितनी भीड़ लेकर आया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए आगाह किया गया है. भीड़ में भी मुस्लिमों की तादात अच्छी रहे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. कोशिश यह की जा रही है कि मायावती की रैली पिछले दिनों हुई भाजपा और सपा की रैलियों से हर मायने में बेजोड़ साबित हो. भीड़ का आंकड़ा मोदी-मुलायम की रैली से दोगुना रखने की कोशिश की जा रही है.

एक तरफ बसपा के रणनीतिकार भीड़ जुटाने का रिकॉर्ड बनाने को बेताब हैं तो दूसरी तरफ भाजपा, कांग्रेस और सपा नेताओं के खिलाफ बसपा सुप्रीमो इन मुद्दों को धार देंगी, जो लोकसभा चुनाव के समय विरोधियों को घेरने के काम आएंगे. प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था के अलावा बसपा की कोशिश इन मुस्लिमों को अपने पाले में फिर से खींचने की है, जो 2012 के विधानसभा चुनाव में इससे छिटक कर सपा के पास चले गए थे. इसके लिए बसपा मुजफ्फरनगर दंगों की सियासत को आगे बढ़ाएगी. वह चाहेंगी कि किसी भी तरह से मुलायम एंड कम्पनी को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाए. इसीलिए दंगों के समय समाजवादी सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया जाएगा. दंगा शिविरों में रह रहे लोगों को बुलडोजर चलाकर हटाए जाने और उनके खिलाफ (दंगा पीड़ितों) मुलायम के बेतुके बयान को बसपा नेत्री अपने श्रीमुख से हवा देंगी. इसके अलावा माया ने अपने नेताओं से कह रखा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहां भी समाजवादी सरकार दिक्कतें और भय का माहौल बना रही है, वहां ऐसे मुद्दों को गंभीरता से उठाया जाए. बसपा सुप्रीमो की कोशिश है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने मुलायम को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के समानान्तर खड़ा कर दिया जाए. अपनी बात सिद्ध करने के लिए मायावती पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के नक्शेकदम पर चलने का आरोप भी लगा चुकी हैं. उन्होंने यह कहकर सपा को कटघरे में खड़ा किया था कि कड़ाके की ठंड में राहत कैम्पों में बुलडोजर चलाकर उनके जख्मों पर वैसे ही नमक छिड़कने का काम सपा सरकार ने किया, जैसा कि भाजपा की गुजरात सरकार मुसलमानों के साथ करती आई है. बसपा नेत्री लगातार इस कोशिश में हैं कि जनता में सपा की इमेज भाजपा के साथ एक सिक्के के दो पहलू जैसी बना दी जाए. यह ऐसा मुद्दा है, जिसके सहारे बसपा अपने सभी विरोधियों कांग्रेस, सपा, भाजपा और रालोद को एक साथ घेर सकती है. हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यह काम इतना आसान नहीं है. माया जब अल्पसख्यकों पर अत्याचार की सियासत को हवा देंगी तो उनके सामने भी यह सवाल खड़ा होगा कि उनकी सरकार ने भी तो मुसलमानों की नहीं सुनी थी. आज भी उनका यही नजरिया है. इसीलिए तो वह दंगा पीड़ितों का दुख-दर्द बांटने मुजफ्फरनगर नहीं गईं. हो सकता है इसकी सफाई वह सावधान रैली में दें. अन्य तमाम दलों के अलावा उनकी तेजी से उभर रही आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोच है, इसका जवाब भी जनता उनसे सुनना चाहेगी. उत्तर प्रदेश में पिछले करीब दो दशकों से बसपा ही ऐसा दल है, जो समाजवादी पार्टी को चुनौती देता रहा है. इसीलिए माया की सावधान रैली पर अन्य दलों के नेताओं के अलावा सपा नेताओं की सबसे अधिक नजरें जमी हुई हैं. सपा अभी से रैली की हवा निकालने की तैयारी में भी जुट गई है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विरोधी दल राहत शिविरों में राजनीति कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे (मायावती) फिर पहले की तरह अपने सांसदों, विधायकों और नेताओं से जन्मदिन की चंदा वसूली में लग गई हैं, जिसमें कइयों की जानें जा चुकी हैं. बसपा सपा-भाजपा को 'एक ही थाली का बैगन' बताने में जुटी है तो सपा नेता ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों के लिए दिखावटी हमदर्दी दिखाकर भाजपा की बी टीम का फर्ज निभाने जा रही है. ■

यूपी में छठवां कोण बनने को बेताब आप

अजय कुमार

चमत्कार की तरह दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी(आप) की नजर स्वाभाविक रूप से इस वर्ष होने वाले आम चुनाव में लग गई है. इसके नेता देश को फिर से 'सोने की चिड़िया' बनाने का दम भर रहे हैं. यह अभियान कहां से शुरू किया जाए, इसे लेकर पार्टी में किसी तरह का संशय और मतभेद नहीं है. यूपी में आप विपक्ष के खिलाफ सबसे मजबूत किलाबंदी करने जा रहा है. 'आप' के धुरंधरों को भी अन्य दलों के नेताओं की तरह इस बात का एहसास अच्छी तरह से है कि केन्द्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है. समाजसेवी अन्ना हजारे से दूर होकर यूपी में ताल ठोंकने जा रहे आप नेताओं को जनता किस तरह गले लगाती है, यह तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 'आप' में उत्साह का माहौल तो है ही. इस उत्साह को कैश कराने के लिए ही 'आप' मचल रही है. यही वजह थी कि जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाने के लिए 'हुंकार' भर रहे थे तो ठीक इसी समय दिल्ली के जश्न से दूर यूपी में 'आप' के विश्वासपात्र संजय सिंह अपनी

पार्टी के कुछ दिग्गजों के साथ लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए माथापच्ची कर रहे थे, जिसकी सुगबुगाहट सुनाई भी दे रही थी. उत्तर प्रदेश में 'आप' करीब-करीब सभी सीटों पर गंभीरता के साथ चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है. दिल्ली में भले ही कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने सरकार बनाई हो, लेकिन यूपी में वह इसके एवज में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई छूट देने को तैयार नहीं है, बल्कि इसका पूरा जोर इन दोनों दिग्गजों को घेरने में लगा हुआ है. अमेठी में राहुल गांधी को घेरने के लिए 'आप' ने कुमार विश्वास को आगे कर दिया है, वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी को 'आप' के कद्दावर नेता संजय सिंह चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं. विश्वास और संजय सिंह मौजूदा सांसद सोनिया गांधी और राहुल के संसदीय क्षेत्र का 'पारा' नाप आए हैं. 'आप' ने राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में 'झाड़ू संदेश यात्रा' निकालकर दस्तक दे दी है. लखीमपुर खीरी से 'आप' इलियास आजमी को मैदान में उतार सकती है. यह सीट भी फिलहाल कांग्रेस के ही पास है.

खैर, 'आप' ने पहले झटके में सोनिया और राहुल गांधी को घेरने की योजना बना कर कांग्रेसियों की नींद उड़ा दी है तो अन्य दलों के सुरमाओं को भी 'आप' का भय सताने लगा है कि वह इसके खिलाफ कौन सा 'विस्फोट' करेगा. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले सांसद मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, लाल जी टंडन, सोनिया, राहुल के अलावा कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेताओं केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, सलमान खुर्शीद, आरबीएन सिंह, सांसद जफर अली नकवी, राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजित सिंह आदि की भी नींद उड़ी हुई है. इन नेताओं को चिंता है कि चुनावी मुकाबले में 'आप' का कोई 'प्यादा' 'वजीर' न बन जाए. दिल्ली की राजनीति में तेजी से उभरी 'आप' पार्टी पूरे देश का सपना देख रही है. विभिन्न दलों के दिग्गज नेता इसके रडार पर हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा, सपा-बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के अन्य कम चर्चित सांसदों की भी नींद उड़ी हुई है. इन्हें इस बात का अहसास अच्छी तरह से है कि दिग्गज तो भले सीट बचा ले जाएं, लेकिन उनके लिए 'आप' की चुनौती मुश्किल हो सकती है. इसका कारण है कि कई संसदीय सीटों पर 'आप' के टिकट से पढ़े-लिखे, साफ-सुथरी छवि वाले ईमानदार प्रत्याशी चुनावी जंग में कूदना चाह रहे हैं. यह वे लोग हैं, जो अभी तक यह मान कर चलते थे कि राजनीति करना आम आदमी के वश की बात नहीं है. इसके लिए मसल और मनी पॉवर होना जरूरी है. सोची-समझी रणनीति के तहत तमाम दलों की बेचैनी को 'आप' पार्टी के नेता अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं. बात दिल्ली से हटकर उत्तर प्रदेश की कि की जाए तो आप के लिए यहां चुनौती दिल्ली के मुकाबले ज्यादा गंभीर है. यूपी की राजनीति पेचीदगी भरी है. इसको समझना आसान नहीं है. साम-दाम-दंड-भेद सहित यहां के नेता सभी तरह के फार्मूले अपनाते हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रमुख रूप से चार कोणों (भाजपा-कांग्रेस-सपा-बसपा) और कहीं-कहीं पांच कोणों (राष्ट्रीय लोकदल) में बंटी हुई है. 'आप' यहां छठा कोण बनना चाहता है.

बहरहाल, अच्छी खबर यह है कि 'आप' के थिंक टैंक ने अभी सिर्फ इतना ही खुलासा किया है कि इनकी पार्टी यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इतने में ही यूपी की राजनीति का रुख बदलने लगा है. आप की दस्तक का ही कमाल है कि भाजपा अपनी साम्प्रदायिक छवि से छुटकारे पाने, सपा गुंडा तत्वों पर लगाम लगाने, जातिवाद की राजनीति को छोड़ विकास के सहारे आगे बढ़ने की सोचने लगी है. इसी प्रकार कांग्रेस को अपना नाकारापन दूर करने की और बसपा को सर्व समाज की चिंता सताने लगी है. विभिन्न दलों के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का एहसास हो गया है कि 2014 के आम चुनाव का एजेंडा अब से 'आप' पार्टी ही तय करेगी. इस बार किसानों की दुर्दशा, राजनीति का अपराधीकरण, सरकारी भ्रष्टाचार, बिजली-सड़क-पानी, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, बेरोजगारी, शिक्षा का व्यावसायीकरण आदि जनता से जुड़ी समस्याएं अहम मुद्दे होंगे.

बात 'आप' की तैयारी कि की जाए तो यूपी में आप को पहचान दिलाने का कमान संजय सिंह के कंधों पर है. संजय सिंह यूपी के ही निवासी हैं. अन्ना के जनलोकपाल अंदोलन के समय भी इनके पास यूपी में आंदोलन सफल बनाने की जिम्मेदारी थी, जिसमें वह कामयाब रहे थे. संजय इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द राज्य के सभी जिलों में चुनाव समिति का गठन कर लिया जाए, जिसके ऊपर ही प्रत्याशी चयन से लेकर आम चुनाव की पूरी तैयारी का जिम्मा होगा. जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआती दिनों तक 'आप' अपने प्रत्याशियों का चयन कर लेना चाहती है. इसके अलावा पार्टी का जनाधार बढ़ाने, नये लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए सभी जिलों में अलग-अलग हेल्पलाइन भी बनाई जा रही है. यूपी के प्रभारी संजय सिंह कहते हैं कि फिलहाल अमेठी से कुमार विश्वास और लखीमपुर खीरी से इलियास आजमी को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला ले लिया गया है, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वह सोनिया गांधी को चुनौती देंगे, तो वह यह मसला आलाकमान पर छोड़ते हुए कहते हैं कि इस बारे में जैसा आदेश होगा, मैं वैसा ही करूंगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर

चेतावनी

विषाक्त मदिरा सदैव जानलेवा

जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है, जिसके सेवन से आंखों की रोशनी जा सकती है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है. यदि किसी व्यक्ति को अवैध मदिरा की बिक्री के अड्डों की सूचना प्राप्त होती है, तो तत्काल जनहित में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/ जिला आबकारी अधिकारी/ आबकारी निरीक्षक तथा पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ही कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दी गई सूचना ऐसे अड्डों पर तुरंत प्रशासनिक कार्यवाही में मददगार हो सकती है. सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जाएगा. जिला आबकारी अधिकारी एवं निरोधक क्षेत्र के आबकारी निरीक्षकों का मोबाइल नं0 नीचे अंकित है. इन मोबाइल नं. पर भी सीधे सूचना दी जा सकती है.

आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3 गोरखपुर, मो नं0-9454466211
आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2 गोरखपुर, मो नं0-9454466210
आबकारी निरीक्षक, सेक्टर-2 गोरखपुर, मो नं0-9454466209
आबकारी निरीक्षक, सेक्टर-1 गोरखपुर, मो नं0-9454466208
जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर, मो नं0-9454465624

जिला आबकारी अधिकारी
गोरखपुर

प्रमोशन परीक्षा से पीसीएस में नाराजगी

रवि प्रकाश

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अनिवार्यता का केंद्र सरकार का फैसला रास नहीं आ रहा है. इसे लेकर पीसीएस लॉबी में विरोध शुरू हो गया है. अपनी आवाज बुलंद करने के लिए गत दिनों उत्तर प्रदेश सिविल सेवा संघ के सदस्यों की कार्यकारी शाखा की कार्यकारिणी एवं सदस्यों की एक बैठक लखनऊ में संपन्न हुई, जिसमें न केवल पीसीएस से आईएएस में प्रोन्नति के लिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परीक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध किया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस प्रकरण में हस्तक्षेप किए जाने का अनुरोध भी किया गया.

पीसीएस लॉबी ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा कि यह दुख की बात है कि वर्तमान समय में लगभग 25 साल की सेवा अवधि के पीसीएस अधिकारी अभी तक आईएएस में प्रोन्नति नहीं पा सके हैं. संघ के अनुसार पीसीएस अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, के माध्यम से विभिन्न स्तरीय परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है. नई परीक्षा व्यवस्था से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली, चयन प्रक्रिया आदि पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा. आयोग द्वारा चयनित लोक सेवकों की प्रोन्नति के लिए पुन: परीक्षा लिया जाना न तो विधिक रूप से औचित्यपूर्ण है और न ही कार्मिक हितों के अनुकूल है. इसके साथ ही नई परीक्षा व्यवस्था लागू किए जाने से शासन द्वारा सौंपे गए विभिन्न दायित्वों एवं कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए जहां अधिकारी अवकाश पर जाना चाहेंगे, वहीं कार्यालय में भी मनोयोग से कार्य नहीं कर सकेंगे.

अपनी मांगों को जोर -शोर से उठाने के लिए सिविल सेवा संघ अपना वार्षिक अधिवेशन शीघ्र भी यथाशीघ्र करना चाहता है. इसके लिये वह मुख्यमंत्री से समय ले रहा है ताकि सीएम की मौजूदगी का फायदा मिल सके. पीसीएस सवंर्ग की नाराजगी यहीं तक सीमित नहीं है. इसे इस बात का भी दुख है कि वेतनमान 37400-8700-67000 रुपये (पुराना वेतनमान 14300-400-18300 रुपये) एवं 37400-8900-67000 रुपये (16000-450-20000 रुपये), जिसमें वर्तमान में काफी पद रिक्त हैं, इन पर अतिशीघ्र प्रोन्नति किए जाने के लिए सक्षम स्तर पर कार्यवाही नहीं हो रही है. संघ के अध्यक्ष चक्रपाणि, महासचिव आरके पांडेय एवं तमाम पदाधिकारी व सदस्य अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लंबी लड़ाई के मूड में भी दिखे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सभी जनपदवासियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रबन्धकों एवं शिक्षक बन्धुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

(सतीश सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।

जिला पंचायत, गोरखपुर प्रगति के पथ पर अग्रसर

भारत के 73 वें संविधान संशोधन के फलस्वरुप प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतें संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं. जिला पंचायतों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन जनमानस की मूलभूत सुविधाओं के दृष्टिगत जिला पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है. वर्तमान शासन के प्रभावी नेतृत्व/ नियंत्रण में जिला पंचायत, गोरखपुर शासन से प्राप्त अनुदानों एवं अपने निजी संसाधनों से जनपद के विकास हित के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़को, पुलियों, जलाशयों, नाली-नाले, पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य संपादित कराया जा रहा है. जनपद में प्रवाहित नदियों पर जिला पंचायत अपने सीमित संसाधनों से नवयुवकों/बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विकसित कस्बों में दुकानों/ गोदामों का निर्माण कराकर उन्हें व्यवसायिक रोजगारपरक सुअवसर उपलब्ध करा रही है. किसानों की फसलों की सुरक्षा के हेतु जिला पंचायत द्वारा पशु रोधालयों मवेशीखानों का संचालन प्रभावी ढ़ंग से किया जा रहा है. जनपद के समस्त व्यलसाईयों से अनुरोध किया जाता है कि जिला पंचायत के देयों का सम्यक भुगतान कर जनपद के विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

(आर.एस.यादव)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गोरखपुर.

(साधना सिंह)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, गोरखपुर